● वर्ष-3

● अंक-109

रायपुर, शुक्रवार
15 दिसंबर 2023

● पृष्ठ-8

● मूल्य-3 रु.

samacharpacheesa@gmail.com

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

# समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6›› ईमानदारी की जीत...

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहली कैबिनेट बैठक

## 25 को किसानों को दो साल का बकाया बोनस मिलेगा

### प्रधानमंत्री आवास योजना के 18 लाख मकान स्वीकृत

कांग्रेस सरकार ने राज्य को आर्थिक रूप से खोखला कर दिया

**रायपुर।** मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहली कैबिनेट की बैठक आज महानदी भवन में हुई । इस बैठक में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास को स्वीकृति प्रदान की गई। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेई के जन्म दिवस पर 2 साल का बकाया बोनस देने की का निर्णय लिया गया । कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मीडिया से चर्चा करते हुए यह जानकारी दी। उन्होने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने राज्य को आर्थिक रूप से खोखला कर दिया है। प्रदेश की आर्थिक स्थिति को लेकर पूछे गए प्रश्न पर सीएम ने कहा कि हमारी पार्टी में भी योग्य लोग हैं और अब डबल इंजन की सरकार हो गई है। मिलकर काम करेंगे बजट की कोई कमी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी ने यह आश्वासन दिया है कि दो वर्ष का बोनस 25 दिसंबर को देंगे। साय ने कहा कि मोदी की गारंटी में जो भी वादा किया है उसे हर हाल में पूरा किया जाएगा। साथ ही सीएम ने कहा कि आदिवासी समाज का मान और सम्मान भाजपा ने जितना बढ़ाया है, उतना किसी भी पार्टी ने नहीं बढ़ाया है। पहले आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में भूखमरी होती थी, लेकिन छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बनी तब सस्ता अनाज देना शुरू किए। आज कहीं कोई भूखमरी नहीं है। यह हमारे आदिवासी समाज के लिए बड़ी उपलब्धि है। 15 साल में शिक्षा, चिकित्सा सहित अन्य क्षेत्रों में पर्याप्त विकास हुआ। कैबिनेट बैठक में 18 लाख पीएम आवास को मंजूरी दे दी गई है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री साय ने कहा कि यह हमारा चुनावी वादा था। प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव के दौरान कहा था कि, बीजेपी सरकार बनने पर मुख्यमंत्री पहला फ़ैसला आवास योजना का लेंगे। अब जल्द ही राज्य के ग़रीब वर्ग के लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिलेगा। कैबिनेट बैठक में उपमुख्यमंत्री अरुण शाह और विजय शर्मा भी मौजूद थे ।

## मथुरा में विवादित जमीन का सर्वे होगा

### श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सर्वे के लिए दी अनुमति

**इलाहाबाद।** मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पर फैसला सुना दिया है। मथुरा में विवादित जमीन का भी अब सर्वे होगा। हिंदू पक्ष की तरफ से शाही ईदगाह परिसर का कोर्ट कमीशन नियुक्त कर सर्वे की मांग की गई थी। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट में याचिका पर सुनवाई पूरी हुई थी।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गुरुवार दोपहर दो बजे मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि केस की पोषणीयता तथा कोर्ट कमिश्नर भेजे जाने संबंधी अर्जी पर अपना फैसला सुनाया। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत वाद की पोषणीयता पर आपत्ति की गई थी। कोर्ट कमिश्नर भेजे जाने संबंधी मंदिर पक्ष की अर्जी पर कोर्ट ने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड व शाही ईदगाह इंतजामिया कमेटी को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय दिया था। जिसपर आज कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सर्वे को मंजूरी दी है।

न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन की पीठ ने मूल मुकदमे में अधिवक्ता हरि शंकर जैन, विष्णु शंकर जैन, प्रभाष पांडे और देवकी नंदन के माध्यम से देवता (भगवान श्री कृष्ण विराजमान) और 7 अन्य द्वारा दायर आदेश 26 नियम 9 सीपीसी आवेदन पर यह आदेश पारित किया।

अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन की याचिका में कहा गया है कि वहां कमल के आकार का एक स्तंभ है जोकि हिंदू मंदिरों की एक विशेषता है और शेषनाग की एक प्रतिकृति है जो हिंदू देवताओं में से एक हैं और जिन्होंने जन्म की रात भगवान कृष्ण की रक्षा की थी। याचिका में यह भी बताया गया है कि मस्जिद के स्तंभ के आधार पर हिंदू धार्मिक प्रतीक हैं और नक्काशी में ये साफ दिखते हैं। याचिकाकर्ताओं ने अनुरोध किया था

कि निर्धारित समय सीमा के भीतर सर्वेक्षण के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपने के विशेष निर्देश के साथ एक आयोग का गठन किया जाये। इस पूरी कार्यवाही की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराने का भी अनुरोध किया गया था।

हम आपको याद दिला दें कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस वर्ष मई में मथुरा की अदालत में लंबित श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़े सभी मुकदमे अपने पास स्थानांतरित कर लिए थे। अब अपना फैसला सुनाते हुए अदालत ने सर्वे की मंजूरी दे दी है। हाईकोर्ट ने सर्वे की मंजूरी के साथ ही साथ फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करने को भी कहा है। बताया जा रहा है कि मथुरा में होने वाला सर्वे ज्ञानवापी से थोड़ा अलग होगा।

इस बीच, श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट और इस मामले के याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। वहीं दूसरी ओर अदालत के फैसले पर भड़कते हुए AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कानून का मजाक बना दिया गया है। ओवैसी ने अदालत का फैसला आने के बाद मीडिया से बातचीत में कहा, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वे कराने की इजाजत दे दी। बाबरी मस्जिद मामले में आये फैसले के बाद मैंने कहा था कि संघ परिवार की शरारत बढ़ेगी। ओवैसी ने दावा किया कि मथुरा विवाद दशकों पहले मस्जिद कमेटी और मंदिर ट्रस्ट ने आपसी सहमति से सुलझा लिया था। ओवैसी ने भड़कते हुए कहा कि जब एक पक्ष मुस्लिमों को लगातार निशाना बनाने में रुचि रखता है तो हमें देन-लेन का उपदेश ना दें। उन्होंने कहा कि कानून मायने नहीं रखता बल्कि मुसलमानों के सम्मान को ठेस पहुंचाना ही इनका मकसद है।

## लगातार चौथे दिन नक्सली हमला, जवान शहीद

**कांकेर.** छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में गुरुवार को नक्सलियों द्वारा किए गए विस्फोट में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के एक जवान की जान चली गई। यह दो दिनों में दूसरी मौत है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह घटना परतापुर पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत सदाकटोला गांव के पास हुई, जब बीएसएफ और जिला पुलिस बल की एक संयुक्त टीम गश्त पर थी। पुलिस ने यह जानकारी दी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह घटना परतापुर पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत सड़कटोला गांव के पास उस समय हुई जब बीएसएफ और जिला पुलिस का एक संयुक्त दल को गश्त कर रहा था। उन्होंने बताया कि नक्सलियों द्वारा किए गए विस्फोट में बीएसएफ के प्रधान आरक्षक अखिलेश राय

(45) घायल हो गए।

अधिकारी ने आगे कहा कि इलाके में बीएसएफ, जिला रिजर्व गार्ड और जिला पुलिस बल की संयुक्त टीम द्वारा तलाशी अभियान जारी है। इससे पहले बुधवार को, राज्य के नारायणपुर जिले में नक्सलियों द्वारा सुरक्षा कर्मियों की एक टीम पर हमला करने और इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस विस्फोट करने से छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के एक जवान की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया।

अधिकारी ने बताया कि घटना के बाद राय को प्रारंभिक उपचार दिया गया और बेहतर इलाज के लिए पखांजूर भेजा गया, लेकिन उन्होंने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। उन्होंने बताया कि शहीद जवान उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे।

अधिकारी ने बताया कि इलाके में बीएसएफ, जिला रिजर्व गार्ड और जिला बल के संयुक्त दल द्वारा तलाशी अभियान जारी है। नारायणपुर जिले में बुधवार को नक्सलियों द्वारा सुरक्षाकर्मियों की टीम पर हमला करने और इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) से विस्फोट करने से छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल (सीएएफ) का एक जवान शहीद हो गया था और एक अन्य घायल हो गया था।

### उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने शहीद कमलेश साहू के परिजनों से मिलकर बंधाया ढांढस

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने नारायणपुर जिले में हुए आईईडी ब्लास्ट में सक्ती जिले के हसौद निवासी शहीद जवान श्री कमलेश साहू को नमन कर श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं। मुख्यमंत्री ने शहीद जवान के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि इस दुख की घड़ी में पूरा छत्तीसगढ़ उनके परिजनों के साथ है। श्री कमलेश साहू ने आदम्य साहस का परिचय देते हुए वीरगति प्राप्त की है।

प्रमुख समाचार

### अफजाल अंसारी की लोकसभा सदस्यता फिर से बहाल होगी

**नई दिल्ली।** सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 2007 के गैंगस्टर एक्ट मामले में अयोग्य ठहराए गए

बहुजन समाज पार्टी के सांसद अफजल अंसारी की सजा को निलंबित कर दिया, एक विधायक के रूप में उनकी स्थिति को इस शर्त के साथ बहाल कर दिया कि वह सदन की कार्यवाही में भाग लेने के बावजूद वोट नहीं दे पाएंगे या भत्ते नहीं ले पाएंगे। पांच बार विधानसभा सदस्य और दो बार सांसद रहे अंसारी को दोषी ठहराए जाने और चार साल जेल की सजा सुनाए जाने के बाद 1 मई को लोकसभा सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने 3-2 के बहुमत से अंसारी की अपील को आंशिक रूप से अनुमति दे दी, जबकि सजा के खिलाफ उनकी याचिका पर फैसला करने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लिए 30 जून, 2024 की समय सीमा निर्धारित की। जस्टिस कांत और भुइयां ने अंसारी की याचिका के पक्ष में फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति दत्ता ने कहा कि उनकी अपील विफल होनी चाहिए।

### 6 समन के बाद भी नहीं हुए हाजिर, अब ईडी हेमंत सोरेन को कर सकती है गिरफ्तार!

**झारखंड।** मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लगातार छठी बार झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के जांच अधिकारियों के सामने पेश होने से इनकार करने के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें हिरासत में लेने के चरम विकल्प पर विचार किया है और भ्रष्टाचार के आरोपों पर उनकी प्रतिक्रिया मांगी है। उसकी जांच की जा रही है। सूत्रों ने कहा कि सोरेन से पूछताछ जांच के लिए महत्वपूर्ण है और इस बात पर जोर दिया कि समन के खिलाफ उनकी अपील को उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ने खारिज कर दिया था। झारखंड के सीएम पर खनन और भूमि घोटाले सहित कई मामलों में भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं। हाल ही में नेपाल से निर्वासित किए गए एक माओवादी के आरोपों के संबंध में भी उसकी जांच चल रही है कि उसके गिरोह ने सीएम के करीबी व्यक्तियों को संरक्षण राशि का भुगतान किया था। सोरेन ईडी के रांची कार्यालय में उपस्थित होने में विफल रहे, जहां उन्हें भूमि घोटाले की जांच में बयान दर्ज करने के लिए बुलाया गया था।

### भाजपा सांसद पांडे ने रेल मंत्री वैष्णव से की मुलाकात, वन्दे भारत ट्रेन को लेकर की बड़ी मांग

**राजनांदगांव।** राजनांदगांव से भाजपा सांसद संतोष पांडे ने आज केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। इसके साथ ही ट्रेनों को लेकर कुछ मांग भी रखी है। इस मुलाकात के बाद संतोष पांडे ने सोशल मीडिया पर तस्वीरों को साझा करते हुए लिखा कि आज केन्द्रीय रेल मंत्री माननीय अश्विनी वैष्णव जी से सौजन्य भेंट कर भगत की कोठी, बिलासपुर से नागपुर तक संचालित वन्दे भारत ट्रेन का डोंगरगढ़ स्टेशन एवं पुरी-गांधीधाम तथा पुरी-अजमेर ट्रेन के राजनांदगांव स्टेशन में ठहराव हेतु पत्र सौंपकर आग्रह किया। इसके साथ ही भाजपा सांसद ने लिखा कि इस दौरान डोंगरगढ़ से कटघोरा तक प्रस्तावित एवं बहुप्रतीक्षित नवीन रेल लाइन निर्माण कार्य को जल्द पूर्ण करने के संबंध में भी चर्चा की। माननीय मंत्री महोदय ने इस संबंध में अधीनस्थ अधिकारी से चर्चा कर तत्काल कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया। वहीं, छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार के गठन से गदगद संतोष पांडे ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि सुशासन का सूर्योदय।

### एक्शन में मोहन सरकार, भाजपा नेता की हथेली काटने वालों के घर पर चला बुलडोजर

**भोपाल।** पुलिस ने इस मामले में अन्य आरोपियों असलम, शाहरुख, बिलाल और समीर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी फारुख राइन, जिसे मिन्नी के नाम से भी जाना जाता है, ने कथित तौर पर भाजपा कार्यकर्ता ठाकुर का हाथ काट दिया, जिसके कारण अधिकारियों के आदेश पर उसके घर पर बुलडोजर लाया गया। मध्य प्रदेश के नवनियुक्त मुख्यमंत्री मोहन यादव एक्शन में नजर में आ रहे हैं। पद संभालते ही मोहन यादव ने भाजपा कार्यकर्ता देवेन्द्र ठाकुर पर हमला करने के आरोपी व्यक्ति के घर पर बुलडोजर कार्रवाई का आदेश दिया। आरोपों के मुताबिक, आरोपी की पहचान फारुख राईन के रूप में हुई है, जिसने बीजेपी कार्यकर्ता पर हमला किया, जिसमें देवेंद्र ठाकुर का हाथ कट गया था। बताया जा रहा है कि यह हमला चुनावी रंजिश के चलते किया गया है।

### संसद सुरक्षा मामला: चारों आरोपियों को 7 दिन की पुलिस रिमांड

**नई दिल्ली।** दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को संसद सुरक्षा उल्लंघन मामले में गिरफ्तार किए गए

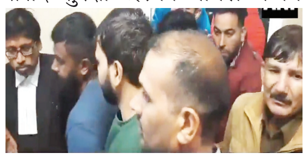

चारों आरोपियों की सात दिन की रिमांड आज मिल गई। आरोपियों को आज पटियाला हाउस कोर्ट ले जाया गया जहां अभियोजन पक्ष ने 15 दिन की रिमांड की मांग की लेकिन कोर्ट ने आरोपियों को सात दिन की रिमांड पर भेज दिया। पुलिस ने अदालत में यह भी दावा किया कि आरोपियों ने लोकसभा के अंदर गैस कनस्तरों की तस्करी के लिए जूते लखनऊ से खरीदे थे जिनमें उन्होंने गुहाएं बनाई थीं। दिल्ली पुलिस के वकील अतुल श्रीवास्तव हमने 15 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड का अनुरोध किया था, जिस पर अदालत ने विचार किया और अदालत सात दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड देने की दयालु रही। जिन लोगों को हिरासत में भेजा गया है वे हैं - मनोरंजन डी, सागर शर्मा, नीलम आज़ाद और अनमोल शिंदे। पुलिस ने आज कहा कि उनकी टीमें जांच के लिए मुंबई, लखनऊ और मैसूरु जैसे शहरों का दौरा करेंगी, ताकि आरोपियों की वित्तीय स्थिति के बारे में जानकारी जुटाई जा सके।

## लोकतंत्र में छोटे दलों का संक्रमण काल

**राजेश बादल**

भारत में छोटी और क्षेत्रीय सियासी पार्टियों के लिए आने वाला समय बहुत मुश्किल भरा हो सकता है। वे इतिहास के उस मोड़ पर हैं, जहां राष्ट्रीय पार्टियां उनके अस्तित्व के लिए अब चुनौती बनती जा रही हैं। भारतीय संस्कृति में विविधता को देखते हुए कभी ये प्रादेशिक दल लोकतंत्र के गुलदस्ते मान लिए गए थे. मगर शनैः-शनैः इस गुलदस्ते से सुगंध काफूर हो गई। हालिया पांच प्रदेशों के विधानसभा चुनाव इसकी बानगी पेश करते हैं। दोनों बड़ी पार्टियों के बीच मत प्रतिशत की गलाकाट स्पर्धा थी. इसलिए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के सामने अपने वोट बैंक में निर्णायक बढ़त हासिल करने की चुनौती थी। दूसरी ओर बहुमत नहीं मिलने की आशंका को देखते हुए प्रादेशिक दलों के एक-दो विधायक भी उनके लिए मायने रखते थे। इसके मद्देनजर वे क्षेत्रीय दलों के एक या दो फीसदी वोटों की भी उपेक्षा नहीं कर सकती थीं। यह दिलचस्प सियासी स्थिति है कि प्रादेशिक पार्टियों से सहयोग का रास्ता भी खुला रखा जाए और उनके वोट बैंक में सेंध लगाकर अपना जनाधार भी बढ़ाया जाए। छोटी पार्टियों के लिए दोनों बड़ी पार्टियों की महाभारत में अपना वोट बैंक बचा कर रखने की चुनौती भी थी। इसके अलावा एक दृश्य और भी दिखाई दिया। मिजोरम में एक नवोदित पार्टी दूसरी छोटी पार्टी के लिए ही गंभीर चुनौती बन गई और बड़ी पार्टियों के लिए दरवाजे एक तरह से बंद रहे। तेलंगाना में राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस ने क्षेत्रीय पार्टी भारत राष्ट्र समिति को सत्ता से बाहर कर दिया। बीआरएस अपना आकार बढ़ाने और राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार करने का सपना ही देखती रही। मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में तो क्षेत्रीय दलों का एक तरह से सफाया ही हो गया। बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी तथा अन्य छोटे दलों को इन राज्यों ने भारी झटका दिया। भारतीय जनता पार्टी के जनाधार की बाढ़ में सारे छोटे दलों का वोट बैंक भी बह गया। इससे पहले हमने उत्तरप्रदेश में भी देखा था, जब विधानसभा चुनाव के परिणाम बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के लिए करारा संदेश लेकर आए थे। जिस प्रदेश में इन पार्टियों ने जन्म लिया, उसी प्रदेश में उनका मत प्रतिशत तेजी से गिरा है। वैसे तो भारतीय संवैधानिक लोकतंत्र किसी भी नए दल का उगना नहीं रोकता। अगर वह पार्टी ठोस वैचारिक आधार, देश के साझा विरासत वाले ढांचे और विकास के व्यावहारिक स्वरूप के साथ अपना रास्ता बनाती है तो भारतीय लोकतंत्र उसका स्वागत करता है। शिखर पर उपस्थित राष्ट्रीय पार्टियों का आकार बड़ा होता है। उनमें नई पीढ़ी को समुचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता। यह भी नए दलों के अस्तित्व में आने का एक कारण है। उत्तरप्रदेश जैसे विराट आकार वाले प्रदेश में तो नई नस्ल ही नहीं,

समाज के सभी वर्गों और जातियों को साथ लेकर भी राष्ट्रीय दल नहीं चल पा रहे थे। इससे अनेक समुदायों, जातियों, उपजातियों का प्रतिनिधित्व करने वाले दल पैदा हो गए। बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और अपना दल इसका उदाहरण हैं। भारत में सबसे अधिक आदिवासी मध्यप्रदेश में रहते हैं और उनमें भी गोंड आदिवासियों की संख्या अनेक राज्यों की कुल आबादी से भी अधिक है। मगर विकास की मुख्य धारा में उनकी लगातार उपेक्षा के कारण गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने जन्म लिया। मेरा मत है कि किसी एक समुदाय या जाति या मजहब की नुमाइंदगी करने वाली पार्टी भारतीय संविधान की भावना का आदर भी नहीं करती। जब वह क्षेत्रीय दल अपनी-अपनी जाति या संप्रदाय का प्रवक्ता बनकर काम करता है तो उसमें लोकतंत्र भी नदारद रहता है। सामूहिक नेतृत्व ही जम्हूरियत की बुनियादी शर्त है और कमोबेश सारी पार्टियां इस पैमाने पर नाकाम रही हैं। वे पुरातन कबीलों की संरचना के आधार पर काम कर रही हैं। वे शुरुआत में सियासी वजूद बनाए रखने के लिए सजातीय वोटों को लुभाकर साथ लाती हैं। पर, बाद में उनके निजी हितों को नहीं साध पातीं. इससे उनका जनाधार खिसकने लगता है। तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार, पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र और उत्तरप्रदेश ऐसी ही प्रादेशिक पार्टियों का उदाहरण हैं।

बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी उत्तरप्रदेश में पनपीं, लेकिन उसी प्रदेश में वे आज अपने सबसे दुर्बल आकार में दिखाई देती हैं। अपने जन्म के पच्चीस साल बाद भी उनका कोई राष्ट्रीय सपना नहीं था और न भारत का गणतंत्र उनको अखिल भारतीय स्तर पर स्वीकार कर पाया।

वास्तविकता तो यह भी है कि प्रादेशिक दल अन्य प्रदेशों में अब अपने उम्मीदवार इसीलिए मैदान में उतारते हैं क्योंकि प्रादेशिक और राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता बनाए रखने के लिए उन्हें मतों की निर्धारित संख्या जरूरी होती है। वे राष्ट्रीय स्वरूप में उभरना ही नहीं चाहते. इन छोटी पार्टियों के संस्थापकों ने जितना विस्तार पार्टी को दिया था, आज भी वह उतना ही है. उसे आधुनिक और राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक भूमिका देने की बात ही इन दलों ने नहीं सोची। इसका खामियाजा कमोबेश सारे छोटे दलों ने भुगता है। आधुनिक लोकतंत्र परंपरागत तौर-तरीकों से नहीं चलाया जा सकता, यह प्रादेशिक पार्टियों को समझना होगा. यह अजीब सा लगता है कि डीएमके, एआईडीएमके या बीजू जनता दल जैसे क्षेत्रीय दल दशकों से अपनी सीमित भूमिका से ही संतुष्ट नजर आते हैं। पर, उनके लिए भी मौजूदा दौर बड़ी चुनौतियां लिए खड़ा है।

भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जे. पी. नड्डा ने बिहार में जो आशंका जताई थी, वह निर्मूल नहीं थी। उन्होंने कहा था कि सारे क्षेत्रीय, प्रादेशिक और छोटे दल धीरे-धीरे समाप्त हो सकते हैं। इस सोच के पीछे दो ही कारण हो सकते हैं। एक तो यह कि राष्ट्रीय दल जनाधार बढ़ाना चाहते हों और दूसरा यह कि क्षेत्रीय दलों ने विराट स्वरूप की कामना करना ही छोड़ दिया हो। दोनों ही स्थितियां लोकतंत्र के लिए कोई बहुत शुभ संकेत नहीं हैं।

# नए साल पर घर लौटने का मां से किया था वादा, छोटे भाई ने दी मुखाग्नि

**सक्ती।** मन में देश और राज्य की सेवा करने का संकल्प लेकर छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल ज्वाइन करने वाले हसौद के लाल कमलेश साहू दशहरा और दिवाली मनाने गांव आया था। गांव से लौटते वक्त उसने घर पर बताया था कि इस

साल की छुट्टी खत्म हो गई है और अगले साल वह फिर आएगा। घर में उसकी पत्नी बुजुर्ग पिता-माता और भाई को भी उसके वापस आने का इंतजार था, लेकिन बुधवार की दोपहर एक दुखद खबर ने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया। नारायणपुर में हुए आईईडी ब्लास्ट में सर्चिंग के लिए निकले कमलेश साहू बलिदान हो गए। हसौद निवासी मुंगेश्वर साहू और उनकी पत्नी ताराबाई के दो बेटे थे। कमलेश सबसे बड़ा और यशवंत छोटा है, उनकी एक बेटी भी है। छोटे भाई यशवंत ने बताया कि कमलेश 2010 से सेवा में था। सीएएफ में जाने के लिए तैयारी कर रहे थे। 2018 में उन्होंने सीएएफ की ज्वाइनिंग ली थी। कमलेश साहू सीएएफ नवमी बटालियन के जवान में थे। उनकी पोस्टिंग नारायणपुर में थी। बुधवार को आमदई खदान के पास कैफ के जवान सर्चिंग के लिए निकले थे। कमलेश साहू और एक और जवान बालोद निवासी विनय कुमार सर्चिंग के दौरान फंड में थे। इस दौरान आईईडी ब्लास्ट हो गई, जिससे वह चपेट में आ गए। इस घटना में कमलेश साहू बलिदान हो गए और विनय कुमार भी घायल हो गया।

**20 महीने पहले ही हुई थी शादी**-कमलेश साहू की शादी 20 महीने पहले ही हुई थी। उसकी शादी मुड़पार गांव के बिंदा साहू के साथ 28 अप्रैल 2022 को धूमधाम से हुई थी। उनके कोई संतान नहीं है। दिवाली के समय अपनी पत्नी से फिर से आने का वादा करके कमलेश गया था, लेकिन आईईडी ब्लास्ट में कमलेश बलिदान हो गए।

**कलेक्टर और एसएसपी पहुंचे बलिदान जवान के घर**- आईईडी ब्लास्ट में जवान के बलिदान होने की सूचना मिलने पर कलेक्टर नूपुर राशि पन्ना और एसपी मरी सहित जवान कमलेश साहू के घर पहुंचे। कलेक्टर ने उनकी पत्नी बिंदा को गले लगाकर ढाढ़स बंधाया। उन्होंने उनके पिता और मन से भी मुलाकात की। जवान कमलेश साहू को स्पेशल एंबुलेंस से नारायणपुर से उनके गृह ग्राम हसौद लाया गया। घर पर अंतिम दर्शन कराने के बाद पूरे गांव का भ्रमण किया।

## नक्सली वारदात षड़यंत्र का हिस्सा, सख्ती से निपटेगी सरकार : शर्मा

**सक्ती।** छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा नक्सली हमले में शहीद हुए कमलेश साहू की अंतिम यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कमलेश साहू के परिवार से मुलाकात की। विजय शर्मा ने परिवार की हर संभव मदद करने का भरोसा

दिलाया।इस दौरान विजय शर्मा ने नक्सलियों की हरकत को कायराना बताते हुए इसे एक साजिश करार दिया। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा नक्सली आखिर ऐसा कर क्यों रहे हैं। इससे उन्हें क्या फायदा मिलने वाला है।बस कहीं पर गोली चला देना या बम फोड़ देने से क्या कुछ मिल रहा है।ये सिर्फ वहशीपन है। इससे भारत का निर्माण नहीं होने वाला है। आखिर इतने साल तक नक्सली आतंक फैला रहे हैं उन्हें इससे क्या कुछ मिल गया है।इसके पीछ जरूर कुछ षड़यंत्र है।आने वाले दिनों में सरकार ऐसी चीजों से सख्ती से निपटेगी।

आपको बता दें कि नारायणपुर के अमदाई खदान के तरफ जवान सर्चिंग के लिए निकले थे।इसी दौरान नक्सलियों ने रास्ते में आईईडी बिछाकर रखा था। जैसे ही जवानों की टुकड़ी आईईडी के ऊपर से गुजरी सीएएफ का 9वीं बटालियन का जवान कमलेश साहू इसकी चपेट में आ गया।कमलेश साहू को इलाज के अस्पताल लाया गया।जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। गुरुवार को कमलेश का गृहग्राम हसौद में अंतिम संस्कार किया गया।कमलेश साहू का डेढ़ वर्ष पहले ही विवाह हुआ था।घर पर माता पिता के साथ बड़ा भाई भी है।

## दुख की घड़ी में पूरा छत्तीसगढ़ शहीद जवान के परिजनों के साथ है: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने नारायणपुर जिले में हुए आईईडी ब्लास्ट में सक्ती जिले के हसौद निवासी शहीद जवान श्री कमलेश साहू को नमन कर श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं। मुख्यमंत्री ने शहीद जवान के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि इस दुख की घड़ी में पूरा छत्तीसगढ़ उनके परिजनों के साथ है। श्री कमलेश साहू ने आदम्य साहस का परिचय देते हुए वीरगति प्राप्त की है। उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने आज सक्ती जिले के हसौद पहुंचकर शहीद श्री कमलेश साहू को श्रद्धांजलि अर्पित की और परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। उन्होंने शहीद के पिता श्री मुंगेश्वर साहू को गले लगाकर उन्हें ढांढस बंधाया। श्री शर्मा ने शहीद कमलेश की माता श्रीमती तारा देवी साहू, पत्नी श्रीमती वृंदाबाई साहू, शहीद की बड़ी बहन श्रीमती कमलेश्वरी साहू और छोटे भाई श्री यशवंत साहू सहित अन्य परिजनों से भी मुलाकात की और सांत्वना दी। उन्होंने कहा कि शहीद श्री कमलेश साहू ने देश की सेवा करते हुए वीरगति प्राप्त की है, उनकी शहादत को नमन है। विधायक श्री केदार कश्यप, जैजैपुर विधायक श्री बालेश्वर साहू, चंद्रपुर विधायक श्री रामकुमार यादव सहित विभिन्न जनप्रतिनिधियों ने भी हसौद पहुंचकर शहीद श्री कमलेश को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर सक्ती की कलेक्टर श्रीमती नूपुर राशि पन्ना, पुलिस अधीक्षक श्री एम. आर आहिरे सहित बड़ी संख्या में नागरिकों ने भी शहीद जवान को श्रद्धांजलि अर्पित की।

## विस्फोटक सामग्री के साथ 2 नक्सली गिरफ्तार

**सुकमा।** जिले में चलाये जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत चिंतलनार थाना व कैंप से सीआरपीएफ की 223वीं बटालियन के उप कमांडेंट रमेश कुमार, कोबरा 201 बटालियन के सहायक कमांडेंट हरीश चंद्र मनोरी व डीआरजी प्रभारी नंदा मरकाम एवं नरसापुरम कैंप में तैनात कोबरा 201 बटालियन के सहायक कमांडेंट श्रवण कुमार के नेतृत्व में जवानों की टुकडियां सर्चिंग अभियान में मोरपल्ली, तिम्मापुरम, पेद्दाबोडकेल, चिन्नाबोड़केल व जब्बागट्टा इलाके की ओर रवाना हुई थी। अभियान के दौरान संयुक्त बल ने जिले के चिंतलनार थाना क्षेत्र के तिम्मापुरम के जंगलों में घेराबंदी कर विस्फोटक सामग्री के साथ 2 नक्सली हेमला जोगा व सोड़ी दुला निवासी तिम्मापुरम को गिरफ्तार किया है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गिरफ्तार दोनों नक्सली संगठन में पेद्दाबोड़केल आरपीसी में दण्डकारण्य आदिवासी किसान मजदूर संघ सदस्य के रूप में सक्रिय थे। उनके कब्जे से डेटोनेटर, कॉरडेक्स वायर, इलेक्ट्रिक वायर, जिलेटिन कैप्सूल बरामद किया गया है। थाना चिंतलनार में कार्यवाही उपरांत गुरूवार को न्यायालय के समक्ष पेश किया जहां से उन्हें जेल दाखिल कर दिया गया।

# जामपारा धान खरीदी केंद्र प्रबंधक के खिलाफ थाने में शिकायत

## आदिवासी किसान ने लगाए अभद्रता के आरोप

**कोरिया।** बैकुंठपुर थाने में धान खरीदी केंद्र जामपारा के प्रभारी धौराटिकरा समिति प्रबंधक अजय साहू के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। जिन पर आदिवासी किसान से अभद्रता करने का आरोप लगा है। आदिवासी किसान रामरुप सिंह ने थाने में शिकायत दी है। रामरुप सिंह की माने तो प्रदेश का मुखिया आदिवासी समाज से चुना गया है।लेकिन धान खरीदी केंद्र प्रभारी अजय साहू आए दिन कुछ ना कुछ कारण बनाकर लोगों के साथ अभद्रता कर रहे हैं। रामरूप ने अजय साहू को धान खरीदी केंद्र से हटाने की मांग की है।

रामरूप के मुताबिक वो हमेशा की तरह जामपारा समिति में पहुंचकर कार्य के लंबित भुगतान के लिए चेक में साइन करके घर जाने लगे,इसी दौरान अजय साहू ने उन्हें रोककर अभद्रता की।जिसके बाद उन्होंने इस बात की शिकायत थाने में दर्ज कराई है।इसके अलावा रामरूप ने आरोप लगाया है कि पहले भी अजय साहू की शिकायत उच्च अधिकारियों से लिखित तौर पर की गई है।जिसमें अजय साहू के द्वारा बाहरी लोगों को लाकर काम करवाने का आरोप है। रामरुप की माने तो समिति एक संस्था है। जहां पर नियुक्त हुए कर्मचारी ही कार्य करते हैं। लेकिन अजय साहू समिति की छवि को धूमिल करते हुए अपने निजी स्वार्थ के कारण धान खरीदी जैसा महत्वपूर्ण काम बाहरी लोगों से करवा रहे हैं।जिससे समिति के स्थायी कर्मचारियों का काम प्रभावित हो रहा है। समिति के कर्मचारी भी इनके बर्ताव से अपमानित महसूस कर रहे हैं।

आपको बता दें कि अजय साहू के खिलाफ विभाग के अधिकारियों से शिकायत की गई है।लेकिन अब तक किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है।जिसके बाद अब आदिवासी समाज ने सीएम से मिलकर अपनी बात रखने की बात कही है।

# पुलिस लाइन खोखरा में अग्निवीर और थल सेना की भर्ती आज से, नौ दिन चलेगा अभियान

## एसपी की अपील- अभ्यर्थी किसी भी प्रलोभन में न आएं

**जांजगीर।** जांजगीर चांपा जिले के पुलिस लाइन खोखरा के मैदान में 15 दिसंबर से 23 दिसंबर तक अग्निवीर सेना और थल सेना की भर्ती की जानी है। इसमें छत्तीसगढ़ के 33 जिले से लगभग 7 हजार अभ्यर्थी शामिल होंगे। कलेक्टर, एसपी और कर्नल ने प्रेस कांफ्रेंस कर दी गई जानकारी।

मिली जानकारी अनुसार, पुलिस लाइन के सभाकक्ष में बुधवार को जिले की कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी, एसपी विजय अग्रवाल और सेना भर्ती के अधिकारी एन सेमलटी ने प्रेस कांफ्रेंस की। इस दौरान कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने बताया कि जांजगीर चांपा जिले को सेना भर्ती के लिए चुना गया है। अग्निविर सेना और थल सेना की भर्ती के लिए पुलिस लाइन के मैदान को तैयार किया गया है। यह मैदान 400 मीटर का है जिसमें तीन राउंड में कुल 1600 मीटर की दौड़ कराई जाएगी।

कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने कहा कि जो अभ्यर्थी ट्रेन से आ रहे हैं उन्हें रैली स्थल तक लाने के लिए नैला रेलवे स्टेशन में वहान लगाया जाएगा। पूछताछ केंद्र बनाया गया है साथ ही अभ्यार्थियों के लिए आवास, भोजन के लिए मंडी परिसर को तैयार किया गया है।

एसपी विजय अग्रवाल ने सुरक्षा को लेकर कहा कि पुलिस लाइन मैदान की ओर आने वाली सड़क को खोखरा चौक से फोर लाइन चौक तक बंद कर दिया जाएगा जिससे भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। परिसर के अंदर और बाहर 20 जवान तैनात रहेंगे। एसपी ने अपील कर कहा कि अभ्यर्थी किसी भी

प्रलोभन में न आएं। भर्ती की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ ऑनलाइन होगी। यदि कोई भी व्यक्ति प्रलोभन देने की बात करे तो तुरंत उसकी सूचना दी जाए।

कर्नल एन सेमल्टी ने अग्निवीर सेना और थल सेना की भर्ती की प्रक्रिया के बारे में बताया कि सेना में भर्ती के लिए पहले दौड़ कराई जाती थी मगर इस बार बदलाव किया गया है। पहले ऑनलाइन परीक्षा ली गई जिसमें पास होने वाले लगभग 7 हजार अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड जारी किया गया है। सुबह से लेकर रात्रि 12 बजे तक अभ्यार्थियों के दस्तावेज चेक किये जाएंगे। मेडिकल चेक किया जाएगा। इसके बाद रात्रि 2 बजे रनिंग ट्रैक में दौड़ कराई जाएगी। 15 दिसंबर को पहले दिन 800 अभ्यार्थियों की दौड़ होगी। उसके बाद दूसरे दिन 1000 से 1200 अभ्यर्थियों की दौड़ होगी।

## गुणवत्ताहीन सड़क निर्माण पर भड़के डिप्टी सीएम विजय शर्मा

**कवर्धा।** नवनिर्वाचित उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने डिप्टी सीएम की शपथ लेने के तत्काल बाद ही कबीरधाम जिले में चल रही सड़क पेंचवर्क के गुणवत्ताहीन कार्यों को संज्ञान में लिया है। उन्होंने संबंधित लोकनिर्माण विभाग के अधिकारी को जिले के सहसपुर लोहारा से रेंगाखार के बीच पीडब्ल्यूडी अंतर्गत पेच रिपेयरिंग के कार्यों को जांच के निर्देश दिए हैं।

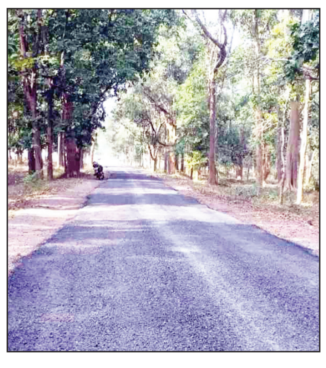

दरअसल, सोशल मीडिया में खबर चल रही थी कि सहसपुर लोहारा से रेंगाखार मार्ग में डामर सड़क का निर्माण कार्य कराया गया था, लेकिन सड़क निर्माण के दो दिन बाद ही सड़क उखड़ गया। उपमुख्यमंत्री के आदेश पर विभाग के अधिकारियों की ओर से तत्काल मौके पर पहुंच कर उस सड़क की जांच की गई और सड़क को अमान्य घोषित कर पुन: सड़क निर्माण कार्य कराने ठेकेदार को आदेशित किया गया।

डिप्टी सीएम ने कहा कि अब छत्तीसगढ़ में सुशासन का राज चलेगा और गलत काम करने वालों के खिलाफ बुलडोजर चलेगा। उन्होंने सख्त निर्देश करते हुए कहा कि सभी निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए। लोकहित में हो रहे समस्त निर्माण कार्यों में गुणवत्ताहीन कार्यों पर सख्ती बरती जाएगी।

**छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार**

## लौह अयस्क परिवहन ठप ग्रामीणों ने रोके ट्रकों के पहिए

**भानुप्रतापपुर।** कांकेर जिले के दुर्गुकोंदल विकासखंड स्थित चेमल खदान से लौह अयस्क परिवहन कर रहे 100 से अधिक ट्रकों के पहिए बीते पांच दिनों से थमे हैं। अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत खदान के आसपास के गांव के रहवासी ट्रकों को रोककर रखे हुए हैं। जंगल में बिना राशन-पानी के ट्रकों के खड़े रहने से चालक-परिचालक परेशान हैं। वहीं ट्रक मालिकों का कहना है कि प्रबंधन और ग्रामीणों की लड़ाई में ट्रकों को रोकना उचित नहीं है। प्रशासन से अनुरोध के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने पर रोष जता रहे हैं। वहीं आंदोलनरत ग्रामीण अपनी मांगों को लेकर कंपनी के अधिकारियों के अलावा किसी से बात नहीं करने पर अड़े हुए हैं। यहां तक मीडिया से भी चर्चा करना मुनासिब नहीं समझ रहे हैं।

## कांग्रेस पार्षद का बार सील

**कवर्धा।** कांग्रेस पार्षद का बार सील किया गया है। पार्षद पर आरोप है कि वो अपने बार में अवैध तरीके से लोगों को शराब परोस रहे थे और ये खेल पिछले 3 वर्षों से चल रहा था। पूरा मामला कवर्धा का है और पार्षद का नाम पार्षद अशोक सिंह है। जानकारी के मुताबिक कवर्धा शहर के मिनीमाता चौक पर नेशनल हाइवे 30 पर जगदम्बा होटल में संचालित व्यावसायिक क्लब को आबकारी विभाग ने सील कर दिया है। उक्त होटल मां दंतेश्वरी वार्ड-16 के कांग्रेस समर्थित पार्षद अशोक सिंह का है। आरोप है कि कांग्रेसी पार्षद अशोक सिंह ने अपनी पत्नी रूबी सिंह के नाम पर व्यावसायिक क्लब के लिए एफएल-4(क) का लाइसेंस लेकर होटल पर बार का बोर्ड लगा दिया था। प्रशासन की आंखों में धूल झोंककर यहां पिछले 3 साल से क्लब सदस्यों के अलावा बाहरी लोगों को शराब परोसी जा रही थी। यहां पड़ोसी राज्य मध्यप्रदेश की अवैध शराब खपाने की शिकायत भी मिल चुकी है। कवर्धा के नंदी विहार कॉलोनी के पास नेशनल हाइवे किनारे देशी व अंग्रेजी शराब दुकान मौजूद हैं। जिस जमीन पर ये शराब दुकान खोली गई है, वह कांग्रेस पार्षद अशोक सिंह का है।

## बीईएमएल कंपनी के वाटर टैंकर में लगी भीषण

**कोरबा।** गेवरा खदान में बीईएमएल कंपनी के वाटर टैंकर में भीषण आग लग गई। आग लगने से करोड़ों की मशीनें जलकर खाक हो गईं। घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। एसईसीएल गेवरा खदान में लगातार हादसे हो रहे हैं। पिछले तीन दिसंबर को सुरक्षा पखवाड़ा खत्म हुआ है। सभी कर्मचारियों अधिकारियों को सुरक्षा से संबंधित दिशा निर्देश दिए गए थे, उसके बाद भी हादसों का दौर लगातार जारी है। जानकारी के अनुसार, पिछले कई महीनों से यहां पर घटनाएं घट रही हैं। इसके बावजूद गेवरा प्रबंधन सुरक्षा के मामले को नजरअंदाज कर रहा है। बताया जा रहा है कि वाहन डीजल टैंक लीकेज की वजह से यह घटना घटित हुई है। वहीं, वाहन चालक अविनाश प्रताप ने किसी तरह टैंकर से कूदकर कर अपनी जान बचाई।

## अज्ञात वाहन की ठोकर से लकड़बग्घे की हुई मौत

**कोंड़ागांव।** केशकाल थाना क्षेत्र अंर्तगत राष्ट्रीय राजमार्ग 30 ग्राम मसुकोकोडा के पास अज्ञात वाहन की ठोकर से एक वन्य प्राणी लकड़बग्घे की मौत हो गई है। ग्रामीणों ने गुरूवार सुबह जब सडक किनारे लकड़बग्घे का शव देखा तो वन विभाग को इसकी सूचना दी। बताया जा रहा है आसपास जंगल में होने के कारण अक्सर शाम होते ही जंगली जानवर सडक पार करने के दौरान अक्सर तेज गति से आ रही वाहनों में कटरा जाते हैं। ग्रामीणों से मिली सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया। केशकाल उपमंडलाधिकारी सुषमा नेताम ने बताया कि मसुकोकोडा के ग्रामीणों ने सूचना दी कि सडक किनारे एक लकड़बग्घा की मौत हो गई है। जिसके बाद रेंजर एसआर ठाकुर अपने टीम के साथ मौके पहुंचे व मृत लकड़बग्घे को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के बाद विधिवत दाह संस्कार किया गया।

## नगरनार एल एंड टी कंपनी से चोरी का आरोपी गिरफ्तार

**जगदलपुर।** नगरनार थाना क्षेत्र अंर्तगत एल एंड टी कंपनी का सुरक्षा कर्मी सेवकराम कंपनी के कार्यक्षेत्र में तैनात सुरक्षा गार्ड आने-जाने वाले कर्मचारियों को जांच कर रहा था, उसी समय स्कुटी वाहन क्रमांक सीजी केएम 8489 से वहां पंहुचे कंपनी में काम करने वाला कर्मचारी शुभम बघेल पिता लक्ष्मीनाथ बघेल निवासी ग्राम घुरगुड़ा बाहर जाने के लिये आया जिसे रोककर जांच किया जो अपने स्कुटी वाहन के फुट रेस्ट जगह पर 6 नग लोहे का बेस जेक चोरी कर ले जा रहा था। जिस पर एल एंड टी कंपनी के अधिकारी और अन्य स्टाप चोरी के आरोपी शुभम बघेल को थाना नगरनार पुलिस को सौपते हुए नगरनार थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाया। रिपोर्ट पर थाना नगरनार में अपराध सदर कायम कर विवेचना में लिया गया। आरोपी के द्वारा अपने मेमोरेंडम कथन में अपराध कारित करना कबुल करने पर आरोपी के कब्जे से 06 नग लोहे का वेस जैक जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिल किया गया है।

# कांग्रेस लोकसभा चुनाव में भाजपा के हर झूठ को लेकर जनता के बीच जाएगी : लखेश्वर बघेल

**जगदलपुर।** विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ने विधानसभा स्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन बस्तर विधानसभा में विधायक लखेश्वर के गृह ग्राम गिरोला में गुरूवार को किया गया। लगातार तीसरी बार बस्तर विधानसभा से जीतकर विधायक बने कांग्रेस के लखेश्वर बघेल ने विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कार्यकर्ता चिंतन मनन कर आत्मावलोकन करें। भाजपा झूठ के दम पर चुनाव जीत गई है, लेकिन हमें हार नहीं मानना है। भाजपा के झूठ को जनता के सामने हमें लाना है। भाजपा ने झूठ का पुलिंदा थमाकर लोगों को गुमराह करने व बरगलाने का काम किया है। इसी झूठ के

दम पर उसने छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई है। उन्होने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी भाजपा के हर झूठ को लेकर जनता के बीच जाएगी। सच्चाई के लिए हम लड़ेंगे और मोहब्बत के साथ जीतेंगे।

लखेश्वर बघेल ने कहा कि भाजपा झूठ की बुनियाद पर खड़ी है, नरेंद्र मोदी ने हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख रूपये डालने का जुमला फेंककर प्रधानमंत्री बने हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने किसानों व महिला स्व सहायता समूहों से झूठा वादा कर जनता के साथ धोखाधड़ी की है। विधायक लखेश्वर बघेल ने कहा कि कांग्रेस ने लोगों को सीधे राहत देने का कार्य किया है। प्रत्येक तीज त्यौहार के लिए अनुदान, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को बोनस देने का काम किया है। बघेल कहा कि कांग्रेस के समस्त कार्यकर्ता राज्य के हर एक परिवार के साथ खड़ा है, किसी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम प्रत्येक परिवार के हक के लिए लड़ेंगे। लोगों को न्याय दिलाना ही हमारा पहला धर्म है। उन्होने कहा कि छत्तीसगढ़ मॉडल क्यों फेल हुआ यह चिंतन का विषय है। प्रदेश में बस्तर जिले की सारी सीटें कांग्रेस के लिए सबसे सुरक्षित सीट मानी जाती हैं, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि लोगों की सहानुभूति कांग्रेस के प्रति कम हो गई, यह चिंतन मनन का विषय है। लखेश्वर बघेल ने कहा कि इस बार के चुनाव में कांग्रेस के परंपरागत वर्चस्व वाले गांवों में भी हमें मुंह की खानी पड़ी है। जबकि भाजपा के गढ़ में हमने परचम लहराया है। इस बारे में भी चिंतन मनन करने की जरूरत है। बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने जिन योजनाओं का क्रियान्वयन किया था, उनकी पूरे देश मे सराहना हुई थी। कांग्रेस का घोषणा पत्र भी भाजपा से बेहतर था। हमारी योजनाओं और कामों को हम लोगों तक नहीं पहुंचा पाए और भाजपा का झूठ लोगों पर हावी हो गया, यह चिंता का विषय है।

## छत्तीसगढ़ में ठंड का सितम जारी, तीन जिलों में 11 डिग्री से नीचे लुढ़का पारा

**बिलासपुर।** छत्तीसगढ़ में बारिश का सिलसिला थमने के बाद प्रदेश का मौसम पूरी तरह बदल गया है। मौसम साफ होने के साथ ही मौसम ड्राई हो गया है। प्रदेश के तीन जिलों में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री से लेकर 8 डिग्री तक लुढ़क गया है। रायपुर मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के बाद तापमान में और गिरावट होने की संभावना जाहिर की है।

बुधवार को सरगुजा में न्यूनतम तापमान 8.9 डिग्री बलरामपुर में 10.2 डिग्री और जशपुर में 10.7 डिग्री दर्ज किया गया है। इन 3 जिलों में सर्दी और कड़ाके की ठंड के साथ ही आसपास के इलाकों में भी ठंड बढ़ गई है। रायपुर में सुबह के समय ठंड महसूस की जा रही है। दोपहर के समय धूप की वजह से ठंड कम महसूस हो रही है। लेकिन रात के तापमान में गिरावट आने लगी है। रायपुर मौसम विभाग के वैज्ञानिक जनक राम साहू ने बताया, प्रदेश में अगले 5 दिनों में न्यूनतम तापमान में कोई कास बदलाव होने की संभावना नहीं है। प्रदेश में कुछ

जगहों पर हल्की ठंडी हवाएं (शीतलहर) भी चल रही है। बुधवार को प्रदेश में सबसे अधिक तापमान दुर्ग में 28.4 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान अंबिकापुर में 8.9 डिग्री दर्ज किया गया है। गुरुवार को प्रदेश के कई जिलों में न्यूनतम तापमान 8.9 डिग्री से लेकर 14.4 डिग्री तक दर्ज किया गया है। बुधवार को रायपुर का अधिकतम तापमान 28 डिग्री और न्यूनतम तापमान 15.6 डिग्री। बिलासपुर का अधिकतम तापमान 26.4 डिग्री और न्यूनतम तापमान 14.4 डिग्री। अंबिकापुर का अधिकतम तापमान 24.01 डिग्री और न्यूनतम तापमान 8.9 डिग्री दर्ज किया गया।

# महंत रामसुंदर दास ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा

■ पत्र में लिखा- हार नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए दे रहा त्याग पत्र

**रायपुर।** विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद से राजनीतिक गलियारों में खलबली मची हुई है। वहीं, अब खबर है कि रायपुर दक्षिण से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे महंत रामसुंदर दास ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि विधानसभा चुनाव में महंत को 67 हजार से ज्यादा वोटों से हार मिली थी। इस हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है।

जानकारी के अनुसार, महंत राम सुंदर दास रायपुर दक्षिण से विधायक बृजमोहन अग्रवाल के खिलाफ चुनाव लड़े थे। लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस वजह से उन्होंने आज इस्तीफा दे दिया है। पीसीसी चीफ दीपक बैज को अपना त्यागपत्र सौंपा दिया है।

बता दें कि इससे पहले कांग्रेस के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष दिलीप षडंगी ने इस्तीफा दिया था। दिलीप षडंगी, छत्तीसगढ़ के फेमस लोक गायक हैं। षडंगी ने राज्य के कलाकारों से हाथ जोड़कर माफी भी मांगी है। अपने इस्तीफे में उन्होंने लिखा- 'कई सालों पहले अपनी नौकरी छोड़कर कांग्रेस में आया था। कलाकारों की सेवा और कलाकारों के माध्यम से कांग्रेस की सेवा करने के लिए आया था, लेकिन निवेदन करने पर उन्हें सिर्फ आश्वासन मिला।' इसलिए वे कांग्रेस से इस्तीफा दिया है।

रामसुंदर दास महंत ने इस्तीफे के बाद कहा, मैंने अपनी भावना से पार्टी को अवगत कराया है, मैं ऐसा मानता हूं कि कांग्रेस के सभी वरिष्ठ ने विश्वास करके मुझे अपना प्रत्याशी रायपुर दक्षिण विधानसभा से बनाया। सभी कार्यकर्ताओं ने एक साथ मिलकर बहुत मेहनत की, लेकिन परिणाम अप्रत्याशित रहा। बहुत लंबे वोटों के अंतर से पराजय का सामना करना पड़ा है, जिसका नैतिक जिम्मेदारी मैं स्वयं को मानता हूं। इस भावना को मैंने पार्टी को अवगत कराया है।

रायपुर दक्षिण सीट को लेकर महंत ने कहा कि पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। मुझे प्रत्याशी बनाकर चुनाव लड़ाया, परिणाम अप्रत्याशित था, इसकी नैतिक जिम्मेदारी मैं अपने आप को ही मानता हूं। हार तो हार है। हार हुई है इससे मैं आहत हूं, इसलिए मैंने त्यागपत्र दिया है।

### कांग्रेस से इस्तीफा है या राजनीतिक से इस्तीफा?

महंत ने कहा, मैं दूधाधारी मठ का सेवक हूं, मठ के साथ-साथ जनता जनार्दन का सेवा करते आया हूं। मठ के द्वारा जिन संस्थाओं से जुड़ा हूं जनहित के द्वारा कार्य किया जा रहा है। उसका विस्तार आगे चलता रहेगा। इस्तीफा देने के पहले कांग्रेस से किसी से बात हुई? इस सवाल पर महंत ने कहा, इस्तीफा देने से पहले मेरे किसी से कोई चर्चा नहीं हुई है। परिणाम को लेकर हमने आपस में चर्चा जरूर किया।

कांग्रेस का समर्पित सिपाही बनकर मैंने पूरा कार्य किया। वरिष्ठ जन भी मेरा पूरा सम्मान करते रहे जो भी दायित्व दिया जाता रहा उन सबका मैं निर्वाह किया। इस साल मुझे प्रत्याशी बनाया। हमने मेहनत किया। परिणाम पक्ष में नहीं रहा। बहुत लंबे अंतर से पराजय का सामना करना पड़ा है। इससे नैतिक जिम्मेदारी मैं लेता हूं। पार्टी में मैं सहज जुड़ा था। किसी उम्मीद के साथ नहीं गया था। दूधाधारी मठ ने मुझे बहुत कुछ दिया है। किसी चीज की कोई उम्मीद या अभिलाषा नहीं है। जन सेवा मैं कर ही रहा हूं और करता रहूंगा। अन्य पार्टी में शामिल होने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है।

### महंत को मनाने दूधाधारी मठ पहुंचे ढेबर

हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में रायपुर दक्षिण से मिली पराजय के बाद महंत रामसुंदर दास द्वारा कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद वरिष्ठ कांग्रेसजनों का दूधाधारी मठ में जमावड़ा शुरू हो गया। उन्हें मनाने के लिये महापौर एजाज ढेबर भी दूधाधारी मठ पहुंचे। महापौर ढेबर ने महंत रामसुंदर दास से बातचीत की और उनसे इस्तीफे पर चर्चा कर वापस लेने का आग्रह किया। महापौर ने कहा कि महंत जी इस्तीफे पर पुन: विचार कर रहे है। कांग्रेस के वरिष्ठ जन भी उन्हे मना रहे हैं और वे मान भी जायेगें। महापौर ने कहा कि हार का इतना बड़ा अंतर आएगा यह सोचा नहीं था उन्होंने,अगर वह हारे हैं तो हम स्वीकारते है की जनता साथ नहीं थी। महापौर ने महंत जी के साथ हुई बातचीत के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि कहा आप संघर्ष करें हम सभी आपके साथ है। इस हार से निस्संदेह उन्हे जो धक्का लगा है उससे उबरने में थोड़ा समय लग सकता है लेकिन वे अपना इस्तीफा वापस लेगें।

# जयसिंह अग्रवाल से कांग्रेस ने तीन दिन के भीतर मांगा जवाब

**रायपुर।** छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कांग्रेस सरकार के मुखिया पर गंभीर आरोप लगाए थे। इस मामले को संज्ञान में लेते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जयसिंह अग्रवाल को नोटिस जारी कर तीन दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है।

चुनाव में हार के बाद जयसिंह अग्रवाल ने कहा था कि इस चुनाव में एकजुटता नहीं थी, इस बार का चुनाव सेंट्रलाइज था। पिछले चुनाव में जो जनादेश मिला, उसका सरकार कदर नहीं कर पाई। मंत्रियों को पावर नहीं मिल पाई। एक ताकत सेंट्रलाइज होकर कुछ लोगों के साथ सरकार चलाती रही। मंत्रियों का जो जिले में प्रभाव होता है, उसे बाधित किया गया।

इतना ही नहीं जयसिंह अग्रवाल ने संगठन के सर्वे पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि, विधायकों के परफार्मेंस का सर्वे सरकार का मुखिया करवाता था। उस सर्वे पर कभी चर्चा नहीं हुई, जो फर्जी सर्वे था। आगे जयसिंह अग्रवाल ने बिना किसी का नाम लिए कहा, खेतों को सुरक्षित रखने के लिए बाड़ा बनाया जाता है। अगर वो बाड़ा ही खेत को खाए तो क्या होगा। जयसिंह अग्रवाल ने इशारों ही इशारों में हार का जिम्मेदार प्रदेश के तात्कालीन मुखिया को बताया था।

## संक्षिप्त समाचार

### अवैध तरीके से दीवार गिराने को लेकर पूर्व विधायक को थमाया नोटिस

**रायपुर।** पूर्व विधायक विनय जायसवाल को उनकी सोसायटी ने नोटिस जारी किया है। जायसवाल को अवैध तरीके से बाउंड्री गिराने के संबंध में नोटिस जारी किया है। जिस पर 15 दिनों के भीतर दीवार को वापस बहाल करने की कहा गया है। सोसायटी ने नोटिस में कहा कि मैग्नेटो सिग्नेचर होमसोसायटी चरण 1 और सेलेक्ट 22 संपत्ति में आपकी संपत्ति से सटे रू.ू।स्स्रूपरिसर की दीवार के अवैध विध्वंस के संबंध में आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए मजबूर है। यह मैग्नेटो सिग्नेचर होम्ससोसाइटी की सुरक्षा और गोपनीयता से संबंधित एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। परिसर की दीवार को गिराना सीधे तौर पर सोसायटी के नियम-कानून का उल्लंघन है। आपने कभी भी किसी भी समय सोसायटी के पदाधिकारियों से इस विषय पर चर्चा नहीं की। नोटिस में आगे कहा गया है कि जल्द से जल्द (15 दिनों के भीतर) मूल योजना के अनुसार परिसर की दीवार को बहाल करें। अन्यथा सोसायटी आपकी लागत पर काम करेगी। यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो आप हमारे संपत्ति प्रबंधक से बात करने के लिए स्वतंत्र हैं।

### प्रदेश के कई जिलों में आईटी की दबिश, इंदौर-नागपुर से पहुंचे 200 अधिकारी

**रायपुर।** आयकर विभाग ने रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग-भिलाई में छापा मारा है। इंदौर और नागपुर के करीब 200 अधिकारियों की टीम छत्तीसगढ़ में अलग-अलग जगहों में छापेमारी कर रही है। जानकारी के अनुसार रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग भिलाई के कोल्ड स्टोरेज और अनाज व्यवसायियों के ठिकानों पर टीम की छापेमारी जारी है। राधामोहन टावर के सभी अनाज व्यापारी,इसके अलावा लाल गंगा मिडॉज में व्यवसायियों के यहां आयकर की टीम पहुंची हुई है। जांच जारी है। राजधानी में समता शॉपिंग आर्केड, तेलघानी नाका चौक, सिलतरा, कुशालपुर में टीमों की जांच जारी है। समता शॉपिंग आर्केड स्थित केके एग्रो ट्रेड वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, तेलघानी चौक स्थित दाल कारोबारी मेसर्स सूरज पल्सेस, सिलतरा स्थित राजेश्वरी कोल्ड स्टोरेज के ठिकानों पर रेड जारी है। मौके पर एमपी पुलिस और सीआरपीएफ के जवान मौजूद हैं। जानकारी के मुताबिक अन्य राज्यों में रेड कार्रवाई से जुड़े तार के संबंध में यहां दबिश दी गई है।

### कमल विहार व इन्द्रप्रस्थ फेस-2 में 18 में से 14 निविदा हुई सफल

**रायपुर।** रायपुर विकास प्राधिकरण के कौशल्या माता विहार (कमल विहार) एवं इन्द्रप्रस्थ फेस-2 में आवासीय एवं व्यावसायिक भूखंड तथा एलआईजी फ्लैट्स के विक्रय के लिए बुधवार तक निविदा आमंत्रित की गई थी। कुल 18 नग निविदा प्राप्त हुई जिसमें से 14 नग निविदा सफल हुई। सफल 14 निविदा से कुल 27.09 करोड़ रूपये आर.डी.ए. को प्राप्त हुआ। इस प्रकार शासन से अनुमति प्राप्त कर बड़े प्लॉटों को छोटा कर आवासीय एवं व्यावसायिक भूखंडों की नीलामी से अब तक लगभग 88 करोड़ रूपये रायपुर विकास प्राधिकरण को प्राप्त हुए हैं। रायपुर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री धर्मेश कुमार साहू द्वारा जानकारी दी गई है कि शेष बचे आवासीय एवं व्यावसायिक भूखंड तथा फ्लैट्स विक्रय हेतु माह के चौथे बुधवार को फिर से निविदा आमंत्रित की जावेगी। निविदा द्वारा आफसेट दर से अधिक दर पर भूखंड एवं फ्लैट्स का विक्रय किया जाता है।

### गुरुकुल महिला महाविद्यालय में हुआ स्लो साइकिल रेस, शतरंज, कबड्डी का आयोजन

**रायपुर।** गुरुकुल महिला महाविद्यालय में वार्षिकोत्सव के दौरान गुरवार को खेल प्रतियोगिता के द्वितीय दिवस में स्लो साइकिल रेस, शतरंज, रस्सी दौड़ एवं कबड्डी का आयोजन हुआ। इसी तारतम्य में प्राध्यापकों के बीच भी प्रतियोगिता आयोजित की गई। एक समूह में विज्ञान विभाग के प्राध्यापक एवं दूसरे में कॉमर्स विभाग के प्राध्यापको ने इसमें भाग लिया। रिंकू पांडे ,प्रीति साहू, पूनम गोस्वामी प्राध्यापकों के मार्गदर्शन में यह प्रतियोगिता संपन्न हुआ।

# पूर्व कांग्रेस विधायक हुए लामबंद,खरगे से मुलाकात कर बतायेंगे हार की वजह

**रायपुर।** हार के बाद बढ़ता रार थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले दिनों कांग्रेस के पूर्व विधायक विनय जायसवाल और बृहस्पति सिंह को नोटिस जारी हुआ तो टिकट काटे हुए करीब दर्जन भर पूर्व विधायक लामबंद हो गए और बकायदा उन्होने एक बैठक भी कर ली है,सभी ने तय किया है कि दिल्ली जाकर पार्टी अध्यक्ष खरगे से मुलाकात करेंगे और बतायेंगे कि उनकी टिकट क्यों काटी गई और छत्तीसगढ़ में पार्टी की हार क्यों हुई। बैठक की इस खबर से कांग्रेस में खलबली मची हुई है। बैठक को हालांकि गोपनीय बताया जा रहा था लेकिन जानकारी बाहर आ गई।

जानकारी के अनुसार, कांग्रेस पार्टी ने चुनाव के समय जिन विधायकों की टिकट काट दी थी, वे सभी विधायक एकजुट होकर पूर्व विधायक विनय जायसवाल की अगुवाई में एक बैठक रखे थे, जिसमें हार को लेकर तैयार रिपोर्ट पर चर्चा की गई। चर्चा है कि पूर्व विधायक एक राय होकर राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से मुलाकात करने दिल्ली जाएंगे। मुलाकात के दौरान विधानसभा चुनाव में हुई हार पर रिपोर्ट सौपेंगे. इस संबंध में हुई बैठक में विनय जायसवाल के अलावा बृहस्पति सिंह, शिशुपाल सोरी, पद्मा मनहर, मोतीलाल देवांगन, चंद्रदेव राय, ममता चंद्राकर, अनिता शर्मा, चुन्नीलाल साहू, भुवनेश्वर बघेल, लक्ष्मी ध्रुव, प्रमोद शर्मा और गुरुदयाल बंजारे के मौजूद रहने की खबर है।

# इम्पेला प्रक्रिया से 100 प्रतिशत ब्लॉक हो चुके दिल की नसों को खोला गया

■ ऐसा करने वाला देश का पहला शासकीय संस्थान बना अम्बेडकर अस्पताल

**रायपुर।** राज्य में पहली बार इम्पेला की प्रक्रिया संपन्न हुई है। डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय में दुनिया के सबसे छोटे हृदय पम्प इम्पेला की सहायता से लगभग सौ प्रतिशत ब्लॉक हो चुके दिल की नसों को एंजियोप्लास्टी के जरिए खोला गया है। ऐसा करने वाला यह अस्पताल देश का पहला शासकीय संस्थान बन गया है।

डॉ. स्मित के अनुसार इम्पेला दुनिया का सबसे छोटा हृदय पम्प है, जो अवरूद्ध हृदय की धमनियों को खोलते समय शरीर के वाइटल आर्गन(हृदय, फेफड़ा, किडनी, लीवर एवं मस्तिष्क) को हेमोडायनामिकली रूप से स्थिर करने के काम करता है, जिससे मरीज की सफलतापूर्वक एंजियोप्लास्टी की जा सके। पूरे विश्व में तीन लाख मरीजों का इस विधि से उपचार हो चुका है और पूरे भारत में

240 मरीज का इस विधि से उपचार हुआ। एसीआई राज्य का पहला शासकीय संस्थान है, जहां इस विधि से उपचार किया गया है।

डॉ. स्मित श्रीवास्तव ने बताया कि, 50 वर्षीय एक मरीज हमारे यहां मेडिसिन विभाग में भर्ती हुआ। मरीज का ईएफ काफी कम था और हार्ट के पंप करने की क्षमता भी काफी कम थी। मैंने देखा कि नस बंद होने के कारण हार्ट फेल हो गया था, तो नस को खोलने से फायदा हो सकता था। जब देखा तो दाहिने तरफ की नस ठीक है और बायीं तरफ की मुख्य नस 100 प्रतिशत बंद थी, जिसे लेफ्ट मेन आर्टरी कहते हैं। हार्ट अटैक के कारण अब समस्या यह थी कि हार्ट का फंक्शन 15 से 20 प्रतिशत ही था। कार्डियक सर्जनों ने कहा कि बाईपास की संभावना काफी कम है। फिर मरीज का उपचार दूसरी विधि से करने की योजना बनाई, जिसमें मरीज का जब एंजियोप्लास्टी करेंगे तो हार्ट के अंदर सबमर्सिबल पंप की तरह एक छोटा डिवाइस डालेंगे, जिसे इम्पेला कहते हैं। इससे जब नसों पर काम करते रहेंगे तो हार्ट चलता रहेगा। एंजियोप्लास्टी के दौरान ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करने के लिए इस मशीन का प्रयोग करते हैं।

उन्होंने बताया कि, हृदय में एक बार स्थापित होने के बाद इम्पेला हृदय पंप चालू हो जाता है, जो बाएं वेंट्रिकल से रक्त खींचता है और इसे महाधमनी में छोड़ता है। बाएं वेंट्रिकल की यह सक्रिय 'अनलोडिंग' मस्तिष्क और अन्य महत्वपूर्ण अंगों में रक्त के प्रवाह को बढ़ाती है और मरीजों के दिल को आराम देते हुए किडनी को गंभीर चोट से बचाती है।

# हाईस्कूल एवं हायर सेकंडरी परीक्षा में छात्र-छात्राओं के आवेदन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से

**रायपुर।** छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल द्वारा आयोजित हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी परीक्षा के लिए सत्र 2023-24 से ऑनलाईन पोर्टल प्रारंभ किया जा रहा है। इस पोर्टल के माध्यम से छात्र-छात्राएं पांच चरणों में आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल द्वारा छात्र-छात्राओं को स्वयं आवेदन भरने की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए स्टुडेंट कार्नर तैयार किया गया है। इसके द्वारा निर्धारित समय-सीमा में छात्र कभी भी और कहीं से भी स्टुडेंट पोर्टल के माध्यम से परीक्षा आवेदन फार्म भर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिये छात्र-छात्रायें वेबसाइड से विवरणिका डाउनलोड कर अध्ययन कर सकते हैं।

छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल द्वारा आयोजित हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी परीक्षा हेतु परीक्षा आवेदन पत्र परीक्षार्थियों के द्वारा संबंधित अध्ययन केन्द्रों में जमा किये जाते हैं, जिसे अध्ययन केन्द्रों के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल के ऑनलाइन पोर्टल पर इन्द्राज किया जाता है एवं शुल्क बैंक

द्वारा पेमेंट गेटवे के द्वारा जमा किया जाता है।

छात्र-छात्रायें कार्यालयीन वेबसाइड https://www.sos.cg.nic.in/ के माध्यम से स्टूडेंट पोर्टल में जाकर सीधे आवेदन करेंगे, जिसमें सर्वप्रथम छात्र को अपना मोबाइल नंबर प्रविष्ट कर एवं पासवर्ड बनाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसमें मोबाइल नंबर यूजर आई.डी. होगा। रजिस्ट्रेशन के पश्चात महत्पूर्ण निर्देश दिखाई देंगे, जिसे छात्र भलीभाँति अध्ययन कर, सहमति करते ही सर्वप्रथम कक्षा हाईस्कूल-हायर सेकण्डरी जिस परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं उसका चयन करेंगे एवं जिला तथा अध्ययन केन्द्र का चुनाव करेंगे। तत्पश्चात परीक्षा के प्रकार हाईस्कूल-सामान्य, क्रेडिट, अवसर एवं श्रेणी सुधार। उसी प्रकार हायर सेकण्डरी-सामान्य, क्रेडिट, अवसर, श्रेणी सुधार, आर.टी.डी., आर.टी.डी. अवसर एवं संकाय परिवर्तन का चयन करना होगा उसके बाद सहमति प्रदान करने पर परीक्षार्थी को आवेदन फार्म दिखाई देगा।प्रथम चरण में आवेदन फार्म में छात्र को अपनी पूर्ण जानकारी प्रविष्ट करना होगा। द्वितीय चरण में आवेदन फार्म पूर्ण होने पर छात्र को अपना फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करना होगा। तीसरे चरण में एडिट का विकल्प आयेगा जिसमें छात्र अपने द्वारा भरे गये आवेदन फार्म का पुन: अवलोकन कर यदि गलत जानकारी प्रविष्ट किये है तो सुधार कर सकेंगे। चौथे चरण में शुल्क भुगतान का विकल्प आयेगा जिसमें छात्र को नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यू.पी.आई. एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से शुल्क जमा कर सकेंगे। पांचवे चरण में शुल्क की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात आवेदन फार्म प्रिंट का विकल्प आयेगा, जिसमें आवेदन फार्म की दो प्रति प्रिंट आउट निकाले जिसमें से एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखे।

# 51 कुण्डीय गायत्री महायज्ञ टिकरापारा में 15 से 18 दिसंबर तक

### दीक्षा संस्कार के साथ नि:शुल्क होगा 16 संस्कार

**रायपुर।** अखिल विश्व गायत्री परिवार शांतिकुंज हरिद्वार के संरक्षण एवं मार्गदर्शन में गायत्री प्रज्ञा पीठ संतोषी नगर रायपुर एवं रायपुर महानगर के गायत्री परिजनों के सहयोग से 15 से 18 दिसम्बर तक दशहरा मैदान छत्तीसगढ़ नगर टिकरापारा में 51 कुण्डीय गायत्री महायज्ञ एवं प्रज्ञा पुराण, विविध संस्कार एवं दीपयज्ञ व साहित्य एवं सप्तसूत्रीय आंदोलन पर विशाल प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान दीक्षा संस्कार के अलावा 16 संस्कार निःशुल्क कराया जाएगा जिसके लिए अग्रिम पंजीयन कराना आवश्यक होगा।

पत्रकारों से चर्चा करते हुए समिति के संयोजक राकृष्ण अग्रवाल, सीपी अग्रवाल, जिला समन्वयक लच्छूराम निषाद, मीडिया प्रभारी प्रदीप साहू, हीरालाल साहू, बंटीराम साहू ने संयुक्त पत्रकारवार्ता में बताया कि 15 दिसंबर 2023 को प्रथम दिवस में दोपहर 01 बजे से सद्गुरू ज्ञान गंगा, सदग्रंथ शोभा यात्रा मंगल जल-कलश यात्रा निकलेगी। द्वितीय दिवस दिनांक 16 दिसम्बर को प्रात: 06 बजे से ध्यान योग, प्रज्ञा योग प्रात: 08.30 बजे देव पूजन एवं 51 कुण्डीय गायत्री महायज्ञ दोपहर 01 बजे भोजन प्रसाद दोपहर 2.30 बजे से कार्यकर्ता गोष्ठी दोपहर 03 से 05.30 बजे तक प्रज्ञा पुराण कथा शाम 05.30 सक

07.30 बजे तक 1 नारियों जागों स्वयं को पहचानों पर प्रवचन होगा। तृतीय दिवस दिनांक 17 दिसम्बर को प्रात: 06 बजे से ध्यान योग, प्रज्ञा योग प्रात: 08.30 बजे 51 कुण्डीय गायत्री महायज्ञ एवं विभिन्न संस्कार दोपहर 01 बजे भोजन प्रसाद दोपहर 2.30 बजे से व्यसन मुक्ति पर युवा कार्यकर्ता गोष्ठी दोपहर 03 से 05.30 बजे तक प्रज्ञा पुराण कथा शाम 05.30 तक 07.30 बजे तक राष्ट्र समर्थ एवं सशक्त कैसे बने पर प्रवचन होगा एवं इसके उपरांत दीप यज्ञ होगा। चतुर्थ दिवस दिनांक 18 दिसम्बर को प्रात: 06 बजे से ध्यान योग, प्रज्ञा योग प्रात: 08.30 बजे से 02 बजे तक 51 कुण्डीय गायत्री महायज्ञ विभिन्न संस्कार एवं पूर्णाहुति तथा परम वंदनिया माताजी भगवती देवी शर्मा की जन्म शताब्दी के लिये संकल्प व बिदाई होगी।

# सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका

■ एक लाख रुपए का जुर्माना भी ठोका

**नई दिल्ली/रायपुर।** कोयला लेव्ही के मामले में सालभर से जेल में निरुद्ध सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक लाख रुपया का जुर्माना भी लगाया।

जानकारी के अनुसार, सौम्या चौरसिया के अधिवक्ताओं ने कोर्ट में ईडी की कार्यवाही के विधिक अधिकारों को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत में पेश याचिका में कहा है कि याचिकाकर्ता महिला है, और उसके छोटे बच्चे हैं। मामले की सुनवाई में लंबा समय लगना है, इसलिए उसे ज़मानत दी जाए। इसके पहले हाईकोर्ट सौम्या चौरसिया की ज़मानत याचिका ख़ारिज कर चुका है।

बता दें कि भूपेश सरकार में सौम्या चौरसिया की गिनती सबसे ताक़तवर अधिकारी रही हैं। राज्य प्रशासनिक सेवा की अधिकारी सौम्या चौरसिया भूपेश बघेल सरकार में सीएम सचिवालय में उप सचिव पद पर पदस्थ थीं। कोल लेव्ही के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने

सौम्या चौरसिया को 2 दिसंबर 2022 को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से लगातार सेंट्रल जेल रायपुर में निरुद्ध है।

### सौम्या चौरसिया पर गंभीर आरोप

प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार, छत्तीसगढ़ में कोयला ट्रांसपोर्टिंग में 25 रुपए टन की लेव्ही वसूली की जाती थी। लेकिन भूपेश बघेल सरकार ने लेव्ही वसूली के लिए नियमों को परिवर्तित किया गया था। इसका फायदा माफिया ने उठाया, जिसका किंगपिन सूर्यकांत तिवारी था, ईडी के अनुसार, सूर्यकांत तिवारी को यह असीमित शक्ति और प्रभाव भूपेश बघेल सरकार की ताकतवर अधिकारी सौम्या चौरसिया से हासिल होते थे।

### पांच सौ करोड़ का स्कैम

ईडी ने मामले में सौम्या चौरसिया के अलावा सूर्यकांत तिवारी, कोल वाशरी संचालक सुनील अग्रवाल, आईएएस समीर बिश्नोई, आईएएस रानू साहू, समेत अन्य को अलग-अलग तारीख़ों पर गिरफ्तार किया था। ईडी का आरोप है कि यह स्कैम क़रीब पांच सौ करोड़ रुपए का था। इस लेव्ही से हासिल राशि से चल-अचल संपत्तियां अर्जित की गईं, जिनमें कई बेनामी भी हैं।

# रानू साहू की याचिका पर सुनवाई की नई तारीख 8 जनवरी

**रायपुर।** छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में गुरुवार को कोयला घोटाला कांड में निलंबित चल रही आईएएस रानू साहू की जमानत याचिका पर आज सुनवाई पूरी नहीं होने पर न्यायालय ने 8 जनवरी को सुनवाई की अगली तारीख मुकर्रर की है। उल्लेखनीय है कि पिछले साल अक्टूबर में ईडी ने छत्तीसगढ़ में कई अफसरों और कारोबारियों के घर-दफ़्तर पर छापामारी की थी और आरोप लगाया था कि राज्य में एक संगठित गिरोह कोयला परिवहन में 25 रुपए प्रति टन की वसूली कर रहा है। ईडी के दस्तावेज़ों की मानें तो 15 जुलाई 2020 को इसके लिए सरकारी अधिकारियों ने एक सोची-समझी नीति के तहत आदेश जारी किया और उसके बाद ही अवैध वसूली का सिलसिला शुरू हुआ। ईडी के अनुसार, इस घोटाले में कई कारोबारी, कांग्रेस पार्टी के नेता और अफ़सर शामिल थे और उन्होंने अब तक इस तरीक़े से 540 करोड़ रुपए से अधिक की रक़म अवैध तरीक़े से वसूली की। अदालत में प्रस्तुत दस्तावेज़ों में ईडी ने दावा किया है कि उसने इस संबंध में बड़ी संख्या में डायरी, फ़ोन चैट, लेन-देन के सबूत, करोड़ों रुपए नक़द, सोना, अरबों रुपए की संपत्ति के ब्यौरे और दूसरे दस्तावेज़ जब्त किए।

## नए सीएम के जरिये भाजपा ने दिया संदेश

**विजय विद्रोही**

मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भाजपा आलाकमान अपने हिसाब से बदलाव कर सका क्योंकि उसे चुनौती देने वाला कोई नहीं था। थोड़ा-बहुत डर राजस्थान में था, लेकिन वहां भी उसकी हनक और धमक के आगे किसी की नहीं चली। आलाकमान ने बदलाव इसलिए किया क्योंकि उसे लोकसभा चुनाव जीतना है और अगले दस सालों के लिए नई भाजपा गठित करनी है। लोकसभा चुनावों को देखते हुए जातिगत समीकरण नए सिरे से तराशने की कोशिश की गई है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री आदिवासी समुदाय से हैं। दो उपमुख्यमंत्रियों में एक सवर्ण और एक ओबीसी हैं। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री ओबीसी के बनाए गए तो उप-मुख्यमंत्रियों में एक सवर्ण और एक दलित समुदाय के। इसी तरह राजस्थान में मुख्यमंत्री ब्राह्मण को बनाया गया तो दो उपमुख्यमंत्रियों में राजपूत और दलित चेहरा सामने रखा गया। तीनों राज्यों में सिर्फ राजस्थान है, जहां एक महिला को भी प्रमुख जिम्मेदारी दी गई। जिस राज्य में भाजपा की झोली में वोट डालने वाली जातियों की जितनी संख्या रही, उसे देखते हुए सत्ता में भागीदारी दी गई है। साफ है कि जातीय समीकरणों के लिहाज से देखा जाए तो ये नाम हैरान नहीं करते। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भाजपा तीनों राज्यों की 65 में से पिछली बार की तरह 62 सीटें जीत पाएगी, जिसके लिए सारी कसरत की गई है। मुख्यमंत्री ऐसे बनाए गए हैं, जिनकी हिंदुत्व में पूरी आस्था है। वे संघ की शाखाओं से निकले हैं। एबीव्हीपी में ट्रेनिंग हासिल कर चुके हैं। ऐसे मुख्यमंत्री कम से कम अपने पहले कार्यकाल में लो प्रोफाइल रहेंगे। वे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के हिसाब से काम करेंगे। वहीं, मुख्य चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने रहेंगे। पार्टी का सारा ध्यान इस बीच समर्पित वोट बैंक को बनाए रखने के साथ फ्लोटिंग युवा वोटर में सेंधमारी पर रहेगा। ध्यान रहे, तीनों राज्यों में भाजपा जीती जरूर, लेकिन कांग्रेस का वोट बैंक कम नहीं हुआ। कुछ जगहों पर तो यह बढ़ा ही है। ऐसे में भाजपा आलाकमान समझ गया है कि वोट बैंक का विस्तार हिंदुत्व या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से नहीं हो सकता। लाभार्थी और युवा वोटरों के हाथों में सत्ता की चाबी है। पीढ़ी परिवर्तन करके नए चेहरों के जरिए लाभार्थी और युवा वोटरों से नया करार करने की यह कोशिश है। मध्य प्रदेश में ओबीसी की जगह ओबीसी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। ऐसा यादव मुख्यमंत्री जो बिहार, यूपी, हरियाणा और राजस्थान के यादवों को भी अपील करे। भाजपा आलाकमान यादव वोट का तोड़ निकालने में पहले से ही लगा है। मोदी सरकार में इस समय भूपेंद्र यादव, राव इंद्रजीत सिंह, नित्यानंद राय और अन्नपूर्णा यादव चार मंत्री हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज अहीर भी महाराष्ट्र के यादव हैं। क्या अखिलेश यादव और लालू-तेजस्वी यादव के वोट बैंक में भाजपा की यह यादव बिग्रेड सेंध लगा पाएगी? यह देखना दिलचस्प रहेगा। राजस्थान में 1990 के बाद पहली किसी ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाया गया है। भाजपा को हिंदुत्व के मुद्दे को उभारना है। यहां सवर्ण जाति का वोट तो उसे मिलता ही रहा है, लेकिन पावर शेयरिंग में हिस्सेदारी कम होने की शिकायत भी यह वर्ग करता रहा है। देखना होगा कि तीनों राज्यों में एक मुख्यमंत्री और दो उप-मुख्यमंत्री पद ब्राह्मण समुदाय को देकर भाजपा यूपी, बिहार के सवर्ण वोटरों को खुश करने में कामयाब होती है या नहीं। आरोप है कि मोदी की भाजपा इंदिरा गांधी की कांग्रेस जैसी हो गई है। लेकिन अगर ऐसा करके इंदिरा गांधी की तरह लंबे समय तक सत्ता में रहा जा सकता है तो इसमें हर्ज ही क्या है? कांग्रेस ने स्थानीय क्षत्रपों पर भरोसा करते हुए कर्नाटक जरूर जीता, लेकिन राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में हार गई। भाजपा आलाकमान समझ गया है कि स्थानीय क्षत्रपों के बेकाबू होने पर उन्हें संभाल पाना मुश्किल हो जाता है। इंडिया मोर्चे की तरफ से जातीय जनगणना को चुनावी धार दी जा रही है। भले ही विधानसभा चुनावों में यह मुद्दा बहुत ज्यादा नहीं चला। फिर भी लोकसभा चुनाव में विपक्ष इसे नजरंदाज नहीं करेगा। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने चरणबद्ध तरीके से इसकी काट तलाशनी शुरू की।

# जीत से ज्यादा मुख्यमंत्रियों के चयन की चर्चा

**संजय तिवारी**

छत्तीसगढ, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भाजपा द्वारा जिन तीन मुख्यमंत्रियों के नामों की घोषणा की गयी है अगर उसका विश्लेषण करना हो तो बड़े से बड़ा राजनीतिक पंडित इस बात का विश्लेषण नहीं कर सकता कि इनको चुनने का आधार क्या है? मसलन, क्या तीनों राज्यों में सिर्फ जातीय समीकरण साधा गया है? नहीं। क्या तीनों राज्यों में बड़े जनाधार वाले नेताओं को महत्व दिया गया है? नहीं। क्या संघ से संबंध इन्हे चुनने का आधार है? नहीं। चुनावी विश्लेषक अपनी अपनी समझ के अनुसार कोई न कोई आधार खोज ही लेंगे लेकिन असल में सीएम चुनने का आधार क्या है इस गुत्थी को समझ पाना असंभव है। आप जितना अनुमान लगाने की कोशिश करेंगे उतना उलझते जाएंगे कि आखिर इन तीनों राज्यों में किस फार्मूले के तहत सीएम नियुक्त किये गये हैं।

ऐसा लगता है कि सारे आधार दरकिनार करके सिर्फ एक आधार देखा गया। वह यह कि जो भी स्थापित नेता हैं उन्हें छोड़कर किसी ऐसे को बना देना है जिसका नाम सुनकर लोग भौचक्के रह जाएं। गूगल पर सर्च करने पर भी लोगों को पता न चले कि ये आखिर हैं कौन? हर एक के मन में बस एक सवाल आये कि अरे इनको सीएम बनाया तो क्यों बनाया? अब प्रधानमंत्री मोदी के हर काम को मास्टरस्ट्रोक कहनेवाले समर्थक सक्रिय होंगे और वो भांति भांति के तर्कों से समझाएंगे कि ऐसा करना क्यों जरूरी था। जहां तक शीर्ष नेतृत्व यानी मोदी और शाह का सवाल है तो वह तो कभी बतानेवाले नहीं कि उन्होंने ये किया तो क्यों किया? हां, इतना जरूर हुआ है कि तीनों राज्यों में जीत से भाजपा कार्यकर्ता जितने उत्साहित थे, जैसे जैसे मुख्यमंत्रियों के नाम की घोषणा होती गयी उनका उत्साह ठंडा पड़ता गया। भाजपा का कोई सामान्य कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर दिखावटी खुशी भी नहीं मना पा रहा है। मानों दिसंबर के सर्द मौसम में सबके मन पर घड़ों पानी पड़ गया हो।

फिर भी मोदी ने संसद भवन में खड़े होकर कभी कहा था कि मुझे और कुछ आये न आये राजनीति करना आता है। 2001 से 2023 तक की उनकी राजनीतिक सफलता देखकर इस पर भरोसा भी होता है कि गुजरात के सीएम रहते हुए उन्होंने कैसे देश के पीएम बनने का सफर पूरा किया। सीएम थे तो देश के सबसे पॉपुलर लीडर बने और पीएम बने तो दुनिया के सबसे पॉपुलर लीडर बन गये। उनकी सफलता बताती है कि उन्होंने राजनीति की जो स्क्रिप्ट लिखी उस पर बनी फिल्म सुपर डुपर हिट हुई। फिर कोई उनके निर्णयों पर शंका करे भी तो कैसे? लेकिन उनकी राजनीतिक सफलता की इस दो दशक की यात्रा में उनके काम करने की शैली हमेशा से चौंकानेवाली ही रही है। वो अपने काम काज और निर्णयों से हमेशा चौंकाते हैं। मोदी के जिन कामों को देखकर जनता चौंकती है, असल में उसे पूरी तैयारी के साथ किया जाता है। उनके निर्णय रातों रात नहीं होते, लेकिन जब सामने आते हैं तो सबको चौंका देते हैं। लेकिन तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नाम सामने आने के बाद इस संभावना को भी बहुत बल नहीं मिलता कि चुनाव से पहले ही उन्होंने अपने मन में मुख्यमंत्रियों के नाम फाइनल कर लिये होंगे।

मसलन छत्तीसगढ नया राज्य बना तो दिलीप सिंहजूदेव का नाम तय था मुख्यमंत्री बनने के लिए। लेकिन रमन सिंह मुख्यमंत्री बने तो 15 सालों में अपने आपको स्थापित कर लिया। छत्तीसगढ के आदिवासी समाज में जहां न अखबार, टीवी पहुंचता है और न इंटरनेट, वहां भी वो चाउरवाले बाबा के नाम से पहचाने जाते हैं। हालांकि वो खुद एक्सीडेन्टल सीएम थे क्योंकि 2003 में ऐन मौके पर दिलीप सिंहजूदेव भ्रष्टाचार के एक मामले में फंस गये थे और उनकी जगह अटल सरकार में राज्यमंत्री रमन सिंह को सीएम बनाने का निर्णय हुआ। पंद्रह साल सीएम रहते हुए उन्होंने न सिर्फ बीजेपी को जीत दिलाई बल्कि अपनी पहचान भी बनायी। इसके बावजूद उन्हें इस बार सीएम नहीं बनाया गया। राजनीतिक विश्लेषक समझा रहे हैं कि छत्तीसगढ में आदिवासी मुख्यमंत्री देकर बीजेपी ने आदिवासी बहुल सीटों पर लोकसभा में अपना दावा मजबूत किया है। लेकिन सवाल यह है कि फिर अब तक आदिवासी किस आधार पर भाजपा को वोट देते आये थे? इस बार भी अगर आदिवासी बहुल सीटों पर जीत मिली तो क्या इसलिए कि उन्हें पता था कि चुनाव के बाद उनका अपना सीएम बननेवाला है? यहां एक बात जो कोई विश्लेषक नहीं बतायेगें वह यह कि बहुसंख्यक आदिवासी जाति देखकर वोट नहीं करते। सामाजिक संबंधों में अपने समाज तक बंधे रहनेवाले आदिवासी राजनीति में जातिवाद से लगभग मुक्त समाज है। उनकी ऐसी छवि बनाना उनका अपमान करने जैसा है।

इसी तरह मध्य प्रदेश में मामा शिवराज को सब सीएम मानकर ही चल रहे थे। जिन्हें आशंका भी थी तो नरेन्द्र सिंह तोमर, प्रह्लाद पटेल या फिर कैलाश विजयवर्गीय के नामों का अनुमान लगा रहे थे। लेकिन छत्तीसगढ के बाद अब चौंकने की बारी मध्य प्रदेश में थी। वहां एक सीएम और दो डिप्टी सीएम का फार्मूला अपनाया गया। जिन मोहन यादव के नाम की घोषणा हुई शायद खुद उन्हें भनक नहीं थी कि वो सीएम बनने जा रहे हैं, इसलिए विधायक दल की बैठक में वो पिछली कुर्सी पर बैठे थे। लेकिन चौंकानेवाले निर्णय तो सबको चौंकाते ही हैं। मोहन यादव को भी चौंकाया। साथ में दो डिप्टी सीएम भी बना दिये गये जिसमें एक दलित और एक ब्राह्मण है। विश्लेषक समझा रहे हैं कि इस तरह जातीय समीकरण के अनुसार देखें तो मोदी शाह ने मध्य प्रदेश में ओबीसी, दलित और ब्राह्मण तीनों को साध लिया है। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि इसकी जरूरत थी क्या? इस तरह के जातीय विभाजन पर अगर चुनाव हुआ होता तो भला बीजेपी को 48.5 प्रतिशत वोट किस आधार पर मिल गया? चुनाव से पहले इस तरह का जातीय वर्गीकरण तो भाजपा ने किया नहीं था। जिसने भी वोट दिया उसने किसी और कारण से वोट दिया। फिर वह कारण मोदी का नाम हो, शिवराज का काम हो या फिर कमल निशान हो। फिर भी अगर ओबीसी, दलित, ब्राह्मण का फार्मूला ही लागू करना था तो शिवराज के साथ भी दो उपमुख्यमंत्री बनाकर लागू किया जा सकता था। आखिरकार वो भी तो ओबीसी समुदाय से ही आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ ये समझना बहुत आसान भी है और बहुत कठिन भी।

दो राज्यों में चौंकते चौंकते अब चौंकने की बारी राजस्थान में थी। मध्य प्रदेश की तरह ही राजस्थान में जितने नामों का अनुमान लगाया गया उसमें से कोई सीएम नहीं बना। सीएम बने भजनलाल शर्मा जिनका अपना खुद का कोई पुख्ता पोलिटिकल प्रोफाइल नहीं है। उनके बारे में सबसे ज्यादा गूगल पर सर्च किया गया लेकिन गूगल भी उनके बारे में कुछ खास नहीं बता पा रहा है। वसुंधरा राजे से मोदी शाह की अनबन पुरानी है। इसलिए इस बात की आशंका तो कई लोगों को थी कि हो सकता है मोदी शाह वसुंधरा को सीएम न बनने दें। परंतु उनके अलावा जिन नामों का अनुमान लगाया जा रहा था, उसमें से किसी को सीएम नहीं चुना गया। अगर मध्य प्रदेश के जातीय तर्क के आधार पर राजस्थान को भी देखें तो राजस्थान में ब्राह्मण प्रदेश अध्यक्ष पहले से था। राज्यपाल भी संयोग से ब्राह्मण है। अब ब्राह्मण सीएम भी बन गया। तब सवाल उठता है कि अगर छत्तीसगढ और मध्य प्रदेश में इतना जातीय गणित साधा गया तो राजस्थान में ऐसा क्यों नहीं किया गया? अगर ब्राह्मण मुख्यमंत्री देकर ही राजनीतिक समीकरण साधना था तो उसके लिए राजस्थान से बेहतर जगह मध्य प्रदेश थी। खैर, विश्लेषक एक बार फिर समझा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में यादव और राजस्थान में ब्राह्मण सीएम देकर पड़ोसी राज्यों को संदेश दिया गया है। ये राजनीतिक विश्लेषकों की अपनी समझ तो हो सकती है लेकिन एक राज्य के चुनाव से किसी दूसरे राज्य को संदेश दिया नहीं जाता। दिया भी जाए तो वह जाता नहीं। हर राज्य की राजनीतिक-सामाजिक परिस्थिति अलग होती है और राज्यों के चुनाव उसी राज्य को साधने के लिए ही होते हैं, किसी और राज्य के लिए नहीं। इसलिए ऐसे विश्लेषण भी किसी ठोस नतीजे पर पहुंचने में मदद नहीं कर सकते।

महाराष्ट्र के बाद अब इन तीन राज्यों में भाजपा द्वारा जिन नामों को सीएम के लिए नामित किया गया उन्हें खुद इस बात का भरोसा शायद न रहा हो कि वो सीएम बनने लायक हो गये हैं। लेकिन निर्णय जब चौंकाने के लिए लिये जाते हैं तब सिवाय चौंक जाने के उसका कोई निहितार्थ होता भी नहीं है। तीनों राज्यों में सीएम के नाम सुनकर लोग चौंक गये, यही चौंक जाना ही इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के चयन का सबके पुख्ता आधार जान पड़ता है। हां, ऐसी परिस्थितियों में मोदी समर्थकों के पास पहले से एक जवाब हमेशा तैयार रहता है जो आज भी दिया ही जाएगा। मोदी जी ने किया है तो कुछ सोचकर ही किया होगा, क्या हम राजनीति को मोदीजी से ज्यादा समझते हैं?

**भारतीय ज्ञान परंपरा....**

## यागचूडामण्युपनिषद् (भाग-12)

**गतांक से आगे...**

प्राणायाम में सर्वप्रथम इड़ा नाड़ी अर्थात् बायें स्वर से श्वास खींचे (पूरक करे)। पुनः पिंगला नाड़ी अर्थात् दायें स्वर से श्वास का रेचन करे (पुनः इसके विपरीत करें)। इस प्रकार प्राणायाम करते समय चन्द्र और सूर्य दोनों का पूर्व वर्णित तरीके से ध्यान का अभ्यास करने पर मात्र दो महीने में नाड़ीशोधन हो जाता है।

नाड़ीशोधन प्राणायाम करने से नाड़ी शुद्ध होने पर वायु को यथेष्ट धारण करने की क्षमता प्राप्त हो जाती है तथा आरोग्य के लाभ के साथ जठराग्नि प्रबल हो जाती है और दिव्यनाद सुनाई पड़ने लगता है। प्राणायाम में कुंभक की स्थिति में जब तक वायु भीतर रुकी रहे, तब तक अपान वायु को भी रोके रखे। इस प्रकार हृदयाकाश में एक श्वास की मात्रा ऊपर और नीचे गमनशील होती है। प्राणायाम की पूरक, कुम्भक और रेचक ये तीनों क्रियाएँ साक्षात् प्रणव का ही रूप हैं (इस चिन्तन के साथ) द्वादश मात्रायुक्त प्राणायाम करना चाहिए। सूर्य और चन्द्र का यह द्वादश मात्रा वाला प्राणायाम साधक के सभी दोषों को समाप्त कर देता है। पूरक में द्वादश मात्रा, कुम्भक में षोडश मात्रा और रेचक में दस मात्रा के प्राणायाम को ओंकार प्राणायाम कहा जाता है। यह प्राणायाम द्वादश मात्रा का सामान्य कोटि का, इससे दुगुनी मात्रा का मध्यम स्तर का और उसकी तिगुनी अर्थात् छत्तीस मात्रा का प्राणायाम उत्तम कोटि का होता है। अधम अर्थात् सामान्य प्राणायाम पसीना लाने वाला होता है, मध्यम प्राणायाम में शरीर काँपने लगता है। तथा उत्तम कोटि के प्राणायाम में शरीर आसन से ऊपर उठने लगता है, इसलिए इसी तरह का प्राणायाम करना चाहिए। योग का अभ्यास करने के लिए एकान्त में बद्धपद्मासन लगाकर बैठे और शिवस्वरूप गुरु को नमस्कार करके नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। **क्रमशः...**

## सरदार वल्लभभाई पटेल

**अनन्या मिश्रा**

सरदार वल्लभ भाई को हम सभी लौहपुरुष के नाम से भी जानते हैं। वह भारत के पहले गृहमंत्री थे। देश की आजादी के बाद देशी रियासतों का एकीकरण कर अखंड भारत के निर्माण में वल्लभ भाई पटेल ने जो भूमिका निभाई उसको भुलाया नहीं जा सकता है। गुजरात के नाडियाद में 31 अक्तूबर 1875 को वल्लभभाई पटेल का जन्म हुआ था। वहीं देश की एकता में उनके योगदान के लिए 31 अक्तूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने साल 1897 में 22 साल की उम्र में मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली थी।

वल्लभभाई पटेल ने इंग्लैंड से वकालत की पढ़ाई की थी। इसके बाद साल 1913 में वह भारत वापस आ गए। फिर उन्होंने अपनी वकालत को यहीं पर जमाया। बता दें कि सरदार पटेल महात्मा गांधी के सत्याग्रह से काफी प्रभावित थे। साल 1918 में सूखे की वजह से गुजरात के खेड़ा में किसान कर देने में असमर्थ हो गए। ऐसे में किसानों पर लगे करों से राहत की मांग की गई। लेकिन अंग्रेज सरकार ने कर से राहत देने से इंकार कर दिया। तब पटेल ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में खेड़ा में सत्याग्रह की अगुवाई की। पटेल के नेतृत्व में किसानों की मांग के आगे अंग्रेज सरकार को भी झुकना पड़ा और अंग्रेज सरकार को करों में राहत देनी पड़ी।

देश की आजादी के बाद 562 रियासतों में बटे संघ को एकीकृत करना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। हांलाकि देश के गृहमंत्री होने के नाते सरदार पटेल ने यह जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। सरदार पटेल ने जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद को छोड़कर सभी रियासतों का भारत में विलय करवा दिया। बाद में जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर भारत में विलय कराने का कारनामा भी पटेल की वजह से संभव हो पाया। यह इतिहास की पहली ऐसी घटना साबित हुई, जब बिना किसी दंगे या खून की एक बूंद भी बहे बिना सभी रियासतों का भारत में विलय करवा दिया गया। हांलाकि हैदराबाद रियासत का विलय करवाने के लिए पटेल को सेना भेजनी पड़ी थी। जिसके बाद हैदराबाद के निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया था।

सरदार वल्लभभाई पटेल की अद्भुत कूटनीति कौशल और नीतिगत दृढ़ता की वजह से महात्मा गांधी ने उन्हें लौहपुरुष कहा था। सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। क्योंकि बिस्मार्क ने भी जर्मन साम्राज्य की स्थापना में अहम भूमिका निभाई थी। इन्ही सब गुणों को देखकर पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा गया।

15 दिसंबर 1950 को दिल का दौरा पड़ने के कारण सरदार वल्लभ भाई पटेल बेहोश हो गए। करीब 4 घंटे बाद जब वह होश में आए तो उन्होंने थोड़ा सा पानी मांगा। जिसके बाद मणिबेन ने उनको गंगाजल में शहद मिलाकर चम्मच से पिलाया और सरदार पटेल ने सदा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह दिया।

# पाकिस्तान को भारी पड़ी तालिबान से यारी

**हर्ष वी. पंत**

अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते पहले ही उलझे हुए थे, मगर पिछले कुछ महीनों में ये रसातल में चले गए हैं। अक्टूबर में पाकिस्तान ने कहा कि जो लोग वैध दस्तावेजों के बगैर रह रहे हैं, वे खुद लौट जाएं। अगर वे नहीं जाते हैं तो 1 नवंबर के बाद उन्हें जबरन अपने-अपने देश भेजा जाएगा। पाकिस्तान में अवैध रूप से रहने वालों में सबसे ज्यादा अफगानी ही हैं। इस फैसले के पीछे इस्लामाबाद ने जो मजबूत इरादा दिखाया, वह अभूतपूर्व था। बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान ने सिर्फ यही फैसला नहीं लिया। इसके साथ ही उसने तस्करी बैन करने के लिए अफगान ट्रांजिट व्यापार समझौते पर भी प्रतिबंध लगा दिया। काबुल पर तालिबान के कब्जे के दो साल के अंदर पाकिस्तान को अफगानिस्तान की ओर से सुरक्षा या रणनीतिक फायदा मिलने की उम्मीद खत्म हो चुकी है।

अगस्त 2021 से ही तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) पाकिस्तान को टारगेट कर रहा है। 2022 में टीटीपी कुल 262 आतंकवादी हमलों के लिए जिम्मेदार था। अगस्त 2021 से हुए आतंकी हमलों में 2867 पाकिस्तानी मारे गए हैं। टीटीपी और पाकिस्तानी सेना के बीच झड़पें भी बढ़ गई हैं। टीटीपी अफगानी तालिबान का वफादार है। वह करीब डेढ़ दशक से पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है। दोहा में शांति समझौते के बाद 2020 में उसने फिर सिर उठाया। तबसे पाकिस्तान में इसकी हरकतें कई गुना बढ़ गई हैं। दरअसल, टीटीपी से अपने मजबूत ऐतिहासिक और वैचारिक समानता के चलते तालिबान उसे नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता।

तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा करने के बाद टीटीपी और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता के प्रयास किए, लेकिन इनका कोई फल नहीं निकला। तालिबान ने टीटीपी के हमलों में किसी तरह की भागीदारी से इनकार किया। उसने टीटीपी को पाकिस्तान की अंदरूनी समस्या कहा। कुछ महीनों से पाकिस्तान में सीमा पार हमले काफी बढ़े हैं। इस्लामिक देशों के नेता पाकिस्तान की चिंता को दूर करने और सहमति बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर पाकिस्तान का रुख सख्त बना हुआ है। अक्टूबर में एक सीनियर पाकिस्तानी डिप्लोमैट ने यह भी बताया कि कैसे अफगानिस्तान में शांति आने से पाकिस्तान को इसका कोई फायदा नहीं मिला। पाकिस्तान के अंतरिम प्रधानमंत्री ने दोनों देशों को मिलकर काम करने की जरूरत पर इस्लामिक अमीरात के कार्यवाहक प्रधानमंत्री को भी लिखा, और दोहा समझौते के उल्लंघन के बावजूद टीटीपी को मिल रहे तालिबानी समर्थन पर विचार करने की अपील की। शरणार्थियों की जबरन वापसी का फैसला तालिबान को कार्रवाई के लिए पाकिस्तान की ओर से दिया गया आखिरी मौका माना जा रहा है।

पाकिस्तान में 40 लाख विदेशियों में से लगभग 38 लाख अफगानी हैं। इनमें से लगभग 17 लाख अवैध रूप से देश में रह रहे हैं। ताजा फैसले का ऐलान करते हुए पाकिस्तान के गृहमंत्री ने 2023 में देश में हुए 24 आत्मघाती बम विस्फोटों में 14 अफगान नागरिकों की भूमिका बताई। पाकिस्तानी पीएम ने फैसले को अफगान तालिबान के असहयोग से भी जोड़ा। पाकिस्तान ने व्यापार की सुविधा को आतंकवाद के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई से जोड़ने की भी कोशिश की है। तालिबान ने इन फैसलों को 'एकतरफा', 'अनुचित' और 'अमानवीय' बताया है और पाकिस्तान के खिलाफ बदले की कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। जाहिर है, इससे क्षेत्र में मानवीय स्थिति और खराब हो जाएगी। अफगान शरणार्थी असहज स्थिति में पड़ गए हैं। पाकिस्तान में उनके हालात पहले से ही अच्छे नहीं थे। अफगानिस्तान लौटने के लिए मजबूर होने या पाकिस्तान में हिरासत में लिए जाने के जोखिम ने उनकी मुसीबत बढ़ा दी है।

अफगानिस्तान पहले से ही खाने-पीने के सामनों की किल्लत से जूझ रहा है और अंतरराष्ट्रीय मदद के बावजूद वहां भुखमरी की बातें सामने आई हैं। कुछ समय पहले आए भूकंप ने भी वहां इस त्रासदी को बढ़ाया है। ऐसे में पाकिस्तान से लौटने वाले शरणार्थियों की वजह से उसकी मुश्किलें और बढ़ेंगी। रोजाना लगभग 9,000-10,000 शरणार्थी सीमित सामान और नकदी के साथ ट्रकों में बैठकर अफगानिस्तान आ रहे हैं। हालांकि तालिबान ने भोजन, आश्रय और स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ राहत कैंप बनाने का दावा किया है, लेकिन इसे लेकर चिंताएं बनी हुई हैं। कुछ शरणार्थियों को तालिबान की ओर से जवाबी कार्रवाई का भी खतरा है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने तालिबान को उनके और टीटीपी के बीच किसी एक को चुनने का ऑप्शन दिया है। जैसे-जैसे पाक तालिबान पर टीटीपी और बाकी आतंकवादी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई के लिए प्रेशर बढ़ा रहा है, उसकी दोहरी नीति ही उसे दिक्कत देने लगी है। यह कोई छुपी हुई बात नहीं है कि वह खुद भी अभी तक चरमपंथी संगठनों का समर्थन करता रहा है। जाहिर है, शरणार्थियों के निकाले जाने का प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और अफगान आबादी में पाकिस्तान के बारे में और भी नकारात्मक धारणाएं बनेंगी।

## आज का इतिहास

2005 2005 अटलांटिक पावर आउटेज शुरू किया गया।
2007 पाकिस्तान में आपातकालीन नागरिक क़ानून लागू।
2010 घाना ने तीन साल पहले एक अपतटीय तेल क्षेत्र की खोज के बाद तेल पंप करना शुरू किया।
2010 तिब्बत की गैलोंगला सुरंग, जो 3,750 मीटर की ऊंचाई पर बनी है, पूरी हो गई है, जो मेडोग काउंटी को बाहरी दुनिया से जोड़ती है।
2010 आयरलैंड गणराज्य को 22.5 बिलियन यूरो का ऋण अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा स्वीकृत है।
2010 लगभग 90 शरण चाहने वालों की एक नाव, ज्यादातर इराक और इरान से, चट्टानों में दुर्घटनाग्रस्त हो गई और क्रिसमस द्वीप, ऑस्ट्रेलिया के तट पर डूब गई, जिसमें 48 लोग मारे गए।
2011 अमेरिकी जनगणना के अनुसार, 2 लोगों में से 1 को कम आय या गरीब माना जाता है।
2011 फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति जैक्स शिराक को पेरिस के मेयर के रूप में सेवा करते हुए पार्टी के सदस्यों के साथ गैर-मौजूद नौकरियों को भरने के लिए गबन और उल्लंघन का दोषी घोषित किया जाता है।
2011 अमेरिकी सीनेट और प्रतिनिधि सभा द्वारा एक बजट समझौता किया जाता है।
2011 चिंपांज़ी पर लगभग सभी शोध का दावा करने वाली एक रिपोर्ट वैज्ञानिक रूप से अनुचित है, जो अमेरिका के राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान को चिंपांज़ी का उपयोग करके नए अध्ययनों पर रोक लगाने का कारण बनता है।
2012 अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन निर्जलीकरण से बेहोश हो गईं और अपने घर में गिरने के बाद हंगामा जारी रहा।
2012 दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति, कल्गेमा मोटलन्थे ने अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के उद्घाटन पर राष्ट्रपति जैकब जुमा द्वारा पार्टी नेतृत्व को चुनौती दी।
2013 चिली के मतदाताओं ने देश के राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति मिशेल बाछलेट का चुनाव किया; बाचेलेट ने 2006 में पहली महिला चिली राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया।

# इंडी एलायंस के घटक दल एक दूसरे की जड़ों में मट्ठा डाल रहे

**अजय सेतिया**

उत्तर मध्य भारत के तीन राज्यों में हार के बाद कांग्रेस के भीतर बहुत बड़ी उथल पुथल शुरू हो चुकी है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से बनी हवा के बूते वह लोकसभा चुनावों की नैया पार करने के मंसूबे बना रही थी। उन मंसूबों पर पानी फिर गया है। हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और लद्दाख हिल काउन्सिल में जीत ने कांग्रेस में ऊर्जा का संचार किया था। उसे लगा था कि इन तीन प्रदेशों में मिली सफलता के कारण विपक्षी दल उसके साथ आने को मजबूर हुए हैं। नीतीश कुमार की कई महीनों से चल रही कोशिशों के बावजूद कांग्रेस ने कर्नाटक के चुनाव नतीजों तक विपक्षी एकता को हरी झंडी नहीं दी थी। कांग्रेस इस रणनीति पर काम कर रही थी कि कर्नाटक जीत लिया, तो भाजपा विरोधी क्षेत्रीय दल उसके साथ आने पर मजबूर होंगे। कर्नाटक में जीतने के बाद कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के शपथग्रहण में यूपीए के घटक दलों को ही न्योता देकर बाकी क्षेत्रीय दलों को एक संदेश दिया था, संदेश यह था कि नया गठबंधन उसी की रहनुमाई में ही होगा, नीतीश, लालू या ममता की रहनुमाई में नहीं।

कांग्रेस के दिमाग में इंडी एलायंस की अवधारणा यूपीए का विस्तृत रूप ही है। इसलिए उसने पटना, बेंगलुरु और मुम्बई की बैठकों में एलायंस के चेयरमेन या कन्वीनर के मुद्दे पर बात ही नहीं होने दी। यह क्षेत्रीय दलों को भी पता है कि कांग्रेस उन्हें अपने हित में इस्तेमाल करना चाहती है। हालांकि सच्चाई यह है कि इंडी एलायंस में शामिल हुए सभी दलों का मकसद एक दूसरे के वोट बैंक का फायदा उठाना ही है। अखिलेश यादव को लगता है कि मुस्लिम वोट बैंक नहीं बंटेगा, तो सपा को 20-25 सीटों पर कांग्रेस के वोट बैंक का फायदा मिल जाएगा। अरविन्द केजरीवाल को लगता है कि कांग्रेस आप को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में आधी सीटें दे देगी तो वह इन तीनों राज्यों से ही 8-10 जीत लेंगे। पांच राज्यों के चुनाव नतीजों ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय आधार की पोल खोल दी है। पाँचों राज्यों में उसके सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई, इसलिए केजरीवाल को इन तीनों राज्यों से ही उम्मीद बची है, और वह कांग्रेस के समर्थन के बिना पूरी नहीं हो सकती। इसी तरह नीतीश कुमार और लालू यादव को लगता है कि बिहार की तीन चौथाई सीटों पर उन्हें ही कांग्रेस के वोट बैंक का लाभ मिलेगा। फारूख अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को लगता है कि कांग्रेस साथ रहेगी तो जम्मू क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकेगा।

कांग्रेस ऐसा मानकर चल रही थी कि लद्दाख, हिमाचल और कर्नाटक की हवा राजस्थान, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़

में भी बहेगी तो इंडी एलायंस के नेतृत्व पर सवाल ही खड़ा नहीं होगा। तीनों राज्यों के चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस सोनिया गांधी को चेयरपर्सन और मल्लिकार्जुन खड़गे को एलायंस का कन्वीनर बनाने की रणनीति पर चल रही थी। कांग्रेस सौ प्रतिशत आश्वस्त थी कि कांग्रेस तीनों राज्यों में जीतेगी, उस जीत का श्रेय गठबंधन को न मिल जाए, इसलिए कांग्रेस ने इंडी एलायंस की न तो कोई साझा रैली की और न ही किसी दल के साथ चुनावी गठबंधन किया। कमलनाथ ने तो भाजपा के हिन्दू वोट बैंक में सेंध मारने के लिए भारत को हिन्दू राष्ट्र तक कह डाला। अपनी जीत को मजबूत बनाने के लिए राहुल गांधी ने तीनों राज्यों में जातीय जनगणना को बड़ा मुद्दा बनाया। कांग्रेस ने जैसे क्षेत्रीय दलों को कर्नाटक विधानसभा चुनाव नतीजों तक इन्तजार करवाया था, वैसे सीटों के बंटवारे के लिए भी पांच राज्यों के नतीजों का इंतजार करवा रही थी। राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल यू और समाजवादी पार्टी को भी इस बात का एहसास था कि अगर कांग्रेस तीनों या दो हिन्दी भाषी क्षेत्रों में जीत गई, तो वह यूपी बिहार में उन्हें खा जाएगी। विधानसभा चुनावों से पहले राहुल गांधी ने जाति आधारित जनगणना का कार्ड इसी रणनीति के साथ खेलना शुरू किया था।

जाति आधारित जनगणना के सहारे कांग्रेस की रणनीति हिन्दी भाषी क्षेत्रों में दलितों और पिछड़ी जातियों को अपनी तरफ आकर्षित करना है, जो इस समय या तो भाजपा के साथ जुड़े हैं, या बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के साथ और उतर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हैं। इसका मतलब साफ़ है कि कांग्रेस सिर्फ भाजपा के वोट बैंक पर ही निशाना नहीं साध रही थी, बल्कि सपा, बसपा, राजद और जदयू के वोट बैंक पर भी निशाना साध रही थी। इससे पहले कर्नाटक में भी कांग्रेस ने जेडीएस के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध मार कर उसे नुक्सान पहुंचाया था। इसलिए हिन्दी भाषी राज्यों के इन चारों दलों के लिए अपने अस्तित्व को बचाना उसी तरह जरूरी हो गया है, जैसे कर्नाटक में जेडीएस ने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए भाजपा से गठबंधन करने का फैसला किया है। तो क्या राजद, जदयू, सपा ने मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में कांग्रेस को हराने में भूमिका निभाई। सपा, आम आदमी पार्टी और जदयू ने अपने उम्मीदवार खड़े करके भले ही ज्यादा भूमिका नहीं निभाई, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के चन्द्रशेखर यादव और सपा के स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने सनातन विरोधी बयानों से कांग्रेस की जड़ों में मठ्ठा डालने का काम जरुर किया। कांग्रेस ने तीनों राज्यों के मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए सनातन विरोध पर चुप्पी साध कर हिन्दू वोट बैंक को भाजपा के पीछे खड़े होने को मजबूर कर दिया।

कांग्रेस शायद अभी भी समझ नहीं पा रही कि वह अपने मुस्लिम तुष्टिकरण के एजेंडे पर चल कर भाजपा के हिन्दू वोट बैंक को ही मजबूत करती है। इन तीन राज्यों के चुनावों में कांग्रेस के ही दो सहयोगी दलों समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल ने उसके साथ खेल कर दिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद का यह बयान हवा में उड़ाने वाला नहीं है कि कांग्रेस की हार का कारण सनातन विरोध पर उसकी चुप्पी है। सनातन विरोध से सपा, जदयू और राजद को भी कोई लाभ नहीं होने वाला, लेकिन राजद और सपा ने ठीक चुनाव के समय सनातन विरोध का मुद्दा उठाकर कांग्रेस को उसकी हैसियत दिखाने का काम कर दिया। इसलिए यह मानना कोरी कल्पना है कि इंडी एलायंस भाजपा को हराने के लिए एकजुट हो कर चुनाव लड़ेंगे, बल्कि इंडी एलायंस के दल एक दूसरे की जड़ें काटने का काम कर रहे हैं। तीनों ही राज्यों में इंडी एलायंस के घटक दलों ने भले ही वोट बैंक की दृष्टि से कांग्रेस को ज्यादा नुक्सान नहीं पहुंचाया, लेकिन कांग्रेस की हवा खराब करने का काम जरुर किया, जिसका अप्रत्यक्ष फायदा भाजपा को हुआ। वोट बैंक की दृष्टि से कांग्रेस को तीनों ही राज्यों में बसपा ने ज्यादा नुक्सान पहुंचाया। मध्यप्रदेश में बसपा, सपा और आप का वोट 2.57 प्रतिशत घट गया, तीनों को एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन बसपा को 3.40 प्रतिशत वोट मिला है। सपा और आप को भी एक प्रतिशत वोट मिला है। छत्तीसगढ़ में भी बसपा को 2.05 प्रतिशत वोट मिला है, राजस्थान में बसपा को 1.80 प्रतिशत और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को 2.4 प्रतिशत वोट मिला है। राजस्थान में कांग्रेस अगर बसपा और रालोप से चुनावी गठबंधन कर लेती, तो वह सत्ता बचा सकती थी।

# मोदी का मास्ट्रक स्ट्रोक, क्या धराशायी होगी राहुल की जमाई फील्डिंग?

**जितेंद्र भारद्वाज**

सियायत की पिच पर प्रधानमंत्री मोदी फ्रंटफुट पर खेल रहे हैं। जिस तरह से मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में सीएम पद के लिए नए चेहरों का चयन किया गया है, उसके पीछे विपक्ष के एजेंडे को धराशाही करना है। पीएम मोदी के मास्टर स्ट्रोक से, इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी द्वारा जितनी आबादी, उतना हक और ओबीसी पर जमाई फील्डिंग, क्या बिखर जाएगी। राजनीतिक जानकार भी मानते हैं कि भाजपा, कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के मुद्दे छीन रही है। राहुल गांधी ने पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में ओबीसी, जातिगत गणना, आदिवासी और जितनी आबादी, उतना हक, जैसे मुद्दों पर जबरदस्त तरीके से भाजपा को घेरने की कोशिश की थी। मध्यप्रदेश में मोहन यादव और छत्तीसगढ़ में आदिवासी को सीएम बनाकर भाजपा ने संकेत दे दिया है कि इन मुद्दों पर कांग्रेस, लंबी दूरी तय नहीं कर सकेगी। पांच राज्यों के चुनाव से पहले बिहार में जातिगत गणना कराई गई थी। इसके बाद राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन के सहयोगियों के साथ चर्चा कर इस मुद्दे को उठा लिया। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष को यह मुद्दा, मंडल कमीशन की तरह लगा था, इसलिए उन्होंने जातिगत गणना और ओबीसी को लेकर प्रेसवार्ता भी की। उसके बाद राहुल ने पांच राज्यों के चुनाव में उक्त मुद्दों को जबरदस्त तरीके से भुनाया। राहुल ने कहा, केंद्र सरकार में 90 सेक्रेटरी में से सिर्फ 3 ओबीसी से हैं। ये ओबीसी समाज का अपमान है। कितने दलित हैं और आदिवासी, इस सवाल का जवाब जाति जनगणना है। केंद्र सरकार, इस सवाल से भाग रही है। वह जनगणना कराने से बच रही है। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व, इन मुद्दों के सियासी नुकसान को भांप चुका था। आरएसएस से सलाह करने के बाद भाजपा ने अपने रणनीति बना ली। उसकी बानगी भी मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों के चयन में देखने को मिल गई है। कांग्रेस पार्टी की राजनीति को करीब से समझने वाले वरिष्ठ पत्रकार एवं लेखक रशीद किदवई कहते हैं, यह राष्ट्रीय दल, औचक फैसले लेने में सक्रियता नहीं दिखाता। सियासत में मुद्दे किसी के होते हैं और उन्हें उठा, कोई दूसरा लेता है। खासतौर पर मुकाबले वाली स्थिति में कांग्रेस पिछड़ जाती है। मोदी, एकाएक राष्ट्रीय राजनीति में आए। आम आदमी पार्टी का उदय हुआ। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की समस्या है कि ये लोग अपने पत्ते, पहले ही खोल देते हैं। जातिगत गणना, ओबीसी या महिला आरक्षण, ये संवेदनशील मुद्दे होते हैं। अगर बिहार में आज इस जातिगत गणना की चर्चा है, चमक है तो उसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लंबे समय तक तैयारी की थी। वो एकाएक लिया गया निर्णय नहीं था। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने बिना तैयारी या होमवर्क किए, इस मुद्दे को उठा लिया। विधानसभा चुनाव में वे इन मुद्दों को भुना नहीं सके। ऐसा पहले भी होता रहा है कि कांग्रेस पार्टी अपने पत्ते पहले ही खोल देती है। सत्ताधारी पार्टी, उनमें थोड़ा बहुत बदलाव कर, उन्हें अपने फायदे के लिए तैयार कर लेती है। राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में चौकीदार चोर है का मुद्दा उठाया, लेकिन उस पर कोई होमवर्क नहीं किया। उसके नफा नुकसान का अंदाजा नहीं लगाया। नतीजा, वह कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचा गया। भाजपा ने तीनों मुख्यमंत्रियों के नाम का एलान कर, राहुल गांधी से एक साथ कई मुद्दे छीन लिए हैं।

# जनता का भरोसा नहीं टूटने की देनी होगी गारंटी

**गिरीश्वर मिश्र**

इसमें कोई संदेह नहीं कि ताजे चुनाव परिणामों से भारतीय जनता पार्टी की छवि एक सशक्त दल के रूप में निखरी है। इस तरह के स्पष्ट जन-समर्थन को संयोग नहीं कहा जा सकता न इसे जाति, धन और धर्म का करिश्मा ही कह सकते हैं। यह दिग्भ्रमित विपक्ष की सौगात भी कहना सही न होगा क्योंकि तेलंगाना के परिणाम विरुद्ध गए हैं। इसके ठीक विपरीत कांग्रेस शासित दो प्रदेशों में मिले मुखर जनादेश आम आदमी का भरोसा और विश्वास तो दिखाते ही हैं, वे अपनी आशाओं और आकांक्षाओं के साथ आगे की राह भी दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश में सत्तारूढ़ दल के समाधान को देखें तो यही लगता है कि पार्टी का जनाधार निश्चित रूप से विस्तृत हुआ है। बहुत हद तक अप्रत्याशित बढ़त वाला भाजपा का ताजा चुनावी प्रदर्शन तात्कालिक रणनीति और प्रचार से अधिक सघन जनसंपर्क तथा समाज के हाशिए के लोगों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रमों की सक्रियता, उपलब्धता और प्राभाविकता को दर्शाता है। राष्ट्र की एकता, उसके गौरव और उसकी सामर्थ्य को लेकर प्रधानमंत्री की प्रकट प्रतिबद्धता से जनता का मन भी बदला है। इस बदलाव के पीछे प्रधानमंत्री मोदी का अथक परिश्रम एक खास कारण है। आर्थिक विकास की ओर आगे बढ़ती एक बड़ी अर्थव्यवस्था के स्वप्न के साथ हाशिए के समाज की स्थिति को सुधारने के लिए प्रकट प्रतिबद्धता ने जनता को भरोसा दिलाया है। यहां इसे भी रेखांकित किया जाना चाहिए कि मतदाता की समझदारी बढ़ने के साथ सरकार की भूमिका भी जनता की निगरानी में आ रहे हैं। प्रशासन तंत्र की चुस्ती-फुर्ती भी पूरी तरह संतोषजनक नहीं है। न्याय, शिक्षा और स्वास्थ्य की प्रचलित प्रणालियां न केवल अस्त-व्यस्त हैं बल्कि उनको बड़े दिनों से सुधार का इंतजार बना हुआ है। तुष्टिकरण की राजनीति से राजनीतिक फायदे तो उठाए जाते रहे हैं किंतु उसका अल्पकालिक असर सतही बदलाव के साथ चुक जाता है। स्वतंत्र देश में कार्यप्रणाली की भयानक जकड़नों को दूर करना होगा। आज अनेक संस्थाएं बुरी तरह से अव्यवस्था का शिकार हो रही हैं। उनके स्वभाव के साथ गैरजरूरी छेड़छाड़ गुणवत्ता को कम करने वाला है। इसी तरह महंगाई, बेरोजगारी, असुरक्षा , भ्रष्टाचार और हिंसा को रोकना जरूरी है। वर्तमान जनादेश में यह गुहार भी छिपी है कि इन समस्याओं से छुटकारा दिलाया जाए। जनता का भरोसा न टूटे, इसकी गारंटी जमीनी स्तर पर देनी होगी।

# उत्तर बनाम दक्षिण का 2024 में कितना दिखेगा असर

**अंकित सिंह**

हाल में ही संपन्न पांच राज्यों के चुनावी नतीजों में भाजपा के जबरदस्त जीत हासिल हुई है। भाजपा ने इन पांच राज्यों में से तीन राज्यों में प्रचंड विजय हासिल की। भाजपा की जीत के बाद राजनीतिक दांव पेंच शुरू हो गए। इसके साथ ही उत्तर बनाम दक्षिण का भी मामला सामने आ गया। दरअसल, भाजपा ने जिन तीन राज्यों में जीत हासिल की, वह हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। इन्हें हिंदी बेल्ट का राज्य माना जाता है जो देश के उत्तर और मध्य क्षेत्र में आते हैं। हालांकि, तेलंगाना में भाजपा ने अपनी पूरी ताकत लगाई थी। बावजूद इसके उसे वहां ज्यादा सफलता नहीं मिली और कांग्रेस ने वहां जीत हासिल की। कर्नाटक के बाद तेलंगाना में जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनी, उसके बाद नॉर्थ बनाम साउथ को भी हवा दे दी गई।

दरअसल, सोशल मीडिया पर सबसे पहले इसकी चर्चा शुरू हुई। उसके बाद डीएमके सांसद सेंथिल कुमार ने संसद में कुछ ऐसा बयान दिया जिसके बाद से इस मुद्दे को हवा मिल गई। हालांकि, भाजपा की ओर से साफ तौर पर कहा गया कि विपक्षी भारत को विभाजित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथी राहुल गांधी के पुराने बयान के भी खूब चर्चा हुई जिसमें उन्होंने कहा था कि उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत के लोगों में राजनीतिक समझ ज्यादा है। भाजपा के नेता अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' के घटक दलों पर देश को उत्तर-दक्षिण के आधार पर बांटने की कोशिश करने का आरोप लगाया और कहा कि विपक्ष अपने प्रयासों में सफल नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि 'इंडिया' गठबंधन के दल भारत को उत्तर-दक्षिण के आधार पर विभाजित करने के अपने कथित प्रयासों में विफल रहेंगे।

अगर भारत के मैप को देखें तो भाजपा की ताकत का साफ तौर पर पता चल जाएगा। भाजपा जहां मध्य और हिंदी हार्ट लैंड में पूरी ताकतवर है। तो वहीं, देश के पश्चिमी क्षेत्र यानी कि राजस्थान, गुजरात में भी उसकी पकड़ मजबूत है। महाराष्ट्र में 2019 में भाजपा को सफलता मिली थी लेकिन वहां वह गठबंधन में हैं। वहीं गोवा में उसकी सरकार है जो केंद्र की राजनीति के लिहाज से उतना महत्व नहीं रखता। पूरे दक्षिण भारत को देखें तो वह कहीं भी सत्ता में नहीं है जबकि पूर्वी तटीय क्षेत्र में भी वह हाशिए पर है जिसमें पश्चिम बंगाल, ओडिसा, आंध्र प्रदेश शामिल है। इन तीनों ही राज्यों में क्षेत्रीय दलों का शासन है जिन्होंने विधानसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। यह बात भी सही है कि इन राज्यों में भाजपा ने अपनी पकड़ को पहले के तुलना में कई ज्यादा गुना मजबूत किया है। 2019 में भाजपा को बंगाल और ओडिशा में उम्मीद से ज्यादा सीटें जीतने में कामयाबी मिली थी।

उत्तर भारत के राज्यों की बात करें तो बीजेपी के कुल 118 लोकसभा के सांसद हैं जबकि 35 राज्यसभा के सांसद हैं। वहीं दक्षिण भारत में 6 राज्य हैं। इन राज्यों में 130 लोकसभा की सीटें हैं। इन 130 सीटों में से भाजपा के पास 29 लोकसभा की सीटें हैं। वहीं राज्यसभा के 7 सांसद हैं। 2019 में जब भाजपा अपने दम पर 303 लोकसभा सीटें जीतने में कामयाब रही थी तब भी दक्षिण भारत के कई राज्यों में उसका खाता तक नहीं खुल सका था। कर्नाटक ही ऐसा राज्य था, जहां भाजपा ने 28 में से 25 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं, चार सीटें उसे तेलंगाना में जितने में कामयाबी हासिल हुई थी। हालांकि, कांग्रेस के लिए भी दक्षिण भारत कोई मजबूत किला नहीं है। दक्षिण भारत में उसके पास लोकसभा के 27 सीटें हैं। आंध्र प्रदेश में 25, केरल में 20, कर्नाटक में 28, तमिलनाडु में 39 और तेलंगाना में 17 लोकसभा की सीटें हैं।

2019 की बात करें तो 224 सीटों पर भाजपा ने 50 फ़ीसदी से ज्यादा वोट हासिल किए थे और जबरदस्त तरीके से जीत हासिल की थी। इनमें से ज्यादातर सीटें उन राज्यों में थी जो कि भाजपा के गढ़ माने जाते हैं। वहीं, बाकी के 319 सीटों की बात करें तो उनमें से भाजपा केवल 79 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई थी। इसके बाद पार्टी का कुल आंकड़ा 303 हुआ था और यह बहुमत के जरूरी 272 से 31 ज्यादा हैं। भाजपा को जो 79 सीटें मिली थी उनमें महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, ओडिसा और तेलंगाना भी शामिल है जहां इंडिया गठबंधन की स्थिति मजबूत मानी जा सकती है। यही कारण है कि बीजेपी इन 79 सीटों पर जीत हासिल करने को लेकर पूरी तरीके से अपनी प्रतिबद्धता दिख रही है और इंडिया गठबंधन पर जबरदस्त तरीके से निशाना साध रही है।

# विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ियों की उम्मीदों पर निशिचत ही खरे उतरेंगे

**डॉ. रमेश ठाकुर**

आदिवासी बाहुल्य प्रदेश %छत्तीसगढ़% की कमान आदिवासी नेता विष्णुदेव साय को सौंपे जाने का जबसे सार्वजनिक ऐलान हुआ है, छत्तीसगढ़िया फूले नहीं समा रहे हैं। खुश होना वैसे बनता भी है, आखिर इतने वर्षों बाद उनकी ख्वाहिशें पूरी जो हुई हैं। स्थानीय लोग शुरू से चाहते थे कि कोई आदिवासी समाज का व्यक्ति ही प्रदेश का मुख्यमंत्री बने। ऐसा व्यक्ति जो 33 फीसदी आदिवासी समाज का चहेता हो और सामाजिक समूह को लेकर साथ चले। लंबे राजनीतिक अनुभव के अलावा पहचान जमीनी स्तर की हो। ऐसा राजनेता जो उनके बीच सदैव रहा हो। फिलहाल, ये सभी खूबियां विष्णुदेव साय में आकर सिमट जाती हैं। विष्णुदेव प्रदेश के सर्वमान्य नेताओं में गिने जाते हैं। यही कारण है कि आदिवासी समुदाय चाहे कांगेस से ताल्लुक रखता हो, या अन्य किसी और सियासी दल से, सभी विष्णुदेव की नियुक्ति से खुश हैं। छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से जकड़ा हुआ है, सभी चाहते हैं कि उन बंधक बेड़ियों से उन्हें कोई मुक्त करवाए।

विष्णुदेव बेदाग और ईमानदार नेता हैं। पंचायत से लेकर केंद्र तक की महत्वपूर्ण सियासी जिम्मेदारियां उन्होंने संभाली हुई हैं। साय बेशक सांसद बनकर केंद्र की राजनीति में पहुंच गए हों लेकिन उनका जुड़ाव स्थानीय स्तर पर कभी कम नहीं हुआ। गांव-कस्बों की टूटी नल-नालियों की परवाह हमेशा करते रहे। केंद्रीय मंत्री भी बने, लेकिन उनके भीतर से ग्राम प्रधान कभी नहीं निकला? वह इसलिए क्योंकि उनकी राजनीति की शुरुआत ही ग्राम प्रधानी से हुई। निश्चित रूप से साय जैसे जमीनी नेता अपने क्षेत्र, समुदाय और प्रदेश में नया इंकलाब लिखने का माद्दा रखते हैं। निश्चित रूप से वह अपने प्रयासों में सफल होने की कोशिश करेंगे। प्रदेश पर इस वक्त करीब 82,125 करोड़ रुपये का कर्ज है। इसके सिवाए महंगाई-बेरोजारी की स्थिति से तो सभी वाकिफ हैं ही, इन सभी चुनौतियों से भी विष्णुदेव को बड़े साहस से लड़ना होगा। हालांकि उन्हें केंद्र सरकार का साथ भरपूर मिलेगा क्योंकि डबल इंजन की सरकार में प्रयासों में गति आना स्वाभाविक होता है।

बहरहाल, छत्तीसगढ़ की 33 फीसदी आदिवासी समुदाय के लिए विष्णुदेव मात्र मुख्यमंत्री ही नहीं बनेंगे, बल्कि वो उनके उम्मीदों को पूरा करने वाले नायक भी बनेंगे। जो प्रदेश गठन के बाद अभी तक पूरी नहीं हुई। प्रदेशवासियों की शुरू से मांग रही है कि उनका मुख्यमंत्री उन्हीं के बीच का हो, ताकि उनकी जरूरतों और समृद्ध विरासतों को आगे बढ़ा सके। ऐसे लक्ष्यों को पूरा करने में विष्णुदेव फिलहाल फिट बैठते दिखाई पड़ते हैं। क्योंकि उन्होंने अपने राजनीति कॅरियर से लोगों के बीच वैसी ही छाप छोड़ी है। तभी, चुनाव कैंपेन के दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने वोटरों को इशारा भी किया था कि विष्णुदेव को बड़ा आदमी बनाएंगे, उनके लिए कुछ बड़ा सोचा हुआ है। हालांकि, तब लोगों ने उनकी बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया था, सोचा कि चुनावों में नेता बहुत कुछ बोलकर चले जाते हैं। पर, इतना नहीं भूलना चाहिए कि नरेंद्र मोदी-अमित शाह अलग किस्म की गारंटी देते हैं। जहां से लोग सोचना बंद कर देते हैं, ये जोड़ी वहीं से सोचना आरंभ करती है। श्रीमती द्रौपदी मुमू को जब राष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित किया गया था, तभी आदिवासी समाज समझ गया था कि कोई तो है जो उनके विषय में सोचता है।

ये भी तय है कि छत्तीसगढ़ को आदिवासी मुख्यमंत्री देने के बाद मोदी-शाह की राजनीति लड़ाई यहीं नहीं थमेगी। अगली फाइट ओडिशा के लिए शुरू होगी, ओडिशा भी आदिवासी बाहुल्य प्रदेश है। छत्तीसगढ़ के बाद वहां के लोगों को भी आदिवासी मुख्यमंत्री देने का संदेश दिया जाएगा। क्योंकि वहां भी चुनाव नजदीक हैं। जहां तक विष्णुदेव साय की बात है तो छत्तीसगढ़ की राजनीति में वो सम्मानीय चेहरा हैं। अजित जोगी के बाद लोग साय से बहुत उम्मीदें करते हैं। क्योंकि साय चार मर्तबा सांसद, दो बार विधायक, केंद्रीय राज्यमंत्री और दो-दो बार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व संभाल चुके हैं। इसके अलावा उनके पास संगठनात्मक कार्य का लंबा-चौड़ा अनुभव भी है। इस बार वो कुनकुरी विधानसभा से निर्वाचित हुए हैं। जहां उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार को अच्छे मार्जिन से मात दी। अपने दम पर जिले की सभी सीटें भाजपा को जितवाईं। जबकि, कुनकुरी में अभी तक कांग्रेस की तूती बोलती रही थी।

बहरहाल, प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे विष्णुदेव साय से भाजपा का शीर्ष नेतृत्व कभी नाराज भी हुआ था। नाराजगी इस कदर थी कि उन्हें प्रदेश अध्यक्षी से भी हटा दिया गया था। पर, बावजूद इसके उनकी निष्ठा पार्टी के प्रति जरा भी कम नहीं हुई थी। साय लगातार पार्टी गतिविधियों में सक्रिय रहे, संगठन को मजबूत करते गए, नए लोगों को भाजपा से जोड़ते रहे। धीरे-धीरे उन्होंने अपने क्षेत्र में ऐसा संगठन खड़ा किया कि मौजूदा चुनाव में दूसरे दलों का सूपड़ा तक साफ करवा दिया। वैसे, अगर उनके शुरुआती राजनीतिक जीवन पर नजर डालें तो आगाज 1989 में हुआ। सबसे पहले वह अपने ग्राम के सरपंच बने, उसी दौरान उनका संघ से जुड़ाव हुआ, जिले, कस्बों व गांवों में शाखाएं स्थापित करवाईं। प्रचारक की भूमिका में आए, धीरे-धीरे संघ के बड़े नेताओं की नजरों में आ गए। संघ का प्रचार उन्होंने आदिवासियों के बीच में भी जबरदस्त किया। कई नक्सलियों का ह्रदय परिवर्तन कर भाजपा और संघ के प्रति प्यार पैदा किया। यही कारण है कि नक्सल प्रभावित सोच वाले व्यक्तियों ने भी इस बार दिल खोलकर भाजपा को वोट किया।

छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद बड़ा मुद्दा है। साय के मुख्यमंत्री बनने के बाद कितना बदलाव आएगा, इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन साय को उम्मीद है कि उन्हें भटके रास्तों से वापस सही रास्तों पर लाने का प्रयास करेंगे। साय पर भाजपा ने पहली दफे भरोसा करके 1990 में 'तपकरा' विधानसभा से उतारा था, जहां उन्होंने जीत हासिल की थी। इसके बाद विष्णुदेव साय रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र से लगातार तीन बार के सांसद चुने गए। 2014 में वो मोदी-शाह के प्रिय बन गए। उनके संबंध अन्य दलों के नेताओं से भी मधुर हैं। सभी को साथ लेकर चलने में विश्वास करते हैं। फिलहाल, मुख्यमंत्री के रूप में उनका पहला वर्ष काफी चुनौतियों से भरा होगा। क्योंकि चुनावों में जो वादे किए हैं उन्हें जमीन पर उतारना होगा। हालांकि मुख्यमंत्री पद के लिए नाम घोषित होने के बाद उन्होंने सबसे पहले चुनावी वादों को पूरा करने का ही प्रण लिया है। किसानों की समस्याएं, सरकारी योजनाओं को लागू करना, शिक्षा, सुरक्षा और चिकित्सा ऐसे मसले हैं जिनको अगर अन्य राज्यों से तुलना करें, तो छत्तीसगढ़ अब भी काफी पिछड़ा है। इसके अलावा सबसे बड़ी परीक्षा तो नक्सलवाद को कम करने की होगी। खत्म करना तो आसान नहीं होगा। कम हो जाए, वो भी गनीमत रहेगी। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ियों को नए मुख्यमंत्री से हजारों उम्मीदें रहेंगी, देखने वाली बात होगी कि साय देशवासियों की उम्मीदों पर कितना खरा उतरते हैं।

अष्टू

# बाल कथा

जीवन जोशी

# ईमानदारी की जीत

**चारों** ओर सुंदर वन में उदासी छाई हुई थी। वन को अज्ञात बीमारी ने घेर लिया था। वन के लगभग सभी जानवर इस बीमारी के कारण अपने परिवार का कोई न कोई सदस्य गवाँ चुके थे। बीमारी से मुकाबला करने के लिए सुंदर वन के राजा शेर सिंह ने एक बैठक बुलाई।

बैठक का नेतृत्व खुद शेर सिंह ने किया। बैठक में गज्जू हाथी, लंबू जिराफ, अकड़ू सांप, चिंपू बंदर, गिलू गिलहरी, कीनू खरगोश सहित सभी जंगलवासियों ने हिस्सा लिया। जब सभी जानवर इकट्ठे हो गए, तो शेर सिंह एक ऊँचे पत्थर पर बैठ गया और जंगलवासियों को संबोधित करते हुए कहने लगा, भाइयो, वन में बीमारी फैलने के कारण हम अपने कई साथियों को गवाँ चुके हैं। इसलिए हमें इस बीमारी से बचने के लिए वन में एक अस्पताल खोलना चाहिए, ताकि जंगल में ही बीमार जानवरों का इलाज किया जा सके।

इस पर जंगलवासियों ने एतराज जताते हुए पूछा कि अस्पताल के लिए पैसा कहाँ से आएगा और अस्पताल में काम करने के लिए डॉक्टरों की जरूरत भी तो पड़ेगी? इस पर शेर सिंह ने कहा, यह पैसा हम सभी मिलकर इकट्ठा करेंगे।

यह सुनकर कीनू खरगोश खड़ा हो गया और बोला, महाराज! मेरे दो मित्र चंपकवन के अस्पताल में डॉक्टर हैं। मैं उन्हें अपने अस्पताल में ले आऊँगा।

इस फैसले का सभी जंगलवासियों ने समर्थन किया। अगले दिन से ही गज्जू हाथी व लंबू जिराफ ने अस्पताल के लिए पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दिया।

जंगलवासियों की मेहनत रंग लाई और जल्दी ही वन में अस्पताल बन गया। कीनू खरगोश ने अपने दोनों डॉक्टर मित्रों वीनू खरगोश और चीनू खरगोश को अपने अस्पताल में बुला लिया। राजा शेर सिंह ने तय किया कि अस्पताल का आधा खर्च वे स्वयं वहन करेंगे और आधा जंगलवासियों से इकट्ठा किया जाएगा।

इस प्रकार वन में अस्पताल चलने लगा। धीरे-धीरे वन में फैली बीमारी पर काबू पा लिया गया। दोनों डॉक्टर अस्पताल में आने वाले मरीजों की पूरी सेवा करते और मरीज़ भी ठीक हो कर डाक्टरों को दुआएँ देते हुए जाते। कुछ समय तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। परंतु कुछ समय के बाद चीनू खरगोश के मन में लालच बढ़ने लगा। उसने वीनू खरगोश को अपने पास बुलाया और कहने लगा यदि वे दोनों मिल कर अस्पताल की दवाइयाँ दूसरे वन में बेचें तथा रात में जाकर दूसरे वन के मरीज़ों को देखें तो अच्छी कमाई कर सकते हैं और इस बात का किसी को पता भी नहीं लगेगा। वीनू खरगोश पूरी तरह से ईमानदार था, इसलिए उसे चीनू का प्रस्ताव पसंद नहीं आया और उसने चीनू को भी ऐसा न करने का सुझाव दिया। लेकिन चीनू कब मानने वाला था। उसके ऊपर तो लालच का भूत सवार था। उसने वीनू के सामने तो ईमानदारी से काम करने का नाटक किया। परंतु चोरी-छिपे बेइमानी पर उतर आया। वह जंगलवासियों की मेहनत से खरीदी गई दवाइयों को दूसरे जंगल में ले जाकर बेचने लगा तथा शाम को वहाँ के मरीजों का इलाज करके कमाई करने लगा। धीरे-धीरे उसका लालच बढ़ता गया। अब वह अस्पताल के कम, दूसरे वन के मरीजों को ज्यादा देखता। इसके

विपरीत, डॉक्टर वीनू अधिक ईमानदारी से काम करता। मरीज भी चीनू की अपेक्षा डॉक्टर वीनू के पास जाना अधिक पसंद करते। एक दिन सभी जानवर मिलकर राजा शेर सिंह के पास चीनू की शिकायत लेकर पहुँचे। उन्होंने चीनू खरगोश की कारगुजारियों से राजा को अवगत कराया और उसे दंड देने की माँग की। शेर सिंह ने उनकी बात ध्यान से सुनी और कहा कि सच्चाई अपनी आँखों से देखे बिना वे कोई निर्णय नहीं लेंगे। इसलिए वे पहले चीनू डॉक्टर की जांच कराएँगे, फिर अपना निर्णय देंगे। जांच का काम चालाक लोमड़ी को सौंपा गया, क्योंकि चीनू खरगोश लोमड़ी को नहीं जानता था। लोमड़ी अगले ही दिन से चीनू के ऊपर नजर रखने लगी। कुछ दिन उस पर नज़र रखने के बाद लोमड़ी ने उसे रंगे हाथों पकड़ने की योजना बनाई। उसने इस योजना की सूचना शेर सिंह को भी दी, ताकि वे समय पर पहुँच कर सच्चाई अपनी आँखों से देख सकें। लोमड़ी डॉक्टर चीनू के कमरे में गई और कहा कि वह पास के जंगल से आई है। वहाँ के राजा काफी बीमार हैं, यदि वे तुम्हारी दवाई से ठीक हो गए, तो तुम्हें मालामाल कर देंगे। यह सुनकर चीनू को लालच आ गया।

## अनोखी तरकीब

**बहुत** पुरानी बात है। एक अमीर व्यापारी के यहाँ चोरी हो गयी। बहुत तलाश करने के बावजूद सामान न मिला और न ही चोर का पता चला। तब अमीर व्यापारी शहर के काजी के पास पहुँचा और चोरी के बारे में बताया।

सबकुछ सुनने के बाद काजी ने व्यापारी के सारे नौकरों और मित्रों को बुलाया। जब सब सामने पहुँच गए तो काजी ने सब को एक-एक छड़ी दी। सभी छड़ियाँ बराबर थीं। न कोई छोटी न बड़ी। सब को छड़ी देने के बाद काजी बोला, इन छड़ियों को आप सब अपने अपने घर ले जाएँ और कल सुबह वापस ले आएँ। इन सभी छड़ियों की खासियत यह है कि यह चोर के पास जा कर ये एक उँगली के बराबर अपने आप बढ़ जाती हैं। जो चोर नहीं होता, उस की छड़ी ऐसी की ऐसी रहती है। न बढ़ती है, न घटती है। इस तरह मैं चोर और बेगुनाह की पहचान कर लेता हूँ।

काजी की बात सुन कर सभी अपनी अपनी छड़ी ले कर अपने अपने घर चल दिए। उन्हीं में व्यापारी के यहाँ चोरी करने वाला चोर भी था। जब वह अपने घर पहुँचा तो उस ने सोचा, अगर कल सुबह काजी के सामने मेरी छड़ी एक उँगली बड़ी निकली तो वह मुझे तुरंत पकड़ लेंगे। फिर न जाने वह सब के सामने कैसी सजा दें। इसलिए क्यों न इस विचित्र छड़ी को एक उँगली काट दिया जााए। ताकि काजी को कुछ भी पता नहीं चले। चोर यह सोच बहुत खुश हुआ और फिर उस ने तुरंत छड़ी को एक उँगली के बराबर काट दिया। फिर उसे घिसघिस कर ऐसा कर दिया कि पता ही न चले कि वह काटी गई है।

अपनी इस चालाकी पर चोर बहुत खुश था और खुशीखुशी चादर तान कर सो गया। सुबह चोर अपनी छड़ी ले कर खुशी खुशी काजी के यहाँ पहुँचा। वहाँ पहले से काफी लोग जमा थे।

काजी 1-1 कर छड़ी देखने लगे। जब चोर की छड़ी देखी तो वह 1 उँगली छोटी पाई गई। उस ने तुरंत चोर को पकड़ लिया। और फिर उस से व्यापारी का सारा माल निकलवा लिया। चोर को जेल में डाल दिया गया।

सभी काजी की इस अनोखी तरकीब की प्रशंसा कर रहे थे।

## कविता

### जल की रानी मछली

तैर-तैर मछली इठलाती,
जल की रानी है कहलाती।

पंख सुनहरे नित चमकाती,
बिना कांटा पकड़ी नहीं जाती।

पानी में ही जीवित रहती,
पर भूखों का दुख न सहती।

परहित जीवन सदा लुटाती,
बलिदानी जग में कहलाती।

– सुगनचंद्र, नलिन

## सेहत

# नकसीर के घरेलु उपचार

**चिलचिलाती** धूप में अक्सर कुछ लोगों को नाक से खून बहने की शिकायत होती है। इसे नकसीर भी कहा जाता है। यह मौसम के अनुसार शरीर में अधिक गर्मी बढ़ने से भी हो सकता है और कुछ लोगों को अधिक गर्म पदार्थ का सेवन करने से भी। पेश है नकसीर से निपटने के घरेलू उपचार-

- प्याज को काटकर नाक के पास रखें और सूंघें।
- काली मिट्टी पर पानी छिड़ककर इसकी खुशबू सूंघें।
- रुई के फाए को सफेद सिरका में भिगोकर उस नथुने में रखें, जिससे खून बह रहा हो।
- जब नाक से खून बह रहा हो तो कुर्सी पर बिना टेका लिए बैठ जाएं, नाक की बजाय मुंह से सांस लें।
- सिर को आगे की ओर झुकाएं न कि पीछे की ओर।
- ठंडे पानी में भीगे हुए रुई के फाए को नाक पर रखें। रुई के छोटे-छोटे फायों को पानी में भिगोकर फ्रीजर में रख लें। इनसे सिकाई करें।

- किसी भी प्रकार के धूम्रपान (एक्टिव या पैसिव दोनों) से बचें।
- साफ हरे धनिए की पत्तियों के रस की कुछ बूंदें नाक में डाल लें।
- इन उपायों के अलावा सिर पर ठंडे पानी की पट्टी रखने से भी राहत मिलेगी।

### दूध

संता (बंता से)- तेरे कुत्ते ने मेरी किताब फाड़ दी!
बंता (संता से)- मैं उसे सजा देता हूं।
संता- मैंने सजा दे दी।
बंता- कैसे?
संता- मैं उसकी कटोरी का दूध पी गया।

### कोर्ट

वकील- गीता पर हाथ रखकर कहो की..
मुजरिम- ये क्या, सीता पर हाथ लगाया तो कोर्ट में बुलाया, अब फिर गीता पर हाथ!!

### शादी

टीचर - बताओ बच्चों कि लड़की की शादी 18 साल बाद और लड़के की 21 साल बाद क्यों करना चाहिए।
एक लड़का- क्योंकि लड़का बड़ा और लड़की छोटी होनी चाहिए !
एक लड़की- नहीं बेवकूफ, क्योंकि लड़की को अक्ल 18 साल बाद और लड़के को 21 साल बाद आती है !!!

### गोली

पठान ने अपनी बीवी को गोली मार दी, क्योंकि उसकी बीवी ने सिर्फ इतना कहा था कि- मैं अपनी जिंदगी, शान और शौकत के साथ गुजारना चाहती हूं।

### इमरजेंसी

डॉक्टर आधी रात को उठा और पत्नी से बोला- मैं हॉस्पिटल जा रहा हूं.. फोन आया है इमरजेंसी है।
पत्नी- किसी को तो अपनी मौत मरने दो।

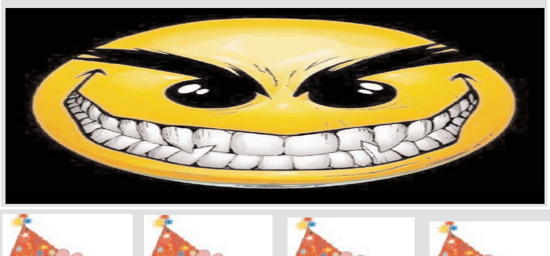

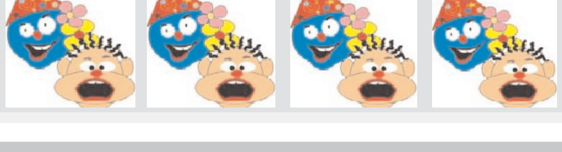

## जानकारी

# कभी सोडा के बिना बेचा जाता था कोका कोला

**कोका** कोला का स्लोगन- ठंडा मतलब कोका कोला.. आज बच्चे बच्चे की जबान पर है। कोका कोला की प्रसिद्धि पर गौर किया जाए तो दुनिया भर में आज प्रति सैकेंड लगभग आठ हजार गिलास कोका कोला पिया जाता है। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि यह ठंडा पेय कहां से आया और इसके आविष्कारक कौन थे।

गर्मियों में ठंडक देने वाले इस शीतल पेय का आविष्कार अटलांटा, अमेरिका के एक दवा विक्रेता डॉ. जॉन स्टिच पेमबर्टन ने किया था। उन्होंने 1886 में कोका के पत्ते और %अफ्रीकी कोला% नामक बादाम के प्रयोग से इस पेय को तैयार किया था। यह न सिर्फ एक शीतल पेय था, बल्कि दिमाग को तरोताजा करने वाला भी था। जब इसे बाजार में लाया गया तो इसे पसंद करने वालों की संख्या बहुत अधिक थी। डॉ. पेमबर्टन के एक पार्टनर फ्रेंक एम. राबिन्सन जो कि किताबों के विक्रेता थे, ने उनके इस पेय को %कोका कोला% नाम दिया।

दोस्तों, अपने आविष्कार के समय कोका कोला बिना सोडा के साथ बेचा गया। एक दिन पेमबर्टन की दवा की दुकान पर सिरदर्द और गर्मी से बेहाल एक ग्राहक आया उसने पेमबर्टन से आग्रह किया कि वह कोका कोला को सोडा के साथ पीना चाहता है। पेमबर्टन ने कोका कोला को सोडा के साथ मिलाकर ग्राहक को दिया और खुद भी पिया। स्वाद में यह बिना सोडा मिश्रित कोका कोला से भी बेहतर और तुरंत राहत पहुंचाने वाला था, और तब से सोडा मिला कोका कोला ही बेचा जाने लगा।

1888 में पेमबर्टन की मौत के बाद 1891 में कोका कोला को बेचे जाने का अधिकार अमेरिका के एमोरी विश्वविद्यालय के चांसलर ग्रिग्स कैंडलर ने खरीदा और 1892 में इसे एक कंपनी का रूप दिया। 1894 में कोका कोला को बोतल में पैक कर पूरे अमेरिका में बेचा जाने लगा।

1915 में कोका कोला की बोतल को नया लुक दिया गया क्योंकि उस समय तक अमेरिका में जो भी शीतल पेय मिलते थे उनकी बोतल का डिजाइन एक जैसा था। बाजार में अलग दिखाने के लिए कोका कोला की बोतल को अलग तरह से डिजाइन कराकर उसका पेटेंट कराया गया। इस बोतल का डिजाइन रूट ग्लास कंपनी के डिजाइनर अर्ल आर डीन ने तैयार किया।

## जीव जंतु

# मैडागास्कर में पाया गया डेढ़ इंच का गिरगिट

**गिरगिट** छिपकली की एक प्रजाति है, जिसे उसकी रंग बदलने की विशिष्टता के लिए जाना जाता है। प्रमुख रूप से यह अफ्रीका, मैडागास्कर, दक्षिणी यूरोप, उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिण एशिया में पाया जाता है। अभी तक इसकी 160 से भी ज्यादा प्रजातियां खोजी जा चुकी हैं।

हाल ही में अमेरिका तथा जर्मनी के वैज्ञानिकों ने मैडागास्कर द्वीप के उत्तरी हिस्से में गिरगिट की चार और ऐसी प्रजातियों की खोज की है जो आकार में बहुत ही छोटी हैं। वैज्ञानिकों के लिए इतने छोटे आकार के जीव को ढूंढ पाना मुश्किल था किन्तु इन जीवों की प्रकृति के आधार पर न सिर्फ इन्हें ढूंढा जा सका बल्कि इनके बारे में बहुत कुछ जाना भी जा सका। खोजकर्ता वैज्ञानिकों का कहना है कि यदि एक बार इसके पाए जाने वाले स्थान का पता चल जाए तो इसे आसानी से पकड़ा भी जा सकता है क्योंकि ये गिरगिट दिन के समय भले ही पेड़ की पत्तों की परतों में छिपे रहते हों किंतु रात होने पर यह सोने के लिए टहनियों पर आ जाते हैं और रात भर एक ही जगह पर रहते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि मैडागास्कर में पाई गई गिरगिट की ये चारों प्रजातियां इतनी छोटी हैं कि सिर्फ देखने भर से इनमें भिन्नता का पता लगा पाना कठिन है। इनमें एक प्रजाति जिसे %ब्रूकेशिया माइक्रा% के नाम से जाना जा रहा है, दुनिया में अब तक प्राप्त गिरगिट की प्रजातियों में सबसे छोटी है। इसमें मिले सबसे छोटे गिरगिट की लंबाई महज 1.3 इंच थी। वैसे आम तौर पर इस प्रजाति के एक पूर्ण विकसित गिरगिट की लंबाई मात्र 2.9 इंच ही है, जबकि इस प्रजाति के नर गिरगिट की लंबाई महज 1.6 इंच तक ही पाई गई। खोजकर्ता वैज्ञानिकों का कहना है कि ब्रुकेशिया माइक्रा इतना छोटा है कि इसे एक माचिस की तीली के सिरे पर बैठाया जा सकता है। दुनिया का यह सबसे छोटा गिरगिट मैडागास्कर में एक निर्जन टापू पर पड़े कंकड़-पत्थरों पर मिला। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह प्रजाति इन टापुओं पर पाए जाने के कारण यहां के वातावरण में अपने को ढालने में छोटी होती चली गई। मैडागास्कर में प्राप्त इस तरह के गिरगिटों का रहवास मात्र एक वर्ग किलोमीटर जगह तक ही सीमित है।

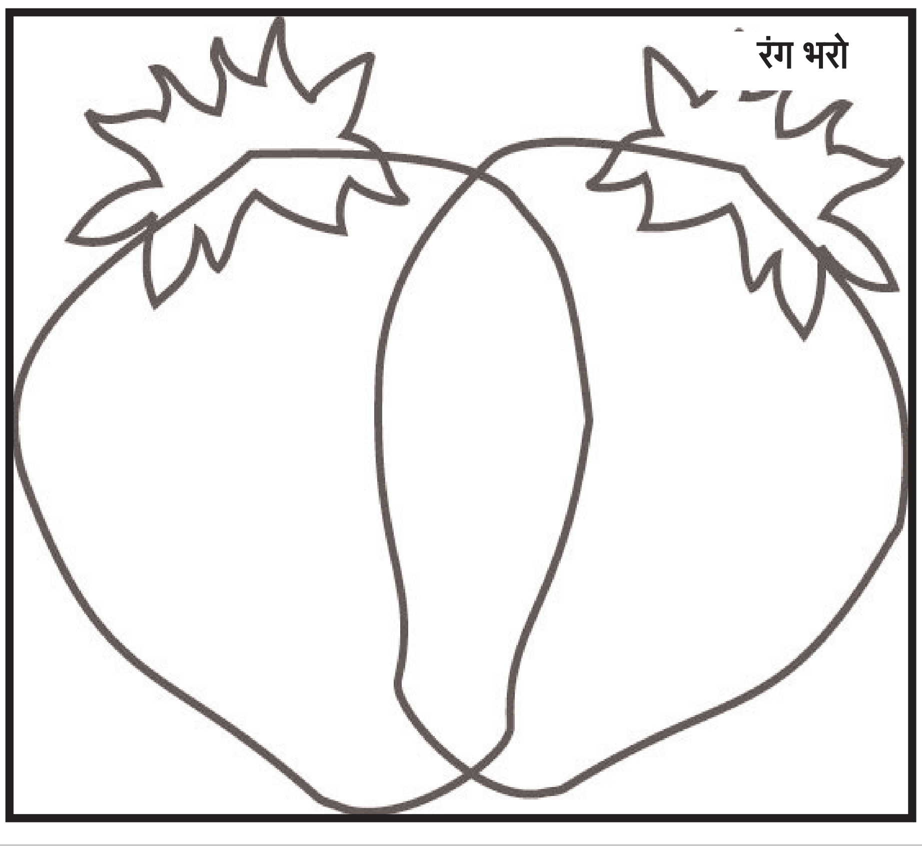


## क्या आप जानते हैं

# गाने बजाने वाले ज्यादा बुद्धिमान

**स्कूलों** में अब वार्षिकोत्सव की धूम रहती है। ऐसे मौकों पर स्टूडेंट्स गायन और वादन की प्रस्तुति से सभी को इम्प्रेस करते हैं। गायन या वादन में रुचि रखने वाले स्टूडेंट्स को अपने इस शौक के कारण साल के बाकी समय घर वालों की डाँट भी सुनने को मिलती होगी या कई जगह इस रुचि को बढ़ावा भी दिया जाता होगा। खैर इन दिनों विज्ञान की दुनिया से जो खबर आई है वह वाद्ययंत्र बजाने वालों के पक्ष में है।

विज्ञान के विशेषज्ञ कहते हैं कि वाद्ययंत्र पर नियमित अभ्यास करने वाले अपने दूसरे साथियों के मुकाबले ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। ऐसे संगीतज्ञों का आईक्यू भी दूसरों के मुकाबले 7 प्वाइंट्स तक ज्यादा होता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि नियमित अभ्यास करने वालों में दिमाग का वह हिस्सा ज्यादा विकसित होता है जिससे संगीत सुना और समझा जाता है। इस हिस्से के विकसित होने के कारण न सिर्फ संगीत बल्कि दूसरी चीजों को समझना भी इन संगीत रसिकों के लिए आसान होता है।

वैज्ञानिक अपनी बात के समर्थन में कहते हैं कि संगीत सीखने से और भी कई फायदे हैं जैसे संगीत में नोट्स और बीट्स पकड़ने वाले स्टूडेंट अलर्ट रहना सीख जाते हैं। एक सुर के बाद अगला सुर क्या होगा इससे उन्हें प्लानिंग करना आ जाता है और संगीत के साथ उनकी भावनात्मक समझ भी बेहतर हो जाती है।

युनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख के मनोवैज्ञानिक लुत्ज जैक का कहना है कि वाद्य यंत्र सीखने से बच्चों को पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखने में मदद मिलती है। वे कहते हैं कि जब बच्चे संगीत के साथ भावों को समझना सीख जाते हैं तो उनके लिए एक से ज्यादा फोरेन लैंग्वेज सीखना आसान हो जाता है, क्योंकि तब वे भाषा की टोन से समझ जाते हैं कि बात का मतलब क्या है।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

## भाजपा अध्यक्ष नड्डा आज से हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे

**नईदिल्ली।** भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा 'विकसित भारत संकल्प यात्रा' में भाग लेने के लिए 15 से 17 दिसंबर तक हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने बृहस्पतिवार को एक बयान में बताया कि नड्डा शुक्रवार को बिलासपुर में अपने गांव विजयपुर पहुंचेंगे जहां वह रात को ठहरेंगे। शनिवार को वह बिलासपुर में पार्टी द्वारा आयोजित एक सम्मान समारोह में भाग लेंगे। वहां से वह सड़क मार्ग से मंडी जिले के सुंदरनगर जाएंगे जहां उनका एक अन्य सम्मान समारोह और एक रोड शो में भाग लेने का कार्यक्रम है। भाजपा अध्यक्ष सुंदरनगर में नव निर्मित भाजपा कार्यालय का उद्घाटन करेंगे और विकसित भारत संकल्प यात्रा के रूप में आयोजित की जा रही 'रथ यात्रा' में भाग लेंगे। बयान के अनुसार, इसके बाद नड्डा कुल्लू के लिए रवाना होंगे और वहां रात्रि विश्राम करेंगे तथा अगले दिन राष्ट्रीय राजधानी लौट जाएंगे।

## शीर्ष अदालत से सत्येंद्र जैन को झटका

**नई दिल्ली।** भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ ने धनशोधन मामले में न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष सूचीबद्ध आम आदमी पार्टी (आप) नेता सत्येंद्र कुमार जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई टालने से गुरुवार को इनकार कर दिया। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि संबंधित न्यायाधीश इस पर निर्णय लेंगे। जैन की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने न्यायमूर्ति चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ से आग्रह किया कि न्यायमूर्ति त्रिवेदी की अगुवाई वाली पीठ द्वारा दिन में उनकी याचिका पर प्रस्तावित सुनवाई को टाल दिया जाए। सिंघवी ने कहा कि न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति त्रिवेदी की पीठ ने इस मामले में पर्याप्त दलीलें सुनी थीं और अब यह मामला उस पीठ के समक्ष सूचीबद्ध है, जिसमें न्यायमूर्ति बोपन्ना शामिल नहीं हैं। इसलिए मामले पर सुनवाई टालना चाहते हैं।

## तेलंगाना में गद्दाम प्रसाद चुने गए विधानसभा स्पीकर

**हैदराबाद।** तेलंगाना में सत्ताधारी कांग्रेस के विधायक गद्दाम प्रसाद कुमार तेलंगाना विधानसभा के स्पीकर चुने गए हैं। गद्दाम प्रसाद कुमार का चुनाव निर्विरोध हुआ। गुरुवार को प्रोटेम स्पीकर अकबरुद्दीन ओवैसी ने गद्दाम प्रसाद कुमार के नाम का एलान किया। ओवैसी ने कहा कि गद्दाम प्रसाद कुमार निर्विरोध सदन के स्पीकर चुने गए हैं। प्रोटेम स्पीकर के एलान के बाद सीएम रेवंत रेड्डी, डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का और बीआरएस विधायक केटी रामाराव गद्दम प्रसाद कुमार को स्पीकर के आसन तक लेकर गए। विधानसभा के सभी सदस्यों ने आसन पर जाकर गद्दाम प्रसाद कुमार को स्पीकर बनने की बधाई दी। इसके बाद सीएम रेवंत रेड्डी ने गद्दम प्रसाद की उम्मीदवारी का समर्थन करने के लिए सभी पार्टियों को धन्यवाद दिया। इस दौरान भाजपा को छोड़कर अन्य सभी पार्टियों बीआरएस, एआईएमआईएम और सीपीआई ने गद्दाम प्रसाद को अपना समर्थन दिया।

## पंजाब में कांग्रेस-आप के गठबंधन की तैयारी

**चंडीगढ़।** आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए पंजाब में भी सियासी दलों की गतिविधियों में अंदरखाने तेजी आने लगी है। हाल ही में पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजों ने जहां विपक्षी दलों को अपनी रणनीति पर फिर से विचार करने पर मजबूर कर दिया है, वहीं सूबे में भाजपा उत्साह से भरी है। राष्ट्रीय स्तर पर बने इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस और आप पंजाब में सीट शेयरिंग की भूमिका तलाश रहे हैं वहीं लंबे अरसे तक एकजुट रहे अकाली दल ने फिर से भाजपा के साथ गठबंधन की संभावनाएं टटोलनी शुरू कर दी हैं। हो सकता है, लोकसभा चुनाव में पंजाब के लोगों को चुनने के लिए दो विकल्प, कांग्रेस-आप और शिअद-भाजपा गठबंधन के रूप मिलें। कांग्रेस और आप के गठजोड़ को लेकर भले ही पंजाब कांग्रेस के नेता खुश नहीं हैं, लेकिन वह इस मामले में पार्टी हाईकमान के दिशानिर्देशों की अनदेखी करने पक्ष में भी नहीं हैं। इसके संकेत पंजाब कांग्रेस प्रधान की तरफ से भी दिए गए हैं।

## 24 विधायकों पर गाज गिरा सकते हैं जगनमोहन रेड्डी

**अमरावती।** आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और वाईएसआरसीपी अध्यक्ष वाईएस जगन मोहन रेड्डी 2024 के चुनाव के लिए बड़े फैसले ले सकते हैं। राज्य में लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा के चुनाव होने हैं। बताया जा रहा है कि 24 वर्तमान विधायकों पर गाज गिर सकती है इनमें 22 एससी और दो एसटी विधायकों शामिल हैं। हालांकि, कहीं यह आंकड़ा 40 का भी बताया जा रहा है। कुछ विधायकों के सीट भी बदले जा सकते हैं। लेकिन अधिकांश को चुनावी प्रक्रिया से बाहर रखा जाएगा, यह साफ होता दिखाई दे रहा है। ऐसा कहा जाता है कि मुख्यमंत्री ने, खासकर तेलंगाना चुनाव के नतीजों का विश्लेषण करने के बाद, कम प्रदर्शन वाले नेताओं को हटाने का मन बना लिया है। पिछले 18 महीनों में हुई समन्वय समिति की बैठकों में, उन्होंने नॉन-परफॉर्मिंग विधायकों और पार्टी नेताओं को अपने तरीके सुधारने या बाहर होने का जोखिम उठाने की चेतावनी दी थी।

# संसद सुरक्षा चूक पर लोकसभा में हंगामा, विपक्ष के 14 सदस्य निलंबित

**नईदिल्ली।** संसद सुरक्षा चूक पर हंगामा जारी है। गुरुवार को शीतकालीन सत्र की शेष अवधि के लिए कांग्रेस के पांच लोकसभा सदस्यों को निलंबित किए जाने के बाद नौ और विपक्षी सांसदों को अनियंत्रित आचरण के लिए सदन से निलंबित कर दिया गया। संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने जानकारी दी। सदन में आसन की अवमानना और अनादर के लिए विपक्ष के 14 सदस्यों को मौजूदा शीतकालीन सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित भी कर दिया गया। पहले कांग्रेस के पांच सदस्यों टी एन प्रतापन, हिबी इडेन, जोतिमणि, रम्या हरिदास और डीन कुरियाकोस को चालू सत्र की शेष अवधि के लिए सदन से निलंबित किया गया।

इसके बाद कांग्रेस के वीके श्रीकंदन, बेनी बेहनन, मोहम्मद जावेद और मणिकम टैगोर, द्रमुक की कनिमोई और एस आर प्रतिबन, माकपा के एस वेकटेशन और पी आर नटराजन तथा भाकपा के के. सुब्बारायन के निलंबन का प्रस्ताव सदन में पारित हुआ। सदन की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद जब दोपहर दो बजे आरंभ हुई तो संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने प्रस्ताव रखा। सभा ने ध्वनिमत से जोशी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। जोशी ने अपने प्रस्ताव में कहा कि आसन की अवमानना करने के लिए इन पांच सदस्यों का नाम आसन की ओर से लिया गया है और इन्हें शेष सत्र के लिए सदन से निलंबित किया जाए। इस दौरान बी महताब आसन पर थे। इसके बाद सदन की कार्यवाही अपराह्न तीन बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। पीठासीन सभापति महताब ने दूसरी बार में नौ विपक्षी सदस्यों के निलंबन के बाद अपराह्न करीब तीन बजकर दो मिनट पर लोकसभा की कार्यवाही शुक्रवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

### सरकार ने कहा- उच्च स्तरीय जांच शुरू

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दिन पहले संसद में बड़े पैमाने पर सुरक्षा उल्लंघन पर चर्चा के लिए गुरुवार सुबह शीर्ष मंत्रियों के साथ बैठक में भाग लिया। इस बीच, सरकार ने संभावित खामियों की जांच के लिए एक पैनल का गठन किया। आपको बता दें कि बुधवार को दो लोगों ने लोकसभा में

घुसपैठ कर दिया था। इसे संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक मानी गई। सरकार ने गुरुवार को कहा कि लोकसभा सुरक्षा उल्लंघन की घटना की उच्च स्तरीय जांच शुरू कर दी गई है और विपक्ष से इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं करने को कहा।

दोपहर 2 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने के तुरंत बाद एक बयान में, संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा, हम सभी सहमत हैं कि बुधवार की दुर्भाग्यपूर्ण घटना सांसदों की सुरक्षा से संबंधित एक गंभीर घटना थी। जोशी ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने घटना के बाद तुरंत सदन के नेताओं के साथ बैठक की और संसद की सुरक्षा को और मजबूत करने के सुझावों को सुना। उन्होंने कहा कि सांसदों द्वारा दिए गए कुछ सुझावों को पहले ही लागू किया जा चुका है और अध्यक्ष ने खुद कहा है कि भविष्य में संसद की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए और उपाय किए जाएंगे।

जोशी ने पिछली घटनाओं का भी जिक्र किया जब संसद में सुरक्षा का ऐसा उल्लंघन हुआ है, उन्होंने कहा कि नारेबाजी, कागज फेंकना और गैलरी से कूदने जैसी घटनाएं पहले भी होती रही हैं। मंत्री ने सदन को बताया कि विधानसभा अध्यक्ष ने उच्च स्तरीय जांच के लिए गृह सचिव को पत्र लिखा है और जांच शुरू हो चुकी है। आज दोनों सदनों के बुलाए जाने के तुरंत बाद, अराजकता फैल गई क्योंकि विपक्षी नेताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और सुरक्षा चूक पर सरकार से स्पष्टीकरण की मांग की। गरमागरम माहौल के बीच, कांग्रेस के पांच सांसदों सहित 14 सांसदों को अनियंत्रित आचरण के लिए लोकसभा से निलंबित कर दिया गया, जबकि तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओ ब्रायन को सभापति जगदीप धनखड़ के साथ मौखिक टकराव के बाद राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया।

सूत्रों के हवाले से बताया कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने संसद सुरक्षा उल्लंघन मामले में पांचवें संदिग्ध को पकड़ लिया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि यह घटना, जो 2001 के संसद हमले की 22वीं बरसी पर हुई थी, इसमें छह व्यक्तियों द्वारा सुनियोजित घुसपैठ शामिल थी। पूछताछ के दौरान यह पता चला कि छह आरोपी चार साल से संपर्क में थे और घटना से कुछ दिन पहले उन्होंने सावधानीपूर्वक उल्लंघन की योजना बनाई थी। सूत्रों ने कहा कि उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से समन्वय किया और घुसपैठ से पहले के दिनों में संसद भवन की टोह ली।

### भाजपा सांसद के खिलाफ कार्रवाई चाहता है विपक्ष

दो घुसपैठियों द्वारा लोकसभा के अंदर हंगामा मचाने के एक दिन बाद, कांग्रेस और भाजपा ने बड़े सुरक्षा उल्लंघन के लिए एक-दूसरे को दोषी ठहराया। कांग्रेस लगातार सांसद प्रताप सिम्हा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मां कर रही है जिनके जरिए घुसपैठ करने वालों का पास बना था। एकजुट विपक्ष संसद में केंद्रीय मंत्री अमित शाह के बयान पर भी अड़ा रहा और उनकी तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अनुपस्थिति पर सवाल उठाया। लोकसभा में सुरक्षा उल्लंघन की घटना को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा के लोकसभा सांसद प्रताप सिम्हा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इसको लेकर फिलहाल एक एक्स पोस्ट लिखा है। उन्होंने लिखा कि इंडिया गठबंधन की पार्टियां दो मांग कर रही हैं। पहला कल संसद में हुई बेहद गंभीर और ख़तरनाक सुरक्षा चूक पर दोनों सदनों में गृह मंत्री विस्तृत बयान दें और उसके बाद इसपर चर्चा हो। दूसरी मांग यह है कि घुसपैठ करने वालों को विजिटर पास दिलवाने वाले भाजपा सांसद प्रताप सिम्हा के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई हो। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार द्वारा इन पूरी तरह से वैध और उचित मांगों को मानने से इंकार करने के कारण आज सुबह लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि मैं पूरी तरह से सरकार को दोषी मानता हूं। पिछली बार हमला हुआ था तो वे अंदर नहीं जा पाए लेकिन इस बार वे लोकसभा पहुंच गए। अगर हम अब भी चुप हैं तो हम हैं अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे। विपक्षी गठबंधन इंडिया के घटक दलों के नेताओं ने संसद की सुरक्षा में चूक के मामले को लेकर बृहस्पतिवार को एक बैठक की और सरकार से आग्रह किया इस मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह विस्तृत बयान दें तथा दोनों सदनों में इस विषय पर चर्चा कराई जाए। विपक्षी दलों की यह भी मांग है कि लोकसभा की दर्शक दीर्घा से सदन में कूदने वाले व्यक्ति को पास दिलाने के लिए अनुशंसा करने वाले भाजपा सांसद प्रताप सिम्हा के खिलाफ कार्रवाई की जाए। लोकसभा में विपक्षी सदस्यों ने संसद सुरक्षा में चूक के मुद्दे पर बृहस्पतिवार को सरकार से जवाब की मांग करते हुए भारी हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही आरंभ होने के करीब 15 मिनट बाद अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। संसद पर आतंकी हमले की बरसी के दिन सुरक्षा में चूक विषय पर चर्चा कराने और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों ने बृहस्पतिवार को संसद में नारेबाजी और भारी हंगामा किया, जिसके चलते उच्च सदन की कार्यवाही भोजनावकाश से पहले दो बार स्थगित हुई।

### सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों पर उठे सवाल

संसद में सुरक्षा चूक का मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर चिंता का कारण बन गया है। सवाल यह भी उठ रहा है कि इस मामले में जो चेहरे सामने आये हैं क्या साजिश उन्होंने ही बुनी या वह सिर्फ मोहरे थे? यदि वह सिर्फ मोहरे थे तो असली साजिशकर्ता कौन है? जिस प्रकार से इस पूरी साजिश को अंजाम दिया गया है उससे यह भी सवाल उठ रहा है कि हमारी खुफिया और सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही थीं? दिल्ली पुलिस ने संसद सुरक्षा चूक की घटना के संबंध में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज कर लिया है। अधिकारियों ने बताया है कि घटना के संबंध में संसद मार्ग पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी (आपराधिक साजिश), 452 (बिना मंजूरी के प्रवेश), 153 (दंगा भड़काने के इरादे से जानबूझकर उकसाना), 186 (लोक सेवक को सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन में बाधा पहुंचाना) और 353 (लोक सेवक को उसके कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए आपराधिक बल का इस्तेमाल करना अथवा हमला) और यूएपीए की धारा 16 तथा 18 के तहत मामला दर्ज किया गया है। जहां तक इस मुद्दे पर हो रही राजनीति की बात है तो आपको बता दें कि विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बयान की मांग पर अड़ा है तो दूसरी ओर रक्षा मंत्री ने सुरक्षा चूक की घटना पर लोकसभा में कहा है कि जो घटना हुई, उसकी सबने निंदा की है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। उन्होंने कहा कि घटना के जांच के आदेश दिए गये हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि हम सभी सांसदों को सावधानी बरतने की आवश्यकता है...इस प्रकार से संसद में अराजक स्थिति पैदा करना उचित नहीं है। वहीं दूसरी ओर, संसद भवन के अंदर और उसके आसपास सुरक्षा के कड़े कदम उठाए गए हैं। पुलिस तथा संसद के सुरक्षा कर्मचारी परिसर में प्रवेश करने वालों की गहन जांच कर रहे हैं। संसद परिसर से कुछ ही मीटर की दूरी पर परिवहन भवन के बाहर तैनात सुरक्षाकर्मी किसी को भी बैरिकेड से आगे जाने की इजाजत तब तक नहीं दे रहे, जब तक कि वह उनके पहचान पत्र की जांच नहीं कर ले रहे। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा को 'मकर द्वार' से संसद के नए भवन में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। संगमा अपनी कार से उतरे और इमारत में प्रवेश करने के लिए 'शार्दुल द्वार' की ओर चले गए। संसद सदस्यों के वाहन चालकों को पास के बिना परिसर में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा। संसद परिसर के प्रवेश द्वार पर मीडिया कर्मियों से उनके परिचय पत्र मांगे जा रहे हैं और उनसे जरूरी सवाल भी किए जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि नए संसद भवन के मकर द्वार को सभी के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है और मीडिया कर्मियों को पुराने संसद भवन के गेट नंबर 12 के पास लॉन में भेज दिया गया।

खेल
प्रमुख समाचार

## डेविड वार्नर ने पर्थ में जड़ा 26वां टेस्ट शतक

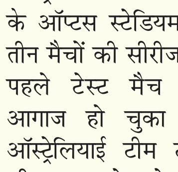

**पर्थ।** पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में तीन मैचों की सीरीज के पहले टेस्ट मैच का आगाज हो चुका है। ऑस्ट्रेलियाई टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही है। इस क्रम में सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर ने 14 दिसंबर को पहले टेस्ट के पहले दिन शतक के साथ अपनी विदाई टेस्ट सीरीज की शानदार शुरुआत की है। डेविड वार्नर का कुल मिलाकर ये 26वां टेस्ट शतक है। वह टेस्ट शतकों की सर्वकालिक सूची में महान सर गैरी सोबर्स के बराबर पहुंच गए हैं, जिन्होंने अपने 93 टेस्ट के करियर में 26 शतक लगाए। अपने गिरते टेस्ट फॉर्म के बीच डेविड वार्नर काफी दबाव में थे। ओपनर को टीम मैनेजमेंट और जॉर्ज बेली के नेतृत्व वाली चयन समिति ने घरेलू सीरीज के पहले टेस्ट के लिए प्लेइंग इलेवन में शामिल करने का समर्थन किया था। हालांकि, वार्नर को प्लेइंग में शामिल करने को लेकर उनकी आलोचना भी हुई, लेकिन वे पूरी ताकत के साथ मैदान पर उतरे और अपने विरोधियों को गलत साबित कर दिया। वार्नर ने अपने 110वें टेस्ट मैच में शतक के साथ पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इंजमाम उल हक को पीछे छोड़ दिया है, जिनके नाम 120 मैचों में 25 शतक थे। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर की नजर अब एलन बॉर्डर के रिकॉर्ड पर है, जिनके नाम 156 मैचों में 27 टेस्ट शतक दर्ज हैं। वार्नर ने एक साल से अधिक समय में अपना पहला टेस्ट शतक पूरा करते हुए 14 चौके और एक छक्का लगाया। वॉर्नर को टेस्ट क्रिकेट में अपने गिरते आंकड़ों के लिए आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। पिछले चार वर्षों में वार्नर ने केवल तीन टेस्ट शतक बनाए हैं, जिसमें मौजूदा पर्थ टेस्ट में शतक भी शामिल है। टेस्ट सीरीज से पहले पूर्व तेज गेंदबाज मिशेल जॉनसन ने वार्नर पर हमला बोला और सवाल उठाया कि अनुभवी सलामी बल्लेबाज को हाल के दिनों में खराब प्रदर्शन के बावजूद विदाई टेस्ट सीरीज में जगह क्यों मिल रही है।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान
प्रमुख समाचार

## सेंसेक्स-निफ्टी नए ऑल टाइम हाई पर पहुंचे

**नईदिल्ली।** आईटी और बैंकिंग शेयरों में लिवाली के दम पर हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन यानी गुरुवार को देसी शेयर बाजार अपने नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए। आज के कारोबार में बीएसई सेंसेक्स 930 अंक मजबूत हुआ। वहीं, निफ्टी में भी 264 अंक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। व्यापक बाजारों में, बीएसई मिडकैप और स्मॉलकैप सूचकांक भी क्रमश: 36,229 और 41,984 के नए ऑलटाइम हाई पर पहुंच गए। इनमें 1 प्रतिशत और 0.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई। बीएसई का 30 शेयरों वाला मानक सूचकांक सेंसेक्स 929.60 अंक यानी 1.34 फीसदी की भारी बढ़त के साथ 70,514.20 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स में आज 70,110.75 और 70,602.89 के रेंज में कारोबार हुआ। वहीं, दूसरी तरफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में भी 264.40 अंक यानी 1.26 फीसदी की बढ़त दर्ज की गई। निफ्टी दिन के अंत में 21,190.75 अंक पर बंद हुआ।

## थोक मुद्रास्फीति नवंबर में आठ महीने के उच्चतम स्तर पर

**नई दिल्ली।** वाणिज्य मंत्रालय की ओर से 14 दिसंबर को जारी आंकड़ों के अनुसार, भारत की थोक मुद्रास्फीति मार्च 2023 के बाद पहली बार ऋणात्मक स्थिति से बाहर निकल गई और नवंबर में बढ़कर 0.26 प्रतिशत हो गई। थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) मुद्रास्फीति अक्टूबर 2023 में -0.52 प्रतिशत और नवंबर 2022 में 6.12 प्रतिशत पर थी। थोक मुद्रास्फीति की दर नवंबर महीने में 0.26 प्रतिशत रही जो आठ महीने में सबसे अधिक है। थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) के आंकड़े सांख्यिकी मंत्रालय के उस बयान के दो दिन बाद आए हैं जिसमें उसने कहा था कि खुदरा मुद्रास्फीति नवंबर में तीन महीने के निचले स्तर 5.55 प्रतिशत पर आ गई है। यह जुलाई के 15 महीने के उच्च स्तर 7.44 प्रतिशत से अब भी 189 आधार अंक कम है। इसी अवधि में थोक मुद्रास्फीति में 149 आधार अंकों की बढ़ोतरी हुई है।

## सीएनजी के बढ़े दाम, दिल्ली में अब 76.59 रुपये प्रति किलो

**नईदिल्ली।** 2023 के खत्म होने से पहले आम आदमी को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी की है। गुरुवार को सबुह-सुबह कंप्रेस्ड नैचुरल गैस यानि सीएनजी के नए दाम जारी किए गए है। बता दें यह तीन हफ्तों में दूसरी बार है जब सीएनजीसी की कीमत में इजाफा किया गया है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के मुताबिक, दिल्ली-एनसीआर में सीएनजी की कीमत में 1 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में सीएनजी के रेट 76.59 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गए हैं। वहीं, नोएडा में सीएनजी 82.20 रुपये प्रति किलो के दाम पर मिलेगी और ग्रेटर नोएडा में इसकी कीमत 81.20 रुपये प्रति किलो हो गई है। नई कीमतें आज से लागू हो गई हैं। 23 नवंबर को दिल्ली-एनसीआर में सीएनजी की कीमत में 1 रुपये प्रति किलोग्राम का इजाफा किया गया था।

## इस साल बिकेंगे कुल 4.5 लाख करोड रुपये के मकान

**नईदिल्ली।** इस साल देश में मकानों की बिक्री ने खूब जोर पकडा। मूल्य के लिहाज से देश के 7 प्रमुख शहरों में 9 महीने में मकानों की बिक्री ने पिछले साल की कुल बिक्री को पीछे छोड़ दिया। इस साल के 9 महीनों में पिछली समान अवधि से बिक्री में 44 फीसदी इजाफा हुआ है। रियल एस्टेट सलाहकार फर्म एनारॉक समूह के मुताबिक साल के आखिर तक इन शहरों में 4.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के मकान बिकने की संभावना है। एनारॉक की रिपोर्ट के मुताबिक देश के 7 शहरों में इस साल के पहले 9 माह में करीब 3.49 लाख करोड़ रुपये मूल्य के मकान बिक चुके हैं, जबकि पिछले पूरे साल में करीब 3.27 लाख करोड़ रुपये मूल्य के मकान बिके थे। जाहिर है इस साल 9 महीने में पिछले पूरे साल की तुलना में मूल्य के लिहाज से मकानों में बिक्री 7 फीसदी ज्यादा रही।

# कर्ज में डूबा है राजस्थान, नए मुख्यमंत्री के सामने चुनौतियों का बड़ा पहाड़

**विनोद पाठक**

राजस्थान में भाजपा की सत्ता में वापसी हो गई है। शुक्रवार को नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शपथ ग्रहण कर लेंगे। कांग्रेस सरकार की नाकामियों को गिनाकर भाजपा सत्ता में लौटी है। चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बड़ी गारंटियां मरुधरा की जनता को दीं। अब राजस्थान में भी डबल इंजन की सरकार है, लेकिन प्रदेश के नए मुखिया के सामने चुनौतियों का बड़ा पहाड़ भी खड़ा है। कमजोर वित्तीय प्रबंधन से जूझ रहे राजस्थान में गारंटियां कैसे पूरी होंगी? पिछली सरकार की लोक-लुभावन योजनाओं का क्या होगा? यह एक बड़ा सवाल है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रचार के दौरान राजस्थान में महंगे पेट्रोल-डीजल का मुद्दा उठाया था। उन्होंने कीमतें कम करने का वादा किया था। भाजपा शासित अन्य प्रदेशों से राजस्थान में 10-11 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल-डीजल महंगा है। कड़ी आलोचनाओं के बाद भी अशोक गहलोत सरकार ने पेट्रोल-डीजल की कीमतें नहीं घटाई थीं। दरअसल, राजस्थान सरकार को पेट्रोल-डीजल पर वैट से भारी कमाई हो रही है। वर्ष 2021-22 और 2022-23 में राज्य सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर वैट से 35,975 करोड़ रुपए का टैक्स जुटाया, जो देश के 18 राज्यों द्वारा वसूले गए 32,000 करोड़ के टैक्स से ज्यादा है। नई सरकार को पेट्रोल-डीजल की कीमतें अन्य भाजपा शासित प्रदेशों के बराबर करनी होगी। अभी हो रही कमाई की भरपाई कहां से होगी, यह नई सरकार के लिए एक चुनौती रहेगी।

चुनाव से कुछ महीने पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में मुफ्त बिजली योजना शुरू की। मुफ्त बिजली

योजना सरकार को भारी पड़ रही है। बिजली कंपनियां कंगाली के मुहाने पर पहुंच चुकी हैं। घाटा 1.20 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो चुका है। फिलहाल घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट और किसानों को 2000 यूनिट प्रतिमाह बिजली मुफ्त दी जा रही है। मुफ्त बिजली योजना से अभी सरकार के खजाने को 7000 करोड़ रुपए वार्षिक का बोझ सहन करना पड़ रहा है। चूंकि, नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पिछली सरकार की जनहित योजनाओं को जारी रखने का वादा किया है तो इस घाटे को पूरा करना उनके लिए बड़ी चुनौती रहने वाली है। अशोक गहलोत अपनी चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को सबसे ज्यादा प्रचारित करते आ रहे थे। उन्होंने पिछले बजट में बीमा राशि को 25 लाख रुपए कर दिया था। उनका चुनावी वादा था कि पुनः सरकार आने पर 50 लाख का बीमा दिया जाएगा।

भाजपा शासित राज्यों में पांच लाख रुपए का आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा मिलता है। यह भी सभी के लिए नहीं है, जबकि राजस्थान में सभी को बीमा का लाभ दिया जा रहा है। चिरंजीवी योजना पर निर्णय लेना नई सरकार के लिए आसान नहीं होगा। अशोक गहलोत ने वरिष्ठ नागरिकों की वृद्धावस्था पेंशन बढ़ा दी थी और हर साल 15 फीसदी बढ़ोतरी का प्रावधान किया। इससे राज्य पर 12,000 करोड़ रुपए सालाना का बोझ पड़ा। इस योजना में अभी केंद्र सरकार का योगदान मात्र 367 करोड़ रुपए का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्जवला गैस धारकों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने का वादा किया है। राजस्थान में 76 लाख परिवार उज्जवला के अंतर्गत आते हैं। ऐसे में नई सरकार पर 750 करोड़ रुपए से ज्यादा का बोझ पड़ने वाला है। अभी योजनाओं को लागू करने के लिए राजस्थान सरकार भारी कर्ज ले रही है। सरकार ने इसी साल अप्रैल से अगस्त की तिमाही में 12,288 करोड़ कर्ज लिया और अक्टूबर से दिसंबर की तिमाही में फिर 14,000 करोड़ का कर्ज लेने की ओर सरकार बढ़ गई।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022-23 में राजस्थान का कर्ज बढ़कर 5 लाख 37 हजार 013 करोड़ हो चुका है। पंजाब के बाद राजस्थान देश में सबसे ज्यादा कर्ज में डूबा राज्य है। वित्तीय प्रबंधन के अलावा नई सरकार के आगे कानून व्यवस्था बड़ी चुनौती रहने वाली है, क्योंकि यही एक ऐसा मुद्दा है, जिसे भाजपा ने सबसे ज्यादा उछाला था। दूसरा प्रतियोगी परीक्षाओं को करने के लिए भी नई सरकार को ठोस योजना बनानी पड़ेगी।

# सत्ता तो सत्ता, संगठन में भी भ्रष्टाचार

## पूर्व विधायकों के निष्कासन पर बीजेपी का कांग्रेस पर तंज

**रायपुर.** छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा महामंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा पर बिकने और सह प्रभारी चंदन यादव पर रकम लेने के आरोप लगाने वाले दो पूर्व विधायकों के निष्कासन पर तंज कसा है. उन्होंने कहा, इससे आरोप धुल नहीं जाएंगे. कांग्रेस सत्ता में थी तो सिर्फ भ्रष्टाचार ही किया. कांग्रेस ने संगठन में भी भ्रष्टाचार किया, यह भेद कांग्रेस के नेता ही उजागर कर रहे हैं.

भाजपा प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप ने कहा कि, कांग्रेस ने बृहस्पत सिंह और विनय जायसवाल को 6 साल के लिए निष्कासित किया है. बृहस्पत सिंह ने प्रदेश कांग्रेस प्रभारी को बिका हुआ बताया था और विनय जायसवाल ने सह प्रभारी चंदन यादव को 7 लाख देने की बात कही थी. कांग्रेस में कितनी अंतर्कलह है, आपस में कितनी फूट है, कांग्रेस संगठन के अंदर क्या चल है, यह सब अब खुलकर सामने आ रहा है. 7 लाख रुपए चंदन यादव को दिया गया या नहीं दिया गया, कांग्रेस के पास इसका क्या जवाब है? क्या केवल जायसवाल को निष्कासित कर देने से यह सवाल खत्म हो जाएगा?

कांग्रेस सत्ता में रहने पर भ्रष्टाचार करती है संगठन में भी भ्रष्टाचार नहीं चलता, इसका क्या प्रमाण है? कांग्रेस सरकार चलाए या संगठन चलाए, हर चीज का रेट फिक्स है. भ्रष्टाचार ही कांग्रेस को खत्म कर रहा है. आपस में यह लड़ रहे हैं. निष्कासित हो रहे हैं. कांग्रेस की यह दुर्गति कितनी ज्यादा थी, यह तो सामने आ ही गया. प्रदेश में सत्ता के दौरान इन्होंने क्या-क्या किया, यह भी जल्द ही सामने आएगा.

प्रदेश भाजपा महामंत्री केदार कश्यप ने आगे कहा कि, हम चुनाव के पहले कांग्रेस की क्रूर और भ्रष्ट सरकार के एक-एक मामले की जांच कराने का जनता से वादा करके सत्ता में आए हैं. भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हमें जनादेश मिला है. जल्द ही सारे भ्रष्टाचारियों की असलियत सामने आ जाएगी. कांग्रेस संगठन के भीतर जो भ्रष्टाचार हुआ है, उस पर कांग्रेस में तनिक भी नैतिकता हो तो अपने प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारी के खिलाफ इन पूर्व विधायकों के आरोप की जांच कराए.

# मोदी की गारंटी सरकार बनने के तुरंत बाद लागू करने का वादा था, अब 5 साल की बात कर रहे: कांग्रेस

**रायपुर।** भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव सरकार की पहली ही केबिनेट की बैठक के निर्णयों से छत्तीसगढ़ की जनता को निराशा हुई। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने पत्रकार वार्ता में कहा कि राज्य में धान खरीदी शुरू है, भाजपा ने वायदा किया था प्रति एकड़ 21 क्विंटल 3100 रू. के भाव में धान की खरीदी करेंगे, साथ ही भाजपा ने वायदा किया था धान खरीदी केन्द्रों में, गांव में ही एकमुश्त नगद भुगतान किया जायेगा लेकिन केबिनेट की बैठक में इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया। यह ऐसा विषय है

जिसमें तुरंत निर्णय लेने की आवश्यकता है। जब धान खरीदी केंद्रों में 21 क्विंटल के आधार पर निर्णय नहीं पहुंचेगा। 3100 के मूल्य तथा नगद भुगतान की व्यवस्था नहीं होगी तो किसानों के इस वायदे का क्या होगा?

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा के उप

### केबिनेट के निर्णय पर प्रतिक्रिया

मुख्यमंत्री विजय शर्मा सहित भाजपा नेताओं ने किसानों का 2 लाख तक कर्जामाफ का वायदा भी किया था। इस संबंध में विजय शर्मा का प्रचार का अनेक वीडियों सोशल मीडिया में भी वायरल है, जिसमें वे 2 लाख तक कर्ज माफी करने का वायदा कर रहे है। केबिनेट में उसके बारे में भी कोई फैसला नहीं हुआ, किसानों से लिकिंग में कर्जा वसूली शुरू है। कर्ज माफी पर तुरंत आदेश की जरूरत है ताकि किसानों से वसूली बंद हो।

# जो किसान धान बेच चुके हैं उन्हें भी 3100 रुपये राशि दी जाएगी

## लॉ एंड ऑर्डर पर धरातल पर काम होगा: उपमुख्यमंत्री

**रायपुर।** कर्ज माफी पर नव निर्वाचित उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बयान दिया है. उन्होंने कहा कि कर्ज माफी तब की जाती है जब किसानों की व्यथा स्थिति ठीक ना हो. 5 साल तक कांग्रेस सरकार में रही. जिन्होंने केवल लालच देने के लिए कर्ज माफी की घोषणा की थी.

हमारी सरकार 3100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी करेगी. जो किसान धान बेच चुके हैं उन्हें 31 सौ रुपये राशि दी जाएगी.

नक्सलियों को लेकर बैठक में होगी चर्चा- डिप्टी सीएम

हसौद रवाना होने से पहले शर्मा ने कहा कि कमलेश साहू शहीद हुए हैं, उनके परिवार के दुख में शामिल होने जा रहा हूं. हमारी सरकार शहीद परिवार के साथ है. जिन्होंने ऐसा किया उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा. उनकी शहादत कभी भुलाई नहीं जाएगी. आज कैबिनेट बैठक पर भी नक्सलियों को लेकर चर्चा करेंगे.

शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व और मार्गदर्शन में वह सभी बातें आएंगी जो हमने चुनाव के समय कही हैं. लॉ एंड ऑर्डर के लिए विशेष रूप से यह सरकार धरातल पर मिलेगी. पसीना बहाते मिलेगी, परिश्रम करते मिलेगी, सेवा करते मिलेगी. विगत सरकार की तरह हर चौक चौराहे पर पैसा खोजने का जो काम हुआ था उससे जनता को निजात मिलेगी.

# शपथ समारोह में राजगीत नहीं बजने का मुद्दा गरमाया

**रायपुर।** 13 दिसंबर को आयोजित मुख्यमंत्री के शपथ समारोह में राजगीत नहीं बजाए जाने का मुद्दा गरमा गया है. कांग्रेस इसे छत्तीसगढ़ महतारी के साथ 3 करोड़ छत्तीसगढ़ियों का अपमान बताया है. कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा, राजगीत छत्तीसगढ़ी अस्मिता का प्रतीक है.

यह छत्तीसगढ़ महतारी की वंदना गीत है. राज्य सरकार की ओर से हर सरकारी आयोजन में राजगीत धुन बजाना अनिवार्य किया गया है. ऐसे में मुख्यमंत्री शपथ समारोह में राजगीत का नहीं बजना बहुत ही दु:खद है.

यह छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान है. 3 करोड़ छत्तीसगढ़ियों की भावना से खिलवाड़ है. इस गलती के लिए जो भी जिम्मेदार है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए.

वहीं कांग्रेस के इस सवाल पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का भी जवाब आ गया है. साय ने कहा कि, राजगीत का पूरा सम्मान है. छत्तीसगढ़ महतारी हम सबकी महतारी है. हम सब आदर करते हैं. राजगीत क्यों नहीं बज पाया मुझे नहीं पता, क्योंकि शपथ समारोह का कार्यक्रम राजभवन तय करता है.

अब सवाल यही उठ रहा है कि, राजभवन की ओर से क्या ये भूल हुई है ? अगर ये भूल हुई है तो क्या अधिकारियों पर कोई जिम्मेदारी तय होगी ? क्योंकि सोशल मीडिया में यह मुद्दा छाया हुआ और लोग यही जानना चाह रहे हैं आखिर राजगीत क्यों नहीं बज पाया ?

# कांग्रेस के सर्वे एजेंसी के खिलाफ एफआईआर जिन विधायकों की सर्वे के बाद कटी थी टिकट वो उठाने जा रहे है बड़ा कदम

**रायपुर.** कांग्रेस के 15 पूर्व विधायकों ने आज पार्टी से अलग बैठक की और हार की वजहों पर चर्चा की। ये सभी वही पूर्व विधायक है जो लगातार पार्टी के बड़े नेताओं के खिलाफ हमलावर है और हार का ठीकरा उनपर फोड़ रहे है। इस बैठक में डॉ. विनय जायसवाल के अलावा पूर्व रूरू बृहस्पत सिंह, शिशुपाल सोरी, चंद्रदेव राय, लक्ष्मी ध्रुव, भुनेश्वर बघेल, मोतीलाल देवांगन, गुरुदयाल बंजारे, प्रमोद शर्मा के साथ अन्य पूर्व विधायक शामिल थे। ये सभी वे विधायक हैं जिनका इस चुनाव में कांग्रेस ने टिकट काट दिया था।

वही इस बैठक के बाद कांग्रेस के इन पूर्व विधायकों ने बड़ा फैसला किया है। उन्होंने बताया है कि वह कांग्रेस की उस सर्वे एजेंसी के खिलाफ एफआईआर कराएँगे जिनके सर्वे के आधार पर उनकी टिकट काटी गई थी। हालाँकि इसके लिए वक़्त तय नहीं किया गया है। एफआईआर वही विधायक कराएँगे जिनके टिकटें काट दी गई थी। दरअसल पार्टी ने चुनाव से पहले दावा किया था कि वह सर्वे के आधार पर जीत हासिल करने वाले नेताओं को ही अपना उम्मीदवार बनाएगी। वही इसके बाद पार्टी ने करीब दो दर्जन विधायकों के टिकट काटकर दूसरे नेताओं को अपना प्रत्याशी बनाया था। हालांकि पार्टी को जैसे परिणाम की अपेक्षा थी वैसा कुछ नहीं हुआ। उलटे पिछले चुनाव में रिकॉर्ड 68 सीट जीतने वाली कांग्रेस इस बार 35 सीटों पर आकर सिमट गई।

# सूचना का अधिकार में ई फाइलिंग सुविधा पर हुई राज्य स्तरीय कार्यशाला

**रायपुर।** सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत ई फाइलिंग सुविधा एवं स्व पंजीयन विषय पर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन आज रायपुर स्थित सर्किट हाउस के ऑडिटोरियम में किया गया। राज्य सूचना आयुक्त श्री मनोज त्रिवेदी, धनवेंद्र जायसवाल, आयोग के सचिव जी आर चुरेंद्र और राज्य शासन की नोडल अधिकारी एवं उप सचिव सामान्य प्रशासन श्रीमती मेरी खेस की उपस्थिति में इस कार्यशाला में राज्य के सभी जिलों के कलेक्टर कार्यालय एवं जिला पंचायत कार्यालय के नोडल अधिकारी उपस्थित हुए। इस कार्यशाला में छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के अधिकारियों एवं एन आई सी के अधिकारियों के द्वारा ऑनलाइन पोर्टल में स्व- पंजीयन एवं ई फाइलिंग की सुविधा के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। कार्यशाला में अधिकारियों की शंकाओ का समाधान भी किया गया। एक दिवसीय राज्य स्तरीय

इस कार्यशाला में राज्य सूचना आयुक्त श्री मनोज त्रिवेदी ने कहा कि आम जनता एवं जन सूचना अधिकारियों एवं प्रथम अपील अधिकारियों की सुविधा के लिए ई फाइलिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। जन सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों को वेब पोर्टल में स्व पंजीयन सुनिश्चित करना है। सूचना का अधिकार अधिनियम के कार्यों के क्रियान्वयन में अब डिजिटल कार्य किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के परिपालन में सभी राज्यों में ई फाइलिंग की सुविधा एवं अन्य कार्य किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में पहले से ही ऑनलाइन पोर्टल की सुविधा शुरू कर दी गई। उन्होंने सभी नोडल अधिकारियों से ई-फाइलिंग की सुविधा को अपने जिले के सभी जन सूचना अधिकारियों और अपीलीय अधिकारियों को अवगत कराते हुए पंजीयन की दिशा में तेजी से काम करने के निर्देश दिए हैं। कार्यशाला में राज्य सूचना आयुक्त जायसवाल ने नोडल अधिकारियों से कहा कि वे सुनिश्चित कराएं कि जन सूचना अधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों के कार्यालय में उनकी नाम पट्टिका स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो। आरटीआई एक्ट में लापरवाही ना करें और किसी लिपिक के सहारे ना रखें। इस कार्य में जन सूचना अधिकारी व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदार होता है। उन्होंने प्रथम अपील का निराकरण गंभीरता से करने की समझाइए देते हुए कहा कि प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश का पालन कराने की जिम्मेदारी भी प्रथम अपीलीय अधिकारी की होती है।

छत्तीसगढ़/राजधानी
प्रमुख समाचार

## हमारी सरकार पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर नहीं बल्कि टीम भावना से कार्य करेगी: मुख्यमंत्री साय

**रायपुर।** मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में गुरुवार को महानदी भवन नवा रायपुर में विभिन्न विभागों के सचिव स्तर के अधिकारियों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में मुख्यमंत्री को राज्य में संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गयी । इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि शासन और प्रशासन विकास की गाड़ी के दो पहिए हैं, हम सब मिलकर राज्य को आगे बढ़ाएंगे । मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर नहीं बल्कि टीम भावना से कार्य करेगी । प्रशासनिक अधिकारी हमारे परिवार के सदस्य की तरह हैं । बैठक में उप मुख्यमंत्री श्री अरूण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ के लोग बहुत ही सहज और सरल हैं, हमें मिलकर राज्य के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना है । उप मुख्यमंत्री श्रविजय शर्मा ने कहा कि लोकतांत्रिक परंपरा में नागरिक, प्रशासन और शासन एक दूसरे के पूरक हैं, हम सब मिलकर ही राज्य को विकास की ओर अग्रसर करेंगे । कार्यक्रम में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू एवं सभी विभागों के सचिव उपस्थित रहे ।

## नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में 'बिहान' द्वारा भोजन, पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता में सुधार की दी गई जानकारी

**रायपुर।** छत्तीसगढ़ में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान), यूनिसेफ और पी.सी.आई. की साझेदारी में किए जा रहे कार्यों से ग्रामीण क्षेत्रों में भोजन, पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता के स्तर में सुधार आ रहा है। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की संचालक श्रीमती पद्मिनी भोई साहू ने नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में प्रदेश में इस संबंध में किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने कार्यशाला में मौजूद वर्ल्ड बैंक, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, वेदांता, टाटा ट्रस्ट, जिंदल एवं एसडब्ल्यू फाउंडेशन को छत्तीसगढ़ आकर एफएनएचडब्ल्यू कार्यों को देखने एवं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ साझेदारी कर समुदाय के विकास में भागीदारी के लिए आमंत्रित किया। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) द्वारा प्रदेश की स्वसहायता समूह की महिलाओं की सहभागिता से गर्भवती महिलाओं, दो वर्ष तक के बच्चों व उनकी माताओं, किशोरी बालिकाओं, धात्री माताओं के खाद्य, पोषण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता में सुधार के लिए यूनिसेफ तथा पी.सी.आई. संस्था के साथ फूड, न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड वॉश (एफएनएचडब्ल्यू) रणनीति के तहत व्यवहार परिवर्तन एवं जेंडर इंटीग्रेशन पर कार्य किया जा रहा है। बस्तर जिले में %स्वाभिमान योजना% के नाम से संचालित इन रणनीतियों को 31 जिलों में समर्द्धि बिहान के नाम से विस्तारित किया जा रहा है।

## सड़क हादसे में घायल लोगों की मदद करने वालों को एसपी ने किया सम्मानितं

**बिलासपुर.** भारत में हर साल सड़क हादसे में लगभग डेढ़ लाख लोगों की मृत्यु होती है, जिसमें विशेष अन्य कारण के अलावा घायलों को तत्काल चिकित्सा सुविधा न मिल पाना भी एक होती है. इस स्थिति का संज्ञान लेते हुए उच्चतम न्यायालय ने सड़क दुर्घटना में घायलों को त्वरित चिकित्सा उपलब्ध कराने वाले व्यक्तियों को गुड सेमीरिटर्न अर्थात नेक इंसान की संज्ञा देते हुए इन्हें प्रोत्साहित एवं पुरस्कृत करने कहा है. आज बिलासपुर जिले के 7 गुड सेमीरिटर्नओं को पुलिस अधीक्षक कार्यालय बिलासपुर में पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह के हाथों प्रशस्तिपत्र और मोमेंटो देकर पुरस्कृत किया गया. सम्मानित किए गए गुड सेमीरिटर्न में थाना- सीपत के दीपक पांडे, जिन्होंने होली के दिन दो पहिया वाहन से गिरने पर एक व्यक्ति को स्वयं 108 के माध्यम से अस्पताल दाखिल किया. इसी प्रकार आरती कश्यप ने फरहद चौक के पास ट्रक से एक शिक्षिका के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से घायल महिला को खून से लथपथ हालत में पहले सिम्स और फिर गंभीर स्थिति को देखते हुए अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया, जिससे जान बच सकी.

## महंत को मनाने महापौर एजाज ढेबर पहुंचे दूधाधारी मठ

**रायपुर।** हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में रायपुर दक्षिण से मिली पराजय के बाद महंत रामसुंदर दास द्वारा कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद वरिष्ठ कांग्रेसजनों का दूधाधारी मठ में जमावड़ा शुरू हो गया। उन्हें मनाने के लिये महापौर एजाज ढेबर भी दूधाधारी मठ पहुंचे। महापौर ढेबर ने महंत रामसुंदर दास से बातचीत की और उनसे इस्तीफे पर चर्चा कर वापस लेने का आग्रह किया। महापौर ने कहा कि महंत जी इस्तीफे पर पुन: विचार कर रहे है। कांग्रेस के वरिष्ठ जन भी उन्हे मना रहे हैं और वे मान भी जायेगें। महापौर ने कहा कि हार का इतना बड़ा अंतर आएगा यह सोचा नहीं था उन्होंने,अगर वह हारे हैं तो हम स्वीकारते है की जनता साथ नहीं थी। महापौर ने महंत जी के साथ हुई बातचीत के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि कहा आप संघर्ष करें हम सभी आपके साथ है। इस हार से निस्संदेह उन्हे जो धक्का लगा है उससे उबरने में थोड़ा समय लग सकता है लेकिन वे अपना इस्तीफा वापस लेगें।

## शिकारी खुद हो गया शिकार, जानवरों को मारने के लिए लगाए बिजली के तार में फंसकर हुई मौत

**बलरामपुर।** कई बार ऐसा भी होता है कि शिकार के लिए बिछाए जाल में शिकारी खुद फंसकर अपनी जान गंवा बैठता है. ऐसा ही कुछ वाड्रफनगर निवासी जितेंद्र उर्फ मुन्ना के साथ हुआ, जो जंगली जानवरों के शिकार के लिए लगाए विद्युत तार की चपेट में आकर अपनी जान गंवा बैठा. घटना वाड्रफनगर पुलिस चौकी अन्तर्गत भगवानपुर जंगल की है, जहां जंगली जानवर का शिकार करने के लगाए गए विद्युत तार की चपेट में आने से एक शख्स की मौत की खबर पर चौकी प्रभारी सहित अन्य स्टाफ घटना स्थल पहुंचे. शव का पंचनामा पश्चात शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए वाड्रफ़नगर के सिविल अस्पताल में भेजा गया. मामले में विवेचना अधिकारी एएसआई राधेश्याम विश्वकर्मा ने बताया कि वाड्रफनगर के वार्ड नं. 15 से लगे जंगल में कुछ लोग जंगली जानवर का शिकार के उपदेश से दूर रात जंगल में गए थे. एक जितेन्द्र उर्फ़ मुन्ना को छोडकर सभी वापस लौट गए. जितेंद्र के भाई के पूछने पर साथियों ने बताया कि वह जंगल में कही गुम हो गया है, और ढूंढ़ने पर भी नहीं मिला. इसके बाद गांव वाले जितेन्द्र को ढूंढ़ने के लिए निकले. घटना स्थल पर जितेन्द्र मृत मिला. प्रथम दृष्टया में ही यह प्रतीत हो रहा था कि उसकी मौत करंट लगने से हुई हैं. फिलहाल, वाड्रफनगर पुलिस इस मामले में मर्ग कायम कर मामले में शामिल लोगों का पता लगा रही है. साथ ही मौत की पूरी वजह तलाश रही हैं. पुलिस का कहना हैं जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा.

### 16 दिसंबर से 26 जनवरी तक होगा आयोजन

# विकसित भारत संकल्प यात्रा: कलेक्टर ने ली समीक्षा बैठक

**रायपुर.** जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 16 दिसंबर से विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू होगी. 26 जनवरी 2024 तक चलने वाली इस यात्रा के सफल आयोजन के लिए कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर भुरे ने कलेक्टोरेट परिसर स्थित सभाकक्ष में आज अब तक की गई तैयारियों की समीक्षा की. समीक्षा बैठक में उन्होंने अधिकारियों को केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए. कलेक्टर ने इस संकल्प यात्रा के सफल और बेहतर आयोजन के लिए सभी तैयारियां समयपूर्व पूरी करने के भी निर्देश बैठक में दिए. बैठक में जिला पंचायत के प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी हरि कृष्ण जोशी, नगर निगम के अपर आयुक्त अभिषेक अग्रवाल सहित सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे.

बैठक में कलेक्टर डॉ. भुरे ने बताया कि 'विकसित भारत संकल्प यात्रा' के आयोजन के दौरान आम जनता को केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, किसान क्रेडिट योजना, जल-जीवन मिशन, प्रधानमंत्री जन-धन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के आदि योजनाओं की जानकारी दी जाएगी. इसके साथ ही इन योजनाओं से पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करने का प्रयास किया जाएगा.

बैठक में कलेक्टर ने निर्देशित किया कि संकल्प यात्रा के लिए रूट चार्ट तैयार कर निर्धारित रूट के अनुसार कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए. कार्यक्रमों में जनभागीदारी गतिविधि, ग्राम पंचायत, नगरीय निकाय स्तर पर समिति का निर्माण, स्थानीय हितग्राहियों को आमंत्रण, सांस्कृतिक कार्यक्रम की तैयारी, स्व-सहायता समूह, ग्राम संगठन का मोबलाइजेशन, कृषि गतिविधियों पर सत्र का आयोजन, प्रतियोगिता में विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत करना, योजनाओं के सफल लाभार्थियों की ओर से अनुभव साझा करना और पोर्टल में जानकारी अपलोड करने के निर्देश भी कलेक्टर ने दिए.

कलेक्टर ने कार्यक्रम के आयोजन स्थल पर आम नागरिकों को सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. इसके अलावा उन्होंने कार्यक्रम स्थल में उज्ज्वला योजना के तहत घरेलू गैस सिलेंडर के लिए पंजीयन और आयुष्मान भारत योजना के तहत स्मार्ट कार्ड बनाने तथा सरकार की अन्य योजनाओं से पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित कराने आवेदन भराने की व्यवस्था करने को भी कहा.

## संगीत प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने दिखाया हुनर

**रायपुर।** प्रगति महाविद्यालय में ''जैज़ 2023'' में गुरुवार को रंगारंग कार्यक्रम के सातवें दिन में सांस्कृतिक कायक्रम के अंतर्गत आज ''संगीत प्रतियोगिता'' का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ में प्राचार्य डॉ. सौम्या नैयर ने विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने अपनी कलात्मक प्रतिभा का परिचय देते हुए संगीतमय अभिव्यक्ति प्रस्तुत की। इस अवसर पर निर्णायकगण संगीत विद्या में पारंगत श्री आशिष ठाकुर एवं कु. सिंधु सोना उपस्थित रहे। संगीत प्रतियोगिता का आगाज अनुराग के '' शिव सहस्त्रनाम '' से हुआ, रौशन बाग ने जहॉ वाद्ययंत्र की प्रस्तुति दी, वही अमितेष मण्डावी ने बस्तरिया हल्बी सॉग को नए अंदाज में रैप सॉग के साथ रिमिक्स करके प्रस्तुत किया। लीना एवं ग्रुप ने '' चोला माटी के है राम '' छत्तीसगढ़ लोक गीत की प्रस्तुति कर माटी की खुशबू बिखेर दी। संगीत प्रतियोगिता में जहां एक ओर काजल शुक्ला के गजल '' होश वालों को खबर क्या '' ने जगजीत सिंग की स्मृतियों को जींवत किया, वही के साई राम के कॉलेज सॉग '' पहला नशा पहला खुमार '' ने लोगों को मदहोश कर दिया। प्रतिभावान विद्यार्थियों के बीच कॉलेज के प्राध्यापकों ने भी अपना हुनर दिखाया। कार्यक्रम को सफल बनाने में महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. सौम्या नैयर, एडमिस्ट्रेटर सुश्री ज्योति ठाकुर, वाणिज्य एवं प्रबंधन विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. रामकृष्ण राव, कम्प्यूटर विभाग के विभागाध्यक्ष श्री मन्नु रवानी, शिक्षा विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. के. एन. गजपाल, पत्रकारिता विभाग के विभागाध्यक्ष श्री प्रवीण कुमार यादव एवं समस्त प्राध्यापको की सराहरनीय भूमिका रही

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर ( छ.ग. ) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर ( छ.ग. ) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.